राष्ट्रीय संस्करण



स्वर्णिम दास्तां लिखने को तैयार भारत के होनहार >>10

दैनिक जागरण

वर्ष 5 अंक 43

मूल्य ₹8.00, नई दिल्ली, शुक्रवार, 23 जुलाई, 2021

www.jagran.com

पृष्ठ 14

आज के मैच

TOKYO 2020

- सुबह 5:30 बजे: तीरंदाजी महिला व्यक्तिगत रैंकिंग राउंड (दीपिका कुमारी)
- सुबह 9:30 बजे: तीरंदाजी पुरुष व्यक्तिगत रैंकिंग राउंड (अतानु, प्रवीण जाधव और तरुणदीप राय)
- सुबह 5:00 बजे: निशानेबाजी 10 मीटर एयर राइफल महिला प्री-इवेंट
- सुबह 6:30 बजे: निशानेबाजी 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष प्री-इवेंट अभ्यास
- सुबह 5:00 बजे: नौकायान
- शाम 4:30 बजे: उद्घाटन समारोह

प्रसारण, सोनी नेटवर्क पर

32 वीं बार ओलिंपिक होंगे, लेकिन इस बार दर्शक नदारद रहेंगे

5 नए खेल सर्फिंग, स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबाल इस बार शामिल किए गए हैं

1964 में भी जापान के टोक्यो में ओलिंपिक हो चुके हैं

127 एथलीट के साथ भारत का अभी तक ओलिंपिक में सबसे बड़ा दल भाग ले रहा है

टोक्यो में खेलों के महाकुंभ का शंखनाद आज

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: टोक्यो में शुक्रवार को ओलिंपिक का आगाज होगा। कोरोना महामारी के कारण इन खेलों का आयोजन एक साल विलंब से हो रहा है, जिसमें 206 देशों से 11000 से अधिक एथलीट 33 खेलों की 339 स्पर्धाओं में अपना दमखम लगाएंगे।

जिल बाइडन मौजूद रहेंगी : उद्घाटन समारोह टोक्यो के राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित होगा। इस दौरान कोई दर्शक नहीं होगा लेकिन 900 अधिकारी और पत्रकार मौजूद रहेंगे। इसमें अलग-अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ओलिंपिक परेड और मार्च पास्ट होगा। इस दौरान अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडन (अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की पत्नी) भी मौजूद रहेंगी, जिन्होंने कोरोना के बावजूद टोक्यो जाने का फैसला किया।



टोक्यो के राष्ट्रीय स्टेडियम में होगा उद्घाटन समारोह ● आइओसी

पहली बार दो ध्वज वाहक : दिग्गज मुक्केबाज एमसी मेरी कोम और पुरुष हाकी कप्तान मनप्रीत सिंह भारत के ध्वजवाहक होंगे। यह पहली बार होगा जब सभी देशों के दो ध्वजवाहक होंगे। परेड में भाग लेने वाले देश जापानी वर्णानुक्रम के मुताबिक मार्च के लिए कतार में खड़े होंगे, जिसमें भारत 21वें स्थान पर होगा। परेड में छह अधिकारियों सहित भारत के 26 सदस्य शामिल होंगे, जिसमें टेबल टेनिस से सुतीर्था मुखर्जी, मनिका बत्रा, जी. साथियान और शरत कमल, नौकायान से केसी गणपति, वरुण अशोक, विष्णु सरवन और नेत्रा कुमानन, तलवारबाज भवानी देवी, जिम्नास्ट प्रणति नायक, तैराक साजन प्रकाश, मुक्केबाजी से सिमरनजीत कौर, लवलीना बोरगेहेन, पूजा रानी, अमित पंघाल, मनीष कौशिक, आशीष और सतीश शामिल हैं। शनिवार को कई भारतीय खिलाड़ियों के मैच हैं, इसलिए परेड के दौरान पूरा दल शामिल नहीं होगा। मनप्रीत को छोड़कर पुरुष और महिला हाकी टीमें, निशानेबाजी, भारोत्तोलन, बैडमिंटन, टेनिस और जूडो खिलाड़ी नदारद रहेंगे।

संबंधित खबरें >> पेज 10

खास बात

- इलेक्ट्रानिक कचरे से बने पदकों के पीछे टोक्यो का लोगो है। आगे स्टेडियम के साथ विजय का प्रतीक माने जाने वाली ग्रीक देवी नाइक को दर्शाया गया है।
- जापान सरकार ने कोरोना रोकने को टोक्यो में आपातकाल लगा रखा है, जो पूरे ओलिंपिक खेलों के दौरान जारी रहेगा।
- टोक्यो ओलिंपिक के शुभंकर को मिराइतोवा और सोमाइटी नाम दिया गया है। जापानी शब्द मिराइतोवा में मिराइ का अर्थ भविष्य और तोवा का अर्थ अनंत काल होता है।
- एक साल देर से होने के चलते जापान को तीन बिलियन डालर (करीब दो लाख करोड़) का अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ा। इस तरह कुल मिलाकर जापान ने 15.4 बिलियन डालर (करीब 11 लाख करोड़ रुपये) खर्च किए हैं।
- टोक्यो ओलिंपिक में प्रायोजकों से 3.3 बिलियन डालर (करीब 2457 करोड़ रुपये) की कमाई हुई है, जो अभी तक के सबसे अधिक प्रायोजकों द्वारा कमाई करने वाले खेल बने हैं।

जागरण विशेष

आइआइटी के शोध से बढ़ी कोरोना की दवा की उम्मीद



कानपुर: आइआइटी कानपुर के एक शोध की सफलता ने कोरोना पर जीत पाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। विशेषज्ञ अहम प्रोटीन में सिग्नलिंग कराने में सफल रहे हैं जिससे दवा बनाने का रास्ता खुल सकता है। (पेज-6)

न्यूज गैलरी

राजनीति ▶ पृष्ठ 4

लोस के सवालों के जवाब पर ममता ने बंगाल में बैठाया पहरा

कोलकाता: बंगाल में जिलाधिकारियों पर रोक लगाने के बाद ममता सरकार ने अब सभी विभागों पर भी लगाम लगा दी है कि बिना उच्चाधिकारी की अनुमति के किसी भी सवाल का जवाब सीधे लोकसभा को नहीं भेजा जाएगा। सब कुछ आवंटित समय के भीतर किया जाएगा।

राष्ट्रीय फलक ▶ पृष्ठ 5

सरकार किसान संगठनों से वार्ता को तैयार: तोमर

नई दिल्ली: कृषि सुधार कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों ने गुरुवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर किसान संसद लगाई, वहीं संसद परिसर में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि उन्हें वार्ता में खुले मन से आना चाहिए। सरकार इसके लिए पूरी तरह तैयार है।

राष्ट्रीय फलक ▶ पृष्ठ 7

मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह पर एक और केस

मुंबई: मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह समेत आठ लोगों के विरुद्ध गुरुवार को केस दर्ज किया गया। प्राथमिकी में आइपीसी की 29 धाराएं लगाई गई हैं। परमबीर समेत 32 लोगों के विरुद्ध अप्रैल में भी एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

लंका पर चढ़ाई

तीसरा वनडे

भारत vs श्रीलंका

दोपहर 3:00 बजे से

स्थान कोलंबो

प्रसारण: सोनी नेटवर्क

संसद के घमासान में टूटी मर्यादाएं

हंगामा ▶ रास में टीएमसी के शांतनु सेन ने मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथ से कागज छीनकर फाड़ा

टीएमसी सदस्यों की पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भी हुई झड़प

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- विपक्ष और सत्तापक्ष के बीच बमुश्किल टला टकराव
- एक हफ्ते के लिए निलंबित हो सकते हैं सेन, आज पेश हो सकता है प्रस्ताव
- पेगासस जासूसी कांड और कृषि कानूनों के खिलाफ उग्र है विपक्ष



पेगासस जासूसी मामले को लेकर गुरुवार को राज्यसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। प्रेट्र



संसद की मर्यादा के खिलाफ काम करने का टीएमसी का पुराना इतिहास रहा है। शोर मचाना, कागज फाड़ना उनकी संस्कृति है। सच्चाई यह है कि विपक्ष अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए लगातार संसद की कार्यप्रणाली में अवरोध डालकर देश की विकास यात्रा को रोकना चाहता है। यह लोकतंत्र का अपमान है।
– जेपी नड्डा, भाजपा अध्यक्ष

देश में किसी की गैरकानूनी निगरानी संभव नहीं : वैष्णव



नई दिल्ली: इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पेगासस मामले में कोई सच्चाई नहीं है। लंबे समय से देश में स्थापित कानूनी प्रक्रियाएं यह सुनिश्चित करती हैं कि किसी प्रकार की गैरकानूनी निगरानी संभव नहीं है। (पेज-3)

पेगासस फोन जासूसी विवाद और कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ संसद में चल रहा विपक्ष का हंगामा अब घमासान में तब्दील हो गया है। राज्यसभा में गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सदस्यों ने तो संसदीय परंपरा की सीमा लांघते हुए सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथों से सदन में कागज छीनकर उसे फाड़ दिया और आसन की ओर उछाल दिया। माना जा रहा है कि इस अशोभनीय कृत्य के लिए टीएमसी सदस्य शांतनु सेन को एक हफ्ते के लिए निलंबित किया जा सकता है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री वी. मुरलीधरन निलंबन प्रस्ताव पेश कर सकते हैं।

राज्यसभा में तृणमूल सदस्यों का यह आक्रामक व्यवहार तब सामने आया जब दोपहर दो बजे सदन की बैठक शुरू हुई। कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों के सदस्य कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग करते हुए वेल में आकर हंगामा कर रहे थे और तृणमूल कांग्रेस के सदस्य पेगासस फोन जासूसी कांड पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी में जुटे थे। इस बीच उपसभापति हरिवंश ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव को पेगासस मामले में बयान देने की अनुमति दे दी। वैष्णव ने बयान पढ़ना अभी शुरू ही किया था कि टीएमसी सदस्य शांतनु सेन ने अचानक उनकी सीट के पास जाकर उनके हाथों से कागज छीन लिया और उसे फाड़कर आसन की ओर उछाल दिया। टीएमसी सदस्य के इस आक्रामक रुख को देखकर भाजपा सदस्य भी उनकी ओर बढ़े तो डोला बनर्जी समेत टीएमसी के कुछ दूसरे सदस्य भी सेन के बचाव में आ गए। इस दौरान सदन में तनाव, गर्मागर्मी और टकराव की स्थिति पैदा हो गई। टीएमसी सदस्यों की पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भी झड़प हुई। हरिवंश ने तृणमूल सदस्यों के इस व्यवहार पर नाराजगी जाहिर करते हुए अश्विनी वैष्णव को अपना बयान सदन के पटल पर रखने की अनुमति दे दी और इसके बाद सदन को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया।

सरकार के संसदीय रणनीतिकारों की बैठक में इस मामले को गंभीर मानते हुए संसदीय मर्यादा तोड़ने वाले विपक्षी सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर मंत्रणा हुई। संकेत हैं कि सेन और बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई के लिए कुछ सदस्यों की ओर से सदन में प्रस्ताव भी लाया जा सकता है।

उधर, लोकसभा की कार्यवाही भी लगातार तीसरे दिन जासूसी कांड और कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर नहीं चल पाई। कांग्रेस, राकांपा, शिवसेना और अकाली दल से लेकर द्रमुक सरीखे अधिकांश विपक्षी दलों ने जंतर-मंतर पर चल रही किसान संसद का समर्थन करते हुए वेल में आकर भारी हंगामा किया।

विपक्षी सदस्यों ने सदन के भीतर संग्राम करने से पहले सुबह संसद परिसर में कृषि कानून विरोधियों के समर्थन में जबर्दस्त विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुआई में पार्टी के दोनों सदनों के सदस्य कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग वाले पोस्टर-बैनर लिए गांधी प्रतिमा के सामने इकट्ठे हुए और किसानों के समर्थन में मुखर आवाज उठाई।

(संबंधित खबरे पेज-3 पर)

अमीर व गरीब के लिए अलग नहीं हो सकती न्याय व्यवस्था

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- सुप्रीम कोर्ट ने रद की बसपा विधायक रामबाई सिंह के पति की जमानत
- कहा, राजनीतिक दबाव से मुक्त रहनी चाहिए न्यायपालिका



सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के एक मामले में हत्यारोपित की जमानत रद करते हुए गुरुवार को जांच में पुलिस प्रशासन के ढीले रवैये और प्रभावी व्यक्ति द्वारा न्यायपालिका को दबाव में लेने पर तीखी टिप्पणियां की हैं। कोर्ट ने कहा, भारत में समानांतर दो न्याय व्यवस्था नहीं हो सकती। एक उनके लिए जो साधन संपन्न, राजनीतिक शक्ति रखने वाले और प्रभावी लोग हैं और दूसरे वे छोटे साधनहीन लोग जिनके पास अन्याय से लड़ने और न्याय पाने की क्षमता नहीं है। कोर्ट ने जिला स्तर तक न्यायपालिका को राजनीतिक व अन्य दबाव से मुक्त रखने की बात कही।

न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और ऋषिकेश राय की पीठ ने ये तीखी टिप्पणियां हत्या आरोपित गोविंद सिंह की जमानत रद करते हुए अपने फैसले में की हैं। कोर्ट ने आदेश दिया कि बसपा विधायक रामबाई सिंह के पति गोविंद सिंह को दूसरी जेल में स्थानांतरित किया जाए, ताकि स्वतंत्र व निष्पक्ष अदालती कार्यवाही सुनिश्चित हो। गोविंद पर कांग्रेस नेता की हत्या का आरोप है।

कोर्ट ने गोविंद की जमानत रद किए जाने की अर्जी खारिज करने पर कहा, हाई कोर्ट ने कानून के तय सिद्धांत की अनदेखी की है। मामले में सत्र अदालत के न्यायाधीश (एडीशनल सेशन जज) द्वारा आशंकाएं व्यक्त किए जाने और दवाब डाले जाने की शिकायत को भी शीर्ष अदालत ने गंभीरता से लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से कहा, वह एडीशनल सेशन जज द्वारा प्रकट की गई आशंका की जांच करे और इसे सही पाए जाने पर जरूरी कार्रवाई करे।

क्या है मामला

कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया के पुत्र सोमेश ने मप्र हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर गोविंद सिंह की जमानत और सजा निलंबन का आदेश रद करने की मांग की। हाई कोर्ट ने 23 जुलाई, 2019 को दोनों अर्जियां खारिज कर दी थीं। इसके बाद सोमेश ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। गोविंद को तीन मामलों में सजा हो चुकी है, जिसमें दो में हत्या के जुर्म में उम्रकैद हुई है। लेकिन कोर्ट से सजा निलंबित कर दी। इससे उसे जमानत मिल गई थी। आरोप है कि जेल से बाहर आने पर उसने देवेंद्र चौरसिया की हत्या की थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने गोविंद सिंह को गत 28 मार्च को गिरफ्तार किया था।

नरम पड़े कैप्टन, सिद्धू आज संभालेंगे पार्टी की कमान

इन्द्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़



कैप्टन अमरिंदर सिंह फाइल

- कार्यकारी अध्यक्ष नागरा ने अमरिंद को सौंपा 57 विधायकों के हस्ताक्षर वाला न्योता
- कैप्टन ने विधायकों, सांसदों को चाय पर बुलाया, वहां से सभी जाएंगे समारोह में



नवजोत सिंह सिद्धू फाइल

नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाए जाने से नाराज चल रहे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आखिर नरम पड़ गए हैं। अब वह शुक्रवार को सिद्धू व चार अन्य कार्यकारी अध्यक्षों के कार्यभार संभालने के अवसर पर आयोजित समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने स्वयं ट्वीट कर यह जानकारी दी। इतना ही नहीं, उन्होंने सभी विधायकों, सांसदों और वरिष्ठ नेताओं को शुक्रवार सुबह पंजाब भवन में चाय पर आमंत्रित किया है। इसके बाद वहां से सभी कांग्रेस भवन में आयोजित समारोह में जाएंगे। हालांकि ट्वीट में नवजोत सिद्धू का नाम नहीं लिखा। वहीं, पार्टी के पंजाब प्रभारी हरीश रावत गुरुवार को सरकारी हेलीकाप्टर में चंडीगढ़ पहुंच गए। वह भी समारोह में मौजूद रहेंगे।

दरअसल, कैप्टन अमरिंदर के समारोह में न जाने की अटकलें लगाई जा रही थीं क्योंकि वह दो बार कह चुके थे कि सिद्धू जब तक अपने पुराने ट्वीट को लेकर सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते वह मुलाकात नहीं करेंगे। हालांकि सिद्धू पर इसका कोई असर नहीं दिखा। वह पार्टी के नेताओं से मुलाकात और धार्मिक स्थलों पर जाकर शक्ति प्रदर्शन करते रहे। गुरुवार को घटनाक्रम बदला। कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए कुलजीत नागरा व संगत सिंह गिलजियां दोपहर साढ़े तीन बजे मुख्यमंत्री के पास गए और 57 विधायकों व पंजाब युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बरिंदर सिंह ढिल्लों के हस्ताक्षर वाला न्योता पत्र सौंपा। यह न्योता पत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें 57 विधायकों के हस्ताक्षर हैं। पंजाब में विधानसभा की 117 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 59 विधायकों की आवश्यकता होती है।

सिद्धू के अमृतसर आवास पर बनी हस्ताक्षर वाले न्योते की रणनीति पेज>>4

कोंकण व पश्चिम महाराष्ट्र में भारी बारिश, डूबा चिपलूण शहर



- वाशिष्ठी नदी में उफान, कई क्षेत्रों में घरों की पहली मंजिल तक भरा पानी
- कई कारें एवं हल्के वाहन वाशिष्ठी नदी के बहाव की दिशा में बहते दिखाई दे रहे थे
- मुंबई-गोवा राजमार्ग पर जलभराव, लगी वाहनों की लंबी कतार, मुसाफिर हुए हलकान
- कोंकण रेल मार्ग पर कई ट्रेनें फंसी, छह हजार से ज्यादा यात्री बीच रास्ते में फंसे
- एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और कोस्टगार्ड की टीमें राहत व बचाव के काम में जुटीं

480 मिलीमीटर बारिश हुई महाबलेश्वर में

5000 से ज्यादा लोग चिपलूण शहर के विभिन्न इलाकों में फंसे

‹‹ महाराष्ट्र में भारी बारिश के बाद गुरुवार को कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए। कोंकण के व्यावसायिक केंद्र चिपलूण में राज्य परिवहन की बसों की सिर्फ छतें ही नजर आ रही थी। (विस्तृत खबर पेज-5 पर) प्रेट्र

राहत की बात

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने देशभर के सभी तकनीकी और संबद्ध संस्थानों को दिए निर्देश

एकमुश्त फीस जमा करने का दबाव न बनाएं संस्थान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- छात्रों को तीन से चार किस्तों में फीस जमा करने का विकल्प देने का दिया सुझाव
- शिक्षकों व दूसरे कर्मियों को समय पर वेतन-भत्तों के भुगतान के भी दिए निर्देश



बड़ा कदम फाइल- इंटरनेट मीडिया

कोरोना संकट के बीच छात्रों पर एकमुश्त पूरी फीस जमा करने का दबाव बना रहे इंजीनियरिंग सहित दूसरे तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटीई) ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि जब तक स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं होती, तब तक छात्रों पर एक साथ पूरी फीस जमा करने का दबाव न बनाया जाए। बल्कि इसकी जगह उन्हें तीन से चार किस्तों में फीस जमा करने का विकल्प दिया जाए।

खास बात यह है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने यह निर्देश तब दिए हैं जब इंजीनियरिंग कालेजों सहित दूसरे तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों में नई कक्षाओं में प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में संस्थानों की ओर से छात्रों से एकमुश्त फीस जमा करने की मांग की जा रही है। छात्रों की ओर से इस संबंध में की गई शिकायतों के बाद हरकत में आए एआइसीटीई के चेयरमैन प्रोफेसर अनिल सहस्रबुद्धे ने यह निर्देश जारी किया है।

एआइसीटीई से संबद्ध देशभर के सभी तकनीकी संस्थानों को लिखे पत्र में उन्होंने फीस को तीन से चार किस्तों में जमा करने के विकल्प की जानकारी संस्थान की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के भी निर्देश दिए हैं।

इसके साथ ही उन्होंने संस्थानों की ओर से शिक्षकों और दूसरे कर्मचारियों की छंटनी पर भी सवाल खड़े किए हैं। साथ ही कहा कि जब तक इनके खिलाफ कोई गंभीर अनियमितता का मामला सामने नहीं आता है, तब तक इन्हें नौकरी से न निकाला जाए। इन्हें समय पर वेतन और सभी भत्तों का भुगतान किया जाए।

एआइसीटीई ने इसके साथ ही तकनीकी शिक्षण संस्थानों को यह सुझाव भी दिया है कि जब तक संस्थान बंद हैं, वे संस्थान के वाई-फाई और इंटरनेट का इस्तेमाल दूसरे शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई कर रहे छात्रों को भी करने दें। एआइसीटीई ने छात्रों को इस दौरान भ्रामक खबरों से बचने की भी सलाह दी। साथ ही अधिकृत जानकारी के लिए एआइसीटीई का अधिकृत पोर्टल देखने के लिए कहा है।

भारत पर आरोप मढ़ कर अपने स्तर से और नीचे गिरा पाक

नई दिल्ली : पाकिस्तान में अफगानिस्तान के राजदूत की बेटी के अपहरण को भारत ने हतप्रभ करने वाली घटना करार दिया है। पाकिस्तान के गृहमंत्री द्वारा इस विवाद में नाम घसीटे जाने की भर्त्सना करते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि पाकिस्तान के अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से भी अपहृता के बयान को खारिज करना एक नया निम्न स्तर है। (पेंज-3)

ई-कामर्स प्लेटफार्म पर नहीं बिकेगा संचालक का सामान

नई दिल्ली: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने ई-कामर्स नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। इसके अनुसार ई-कामर्स प्लेटफार्म को संचालित करने वाली कंपनियां उस प्लेटफार्म पर अपना कोई सामान नहीं बेच सकेंगी। इसके साथ ही ई-कामर्स प्लेटफार्म पर शुरुआती कीमत कम दिखाने और भुगतान के वक्त उसमें अन्य शुल्क जोड़कर ज्यादा दाम दिखाने का खेल अब नहीं चलेगा। (पेज-7)

जमानत के मामलों में कानूनी प्रविधानों पर नहीं होनी चाहिए बहस : सुप्रीम कोर्ट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- दिल्ली दंगा मामले में पुलिस की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट की टिप्पणी
- पुलिस ने आरोपितों देवांगना, नताशा और आसिफ की जमानत को दी है चुनौती

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली दंगों के मामले में आरोपित देवांगना कालिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल की जमानत को चुनौती देने वाली दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि जमानत के मामलों में कानूनी प्रविधानों पर बहस नहीं होनी चाहिए। आजकल जमानत के मामलों में निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबी चौड़ी बहस होती हैं, लेकिन ऐसे मामलों में प्रथमदृष्टया सिर्फ इस बात पर विचार होना चाहिए कि मामले में जमानत दी जा सकती है या नहीं। हालांकि शीर्ष कोर्ट ने पक्षकारों की मांग पर मामले की सुनवाई चार सप्ताह के लिए टाल दी।

यह मामला दिल्ली दंगों से जुड़ा है जिसमें पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर तीनों आरोपितों की जमानत रद करने के साथ ही गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) लागू किए जाने के बारे में हाई कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों को भी चुनौती दी है। पिछली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट का आदेश किसी और मामले में नजीर नहीं माना जाएगा, हालांकि कोर्ट ने तीनों आरोपितों की जमानत में उस वक्त दखल नहीं दिया था। ज्ञात हो, दिल्ली हाई कोर्ट ने तीनों आरोपितों को जमानत देते हुए कहा था कि असहमति को दबाने के लिए केस किया गया।

टिप्पणियों पर सुनवाई चाहते हैं या जमानत को भी चुनौती दे रहे हैं: सुप्रीम कोर्ट पेज>>2

49 कोरोना के नए मामले आए हैं गुरुवार को दिल्ली में। 29 मरीज हुए ठीक। एक मरीज की मौत हो गई। कोरोना के अब तक कुल 14 लाख 35 हजार 720 मामले आए हैं। इनमें से 14 लाख 10 हजार 95 मरीज ठीक हो चुके हैं।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 23 जुलाई, 2021

मुख्यमंत्री के वादे को निभाए दिल्ली सरकार : हाई कोर्ट

उठाए सवाल ▶ गरीबों के किराये का भुगतान करने के वादे का मामला

सीएम के आश्वासन पर छह सप्ताह के अंदर फैसला करने को कहा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

किराया देने में असमर्थ गरीबों का किराया भुगतान करने के संबंध में प्रेसवार्ता कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की घोषणा को अमलीजामा नहीं पहनाए जाने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सवाल खड़े किए। न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह की पीठ ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि महामारी के कारण श्रमिकों के बड़े पैमाने पर दिल्ली छोड़कर जाने के दौरान मुख्यमंत्री की तरफ से किए गए गंभीर वादे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उचित शासन के लिए सरकार को मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए आश्वासन पर निर्णय लेने की जरूरत होती है। पीठ ने कहा कि मुख्यमंत्री का आश्वासन लागू करने योग्य है और दिल्ली सरकार छह सप्ताह के अंदर इस पर फैसला करें।

29 मार्च, 2020 को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिए आश्वासन को पूरा नहीं करने के खिलाफ याचिकाकर्ता नजमा द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुनाते हुए पीठ ने कहा कि इसमें उन लोगों के व्यापक हित को ध्यान में रखा जाए, जिन्हें लाभ देने का मुख्यमंत्री का इरादा था। इसके साथ ही कहा कि इसके बाद सरकार इसे लेकर एक स्पष्ट नीति तैयार करे। पीठ ने कहा यह वादा किरायेदारों के घावों पर एक मरहम के रूप में कार्य कर सकता था, जोकि महामारी में बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। पीठ ने कहा कि यह पूरी तरह से अस्पष्ट है कि सरकार ने अपने सीएम के वादे का सम्मान नहीं किया।

कानून से वादा न टूटने की रहती है अपेक्षा : पीठ ने कहा कि यह सामाजिक संदर्भ है कि वादे तोड़े जाने के लिए होते हैं, लेकिन कानून ने ऐसे सिद्धांतों को विकसित किया है जिसके तहत सरकार या उसके अधिकारियों की तरफ से किए गए वादों को तोड़ा न जा सके और कुछ शर्तों के अधीन न्यायिक रूप से इसे लागू किया सके। पीठ यह भी कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था मेंसरकार के प्रमुखों व जिम्मेदार पदों पर रहने वाले लोगों से संकट के समय जिम्मेदार आश्वासन देने की उम्मीद की जाती है।

अदालत ने कहा कि नागरिकों को उम्मीद रहती है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे पदाधिकारी का आश्वासन प्रभावी होगा। यह भी नहीं कहा जा सकता है कि किसी भी किरायेदार या मकान मालिक ने मुख्यमंत्री के आश्वासन पर विश्वास नहीं किया होगा। पीठ ने कहा कि आश्वासन एक राजनीति वादा नहीं था, क्योंकि इसे चुनावी रैली के हिस्से के रूप में नहीं बनाया गया था।

दिल्ली सरकार की दलील को ठुकराया : अदालत ने सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की उस दलील को भी ठुकरा दिया, जिसमें उसने कहा कि सभी सरकारी नीतियां उपराज्यपाल के स्तर पर तय होती हैं और मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया कोई भी बयान कानून में लागू नहीं होगा। पीठ ने कहा कि सिर्फ इसलिए मुख्यमंत्री को सभी जिम्मेदारियों से दूर नहीं किया जा सकता है कि सरकार के कामकाज का संचालन उपराज्यपाल द्वारा किया जा रहा है।

लिवर को भी जख्मी कर रहा कोरोना वायरस

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : कोरोना से ठीक हुए कई लोग लिवर में घाव व पस भरने की समस्या से पीड़ित होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। पिछले दो माह में ऐसे 14 मरीज गंगाराम अस्पताल पहुंचे। उन मरीजों के लिवर में पस भर गया था। 13 मरीज ठीक हो गए, लेकिन एक महिला की हालत ज्यादा गंभीर होने के कारण डाक्टर उसे बचा नहीं पाए।

अस्पताल के गैस्ट्रोलाजी विभाग के मुखिया डा. अनिल अरोड़ा ने कहा कि दूषित भोजन व पानी के कारण एंटअमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रमण होता है। इससे लिवर में फोड़ा होने और उसमें पस भरने की बीमारी होती है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता ठीक होने पर जल्दी इस तरह का संक्रमण नहीं होता। कोरोना शरीर की प्रतिरोधक क्षमता पर असर डाल रहा है। इसके अलावा स्टेरायड दवाओं से भी प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है। इससे ही मरीजों को लिवर की बीमारी हुई। ये सभी मरीज कोरोना से ठीक होने के 22 दिन के अंदर इलाज के लिए पहुंचे थे। उन्हें बुखार व पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द था। तीन को मल के साथ रक्तस्राव की समस्या थी। कोरोना होने पर आठ मरीजों को स्टेरायड दी गई थी। छह के लिवर में दोनों तरफ कई फोड़े हो गए थे, जिनमें पस भरा था। तीन मरीजों की आंत में अल्सर हो गया था। सभी के लिवर से पस को निकाला गया और एंटीबायोटिक दवाओं से इलाज किया गया। 13 मरीज ठीक हो गए, लेकिन एक महिला की पेट में फोड़ा फटने से अधिक रक्तस्राव के कारण मौत हो गई।

इस माह तीन चौथाई कम हुआ टीकाकरण

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

- स्वास्थ्य विभाग के परिवार कल्याण निदेशालय ने जारी किया आदेश
- 31 जुलाई तक सरकारी केंद्रों में नहीं दी जाएगी कोविशील्ड की पहली डोज

कोरोना के टीके की कमी के कारण दिल्ली में एक माह में टीकाकरण करीब तीन चौथाई कम हो गया है। स्थिति यह है कि सप्ताह दर सप्ताह टीकाकरण कम होता जा रहा है। इस वजह से दिल्ली में आधे से ज्यादा टीकाकरण केंद्र भी बंद हो गए हैं। खास तौर पर कोविशील्ड टीके की कमी ज्यादा है। इसके मद्देनजर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के परिवार कल्याण निदेशालय ने गुरुवार को आदेश जारी कर सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर अगले नौ दिन तक कोविशील्ड टीके की पहली डोज देने पर रोक लगा दी है। इस वजह से अभी लोगों को कोविशील्ड की पहली डोज नहीं दी जाएगी।

निदेशालय के आदेश के मुताबिक 31 जुलाई तक सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर कोविशील्ड की सिर्फ दूसरी डोज दी जाएगी। निदेशालय के आदेश में कहा गया है कि एक मई को 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को टीका लगाने का काम शुरू हुआ था। ज्यादातर लोगों को कोविशील्ड टीका लगा है। इस टीके की दूसरी डोज 84 दिन के अंतराल पर देने का प्रविधान है। इसलिए पहली डोज ले चुके लोग दूसरी डोज लेने के योग्य हो गए हैं। इसके अलावा टीके की भी कमी बनी हुई है। इसलिए अभी कोविशील्ड की दूसरी डोज ही लगेगी।

बहरहाल, समस्या यह है कि कोवैक्सीन की पहले ही कमी बनी हुई है। इस वजह से कोवैक्सीन की सिर्फ 20 फीसद डोज ही पहली डोज के रूप में दी जा रही है। ऐसे में जिन लोगों ने अब तक एक भी डोज नहीं ली है, उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं।

इस माह के पहले सप्ताह से ही कम होने लगा था टीकाकरण : 26 जून से दो जुलाई के बीच 10 लाख 90 हजार से अधिक टीकाकरण हुआ था। इसके बाद इस माह के पहले सप्ताह से ही टीकाकरण कम होने लगा था। पिछले छह दिनों में महज दो लाख 44 हजार 553 लोगों को टीका लगा है। दिल्ली में अब तक 75.73 फीसद लोगों को कोविशील्ड व 23.97 फीसद लोगों को कोवैक्सीन टीका लगा है। दिल्ली में 1374 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन गुरुवार को 656 केंद्रों पर ही टीकाकरण हुआ। इसके चलते कई लोगों को टीका केंद्रों से वापस जाना पड़ा। इससे उनमें निराशा हुई। उनका कहना है कि सरकार को जल्द से जल्द अधिक टीके की व्यवस्था करनी चाहिए।

पहली डोज के लिए निजी अस्पतालों पर बढ़ी निर्भरता

निजी अस्पतालों में टीके की पहली डोज देने का काम जारी रहेगा। निजी अस्पतालों में स्लाट भी उपलब्ध है। ऐसे में पहली डोज लेने के लिए निजी अस्पतालों पर निर्भरता बढ़ गई है।

स्टाक में टीके की तीन लाख 11 हजार 50 डोज उपलब्ध

मौजूदा समय में दिल्ली में टीके की कुल तीन लाख 11 हजार 50 डोज उपलब्ध है। इसमें कोवैक्सीन की दो लाख 45 हजार 590 डोज उपलब्ध है। इसमें से 70 हजार डोज एक दिन पहले आई है। कोविशील्ड की महज 65,460 डोज उपलब्ध है।

दिल्ली में सप्ताहवार टीकाकरण के आंकड़े

सप्ताह	टीकाकरण
26 से दो जुलाई	10,90,145
तीन से नौ जुलाई	5,98,730
10 से 16 जुलाई	4,41,506
17 से 23 जुलाई	2,44,553

नोट : अंतिम सप्ताह के आंकड़े 22 जुलाई तक के ही हैं।

दिल्ली में 22 जुलाई को दोपहर तक कुल टीकाकरण के आंकड़े

अब तक कुल टीकाकरण	95,60,969
पहली डोज	72,48,964
दूसरी डोज	23,12,005
कोविशील्ड	72,40,878
कोवैक्सीन	22,92,347
स्पुतनिक वी	27,744

साफ नीयत से किए गए जनहित के कार्यों का गलत अर्थ निकालना ठीक नहीं : एलजी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

- छह पेज के पत्र में बैजल ने सिसोदिया के हर आरोपों का दिया जवाब, सभी बताए निराधार



अनिल बैजल। फाइल/इंटरनेट मीडिया

दिल्ली सरकार और राजनिवास के बीच अधिकारों को लेकर चल रहा टकराव कम होता दिखाई नहीं दे रहा है। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार को छह पेज का पत्र लिखा है। इसमें न सिर्फ सिसोदिया द्वारा लिखे गए पत्र को सार्वजनिक करने पर नाराजगी जताई, बल्कि यह भी कहा कि साफ नीयत से किए गए जनहित के कार्यों का गलत अर्थ निकालना ठीक नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने सिसोदिया द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को भी निराधार बताया।

उपराज्यपाल अनिल बैजल ने गुरुवार को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पत्र लिखा है। इसमें कहा कि उपराज्यपाल कार्यालय देश के संविधान और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सर्वोच्च सम्मान रखता है तथा सत्ता के विभाजन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले कुछ माह में उनके द्वारा जो भी बैठकें बुलाई गई हैं, वे सभी उपराज्यपाल कार्यालय के संवैधानिक अधिकारों व प्रविधान के मुताबिक हैं। उन्होंने कहा है कि कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन सिसोदिया ने जो पत्र उन्हें लिखा था, उसे संवैधानिक अधिकारियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से संबंधित संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए था। इसके लिए उपमुख्यमंत्री को उनके साथ व्यक्तिगत रूप से चर्चा करनी चाहिए थी। उपराज्यपाल ने कहा, उनके द्वारा साफ नीयत से किए जाने वाले जनहित के कार्यों का गलत अर्थ ही नहीं निकाला जा रहा है, बल्कि पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है।

मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी बैठकों थे मौजूद : उपराज्यपाल के मुताबिक उन्होंने कोविड-19 महामारी को लेकर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की तीन बैठकें बुलाई हैं। इसके अलावा टीकाकरण की स्थिति, विभिन्न एजेंसियों द्वारा जमीनी स्तर पर कोविड उपयुक्त व्यवहार के प्रवर्तन, सरकारी और निजी अस्पतालों में आक्सीजन संयंत्रों की स्थापना, आक्सीजनयुक्त और आइसीयू बिस्तरों सहित अस्पतालों के बुनियादी ढांचे में सुधार, चिकित्सा एवं पैरामेडिकल स्टाफ की क्षमता संवर्धन, दिल्ली में सीरो सर्वे कराने, आर्थिक गतिविधियों को खोलने के लिए जमीनी हकीकत के आकलन, माइक्रो कंटेनमेंट जोन की स्थापना आदि मुद्दों पर नौ अन्य बैठकें बुलाई गई थीं। इन सभी बैठकों में मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और मनीष सिसोदिया खुद उपस्थित थे। ऐसे में उपमुख्यमंत्री द्वारा लगाए गए निराधार आरोप दुर्भाग्यपूर्ण हैं।

योजनाओं का ठीक से पालन कराना भी मेरी जिम्मेदारी

उपराज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा नामित और नियुक्त संवैधानिक पदाधिकारी के रूप में यह सुनिश्चित करना भी उनका दायित्व है कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और उनके अंतर्गत बनाई गई योजनाओं का ठीक से पालन हो रहा है या नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जल संकट को लेकर पड़ोसी राज्यों से बात करने को लेकर भी मुख्यमंत्री ने स्वयं उनसे अनुरोध किया था। इसी कड़ी में उन्होंने जल बोर्ड की भी तीन बैठकें लीं। मास्टर प्लान 2041 को लेकर उन्होंने डीडीए की बैठकें भी की हैं।

सिसोदिया ने ये कहा था

सिसोदिया ने उपराज्यपाल को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने बैजल के कार्यों को लोकतंत्र की हत्या और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करार दिया था। सिसोदिया ने उपराज्यपाल द्वारा सरकार के अधिकारियों को उन विषयों पर निर्देश जारी करने के लिए भी आपत्ति जताई थी। सिसोदिया ने कहा था कि चुनी हुई सरकार के कामों में उपराज्यपाल दखल दे रहे हैं।

लखनऊ और शिलांग में प्रवेश परीक्षा केंद्र बनाएगा दिल्ली विश्वविद्यालय

संजीव कुमार मिश्र, नई दिल्ली



दिल्ली विवि की फाइल फोटो। इंटरनेट मीडिया

स्नातकोत्तर के सभी व स्नातक के 13 पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा आयोजित कराता है। डीयू की प्रवेश परीक्षा हर वर्ष 24 केंद्रों पर होती थी। उत्तर प्रदेश से लगातार बढ़ रहे आवेदनों के चलते डीयू ने परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब तक उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही केंद्र बनाया जाता था, लेकिन इस साल बनारस के साथ ही लखनऊ में भी प्रवेश परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। डीयू मेघालय की राजधानी शिलांग में भी एक परीक्षा केंद्र बनाने पर विचार कर रहा है।

छात्रों के लिए राहत : डीयू प्रशासन ने कहा कि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है। बनारस में केंद्र होने की वजह से पूर्वांचल के छात्रों के लिए केंद्र पर पहुंचना फिर भी सहूलियत भरा था, लेकिन पश्चिमी उप्र समेत अन्य इलाकों के छात्रों को काफी दिक्कत होती थी। लखनऊ, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद व आगरा तक से छात्र परीक्षा देने दिल्ली-एनसीआर आते थे। इसमें छात्रों का समय बहुत व्यर्थ जाता था।

अब तक 24 केंद्र : गांधी नगर, अमृतसर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली-एनसीआर, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंफाल, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, रांची, शिमला, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, बनारस।

स्नातक के 12 पाठ्यक्रमों के लिए होगी प्रवेश परीक्षा : गत वर्ष तक स्नातक के नौ पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए डीयू प्रवेश परीक्षा आयोजित कराता था, लेकिन इस साल तीन नए पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। इस तरह पाठ्यक्रमों की संख्या बढ़कर 12 हो जाएगी।

गत वर्ष डीयू में स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आवेदन

राज्य	आवेदन
दिल्ली	142526
उत्तर प्रदेश	66657
हरियाणा	50701
बिहार	21151
राजस्थान	14485
उत्तराखंड	7531
मध्य प्रदेश	7490
झारखंड	5874
केरल	5227
बंगाल	5182

तीन नए पाठ्यक्रम बढ़े

- बैचलर इन फिजियोथेरेपी
- बैचलर इन आकुपेशनल थेरेपी।
- बैचलर आफ आर्थोटिक्स

आप कार्यकर्ताओं ने मेरे घर पर किया हमला : आदेश गुप्ता

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

- भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पुत्र ने पटेल नगर थाने में दी शिकायत, कार्रवाई की मांग
- आरोप गलत, पेट्रोल-डीजल के बढ़ रहे दाम के विरोध में था प्रदर्शन : आप विधायक

आम आदमी पार्टी (आप) के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार शाम प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता के पटेल नगर स्थित निवास के बाहर पहुंचकर नारेबाजी की। गुप्ता ने आप कार्यकर्ताओं पर उनकी अनुपस्थिति में घर पर हमला करने और सुरक्षाकर्मी के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। उनके पुत्र रजत गुप्ता ने पटेल नगर थाने में इसकी शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं, पटेल नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक राजकुमार आनंद ने हमले के आरोप को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि आप कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल-डीजल के बढ़ रहे दाम के विरोध में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के घर के बाहर सिर्फ प्रदर्शन किया।

भाजपा का कहना है कि अरविंद केजरीवाल सरकार के घोटाले उजागर होने से आप नेता बौखला गए हैं। बौखलाहट में प्रदेश अध्यक्ष के घर पर हमला किया गया है। इससे पूर्व भी 11 जुलाई को हमला किया गया था। भाजपा इससे डरने वाली नहीं है। प्रदेश भाजपा महामंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि राजनीति में विरोधियों के साथ मारपीट करने की नई परंपरा मुख्यमंत्री केजरीवाल की देन है। उन्होंने कहा कि घटना की शिकायत पुलिस से की गई है। हमला करने वालों में आप के झारखंड व गोवा के सहप्रभारी अंकुश नारंग और उनके समर्थक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आप सरकार के घोटाले से दिल्ली की जनता त्रस्त है। अपनी कमियों पर पर्दा डालने और अपने मंत्रियों, विधायकों और नेताओं के बचाव में विपक्षी दलों के नेताओं पर हमला किया जा रहा है। भाजपा की ओर से इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।

वहीं, राजकुमार आनंद ने कहा कि पेट्रोल व डीजल के दाम बढ़ने से लोगों में केंद्र सरकार व भाजपा के खिलाफ भारी रोष है। उनके क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने रोष जताने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के घर के सामने प्रदर्शन किया। भाजपा हमला करने का बेबुनियाद आरोप लगा रही है। नारंग का कहना है कि आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन शांतिपूर्ण था। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष यदि हमला करने का आरोप लगा रहे हैं तो वह इसे साबित करके दिखाएं।

कोर्ट की टिप्पणियों पर सुनवाई चाहते हैं या जमानत को भी चुनौती दे रहे हैं

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

गुरुवार को जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामला सुनवाई के लिए लगा। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि वह इस मामले में सिर्फ हाई कोर्ट की कानून के बारे में की गई टिप्पणियों के खिलाफ सुनवाई चाहते हैं या तीनों आरोपितों की जमानत को भी चुनौती दे रहे हैं। मेहता ने कहा कि वह दोनों मुद्दों पर सुनवाई चाहते हैं। हालांकि कोर्ट जमानत रद करने की मांग के प्रति कुछ उदासीन दिखा, लेकिन फिर भी कहा ठीक है, सुनेंगे। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि आजकल जमानत के मामलों में लंबी-लंबी बहसें होती हैं, जबकि समय सीमित होता है। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में कुछ घंटे ही सुनवाई के लिए देंगे।

चार्जशीट को पेन ड्राइव में दाखिल करने की मांगी इजाजत : शुरुआत में आरोपितों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कुछ समय दिए जाने का अनुरोध करते हुए कहा कि इन तीन छात्रों के खिलाफ 20,000 पेज की चार्जशीट दाखिल हुई है। उन्होंने कोर्ट से उसे पेन ड्राइव में दाखिल करने की इजाजत मांगी। कोर्ट ने उनकी मांग स्वीकार करते हुए सुनवाई चार सप्ताह के लिए टाल दी।

आइजीआइ के टर्मिनल-2 से विमानों का संचालन शुरू

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : कोरोना संकट के बीच इस वर्ष 18 मई को बंद किए गए इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आइजीआइ) एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 से विमानों का संचालन शुरू कर दिया गया। गुरुवार तड़के तीन बजे इंडिगो एयरलाइंस की दिल्ली-कोलकाता विमान ने उड़ान भरी और अपने तय समय पर कोलकाता पहुंच गई। ज्ञात हो कि इससे पहले सिर्फ टर्मिनल-3 से ही विमानों का संचालन किया जा रहा था। जून के अंत में इस टर्मिनल पर आने-जाने वाले यात्रियों की संख्या 60 हजार से ज्यादा होने लगी थी। इसके बाद डायल ने टर्मिनल-2 से विमानों के संचालन करने की तैयारी शुरू कर दी थी।

तिरंगे के कपड़े की गुणवत्ता सुधारेगा आइआइटी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

22 जुलाई, 1947 को तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया

26 जनवरी, 2002 को आम नागरिकों को तिरंगा फहराने का अधिकार मिला



आइआइटी, दिल्ली और फ्लैग फाउंडेशन आफ इंडिया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के दौरान (बाएं से) प्रो. विपिन कुमार, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) अशिम कोहली, आइआइटी निदेशक प्रो वी रामगोपाल राव। सौजन्य : आइआइटी दिल्ली

22 जुलाई, 1947 को तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया था। संविधान सभा में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इसकी घोषणा की थी। 26 जनवरी, 2002 को भारत के प्रत्येक नागरिक को तिरंगा झंडा फहराने की इजाजत मिली थी। भारत को एकता के सूत्र में पिरोते तिरंगे झंडे के कपड़े की गुणवत्ता सुधारने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी, दिल्ली) ने फ्लैग फाउंडेशन आफ इंडिया के साथ करार किया है। इसके तहत संयुक्त रूप से शोध किया जाएगा।

मौसम के प्रभावों से बचाना मकसद : आइआइटी विज्ञानियों ने कहा कि देश में जलवायु और भौगोलिक भिन्नताएं हैं। फैब्रिक डिजाइन करना बड़ी चुनौती है। ऐसे में शोध के जरिये झंडे के लिए कपड़े को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा, ताकि वह कठिन जलवायु परिस्थितियों में भी लंबे समय तक टिक सके और बहुत भारी भी नहीं हो।

> यह समय की मांग है कि उचित मानकीकरण और विषय की जानकारी या फैब्रिक प्रौद्योगिकी की कुशलता और ध्वज में इस्तेमाल होने वाले कपड़े की गुणवत्ता में सुधार के लिए उत्पादकों की मदद की जाए।
> –प्रो. विपिन कुमार, टेक्सटाइल एंड फाइबर इंजीनियरिंग विभाग, आइआइटी दिल्ली

> अच्छी गुणवत्ता का झंडा प्राप्त करना हमारे लिए हमेशा चुनौती भरा रहा है। उचित प्रौद्योगिकी विकसित करने को लेकर आइआइटीटी दिल्ली के विशेषज्ञों के साथ काम करना गौरवान्वित करने वाला पल है।
> –मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) अशिम कोहली, सीईओ, फ्लैग फाउंडेशन आफ इंडिया

शोध

प्लास्टिक और माइक्रोप्लास्टिक से प्रदूषित हो रहा गंगा जल

पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले दिल्ली के गैर सरकारी संगठन टाक्सिक लिंक के अध्ययन में आया सामने, हरिद्वार, कानपुर और वाराणसी में नदी से लिए गए सभी नमूनों में पाया गया माइक्रोप्लास्टिक

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली



गैर-शोधित सीवेज बड़ी समस्या है।

पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले दिल्ली के गैर सरकारी संगठन टाक्सिक लिंक के नए अध्ययन में सामने आया है कि प्लास्टिक और माइक्रोप्लास्टिक से गंगा का जल तेजी से प्रदूषित हो रहा है। गुरुवार को जारी किए गए 'गंगा नदी के किनारे माइक्रोप्लास्टिक का मात्रात्मक विश्लेषण' नामक इस अध्ययन में सामने आया है कि हरिद्वार, कानपुर और वाराणसी में गंगा जल के सभी नमूनों में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है।

अध्ययन के मुताबिक प्लास्टिक उत्पादों की सर्वाधिक मात्रा वाराणसी में पाई गई है। नदी के किनारे कई शहरों से गैर-शोधित सीवेज, औद्योगिक कचरा और प्लास्टिक से नदी में भारी मात्रा में प्रदूषक तत्व मिल रहे हैं। प्लास्टिक उत्पादों व कचरे को नदी में छोड़ या फेंक दिया जाता है। यह प्लास्टिक धीरे-धीरे अति सूक्ष्म कणों में बदलकर नदी की तलहटी में बैठ जाता है।

हरिद्वार, कानपुर और वाराणसी में नदी से पानी के नमूने एकत्रित कर गोवा में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (एनआइओ) के सहयोग से इनकी जांच की गई। परिणाम दर्शाते हैं कि गंगा जल में माइक्रोप्लास्टिक के तौर पर भी 40 प्रकार के अलग-अलग पालिमर मौजूद हैं। तीनों स्थानों में ईवीओएच, पलीएसिटिलीन, पीआइपी, पीवीसी और पीवीएएल जैसे रेजिन भारी मात्रा में मौजूद थे। वाराणसी और कानपुर में एकदम छोटे-छोटे दाने देखे गए, जबकि हरिद्वार में कोई दाना नहीं पाया गया। एनआइओ के प्रमुख अनुसंधानकर्ता डा. महुआ साहा ने बताया कि वाराणसी और कानपुर की तुलना में हरिद्वार में गंगा जल में माइक्रोप्लास्टिक की संख्या सबसे कम 1.30 से 0.518 तक माइक्रोप्लास्टिक प्रति घन मीटर थी।

> भविष्य को देखते हुए जलीय जीवन पर प्लास्टिक के खतरे से निपटने की अत्यंत जरूरत है। उद्योग, सरकार, नागरिक समाज संगठनों सहित विभिन्न दावेदारों को प्लास्टिक कचरा प्रबंधन में सुधार और बाद में माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण में कमी के लिए हाथ मिलाने की जरूरत है।
> –सतीश सिन्हा, एसोसिएट डायरेक्टर, टाक्सिक लिंक

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष

- गंगा मुख्य रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक और प्लास्टिक के बने सेकेंडरी उत्पादों से प्रदूषित पाई गई।
- वाराणसी में गंगा नदी के सतही जल में 2.42 से 0.405 तक माइक्रोप्लास्टिक प्रति घन मीटर पाई गई।
- कानपुर में गंगा नदी के सतही जल में 2.16 से 0.500 तक माइक्रोप्लास्टिकप्रति घन मीटर पाई गई।
- हरिद्वार में 1.30 से 0.518 तक माइक्रोप्लास्टिक प्रति घन मीटर पाई गई। यह मात्रा वाराणसी और कानपुर की तुलना में कम है।
- सभी जगहों पर सबसे अधिक टुकड़े पाए गए, जिसके बाद झिल्ली और रेशे। कानपुर में थोड़ा अंतर पाया, क्योंकि वहां झिल्ली की तुलना में रेशे अधिक मात्रा में पाए गए।
- तीनों जगहों पर सबसे अधिक काले और भूरे रंग के टुकड़े पाए गए। काले रंग के टुकड़ों का अधिक होना यह बताता है कि ये टायरों के टुकड़े थे। नदी में कई प्रकार के रबर (ब्यूटाडीन, पालीसोप्रीन, प्राकृतिक रबर) प्रचुर मात्रा में पाए गए।

डीएसजीएमसी चुनाव पर असमंजस खत्म, 22 अगस्त को होगा मतदान

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। गुरुद्वारा चुनाव आयोग निदेशालय (दिल्ली सरकार) ने जल्द चुनाव कराने की मांग को लेकर शिरोमणि अकाली दल (शिअद बादल) की तरफ से दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट को सूचित किया कि डीएसजीएमसी चुनाव 22 अगस्त को होंगे और 31 अगस्त से पहले परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।

मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ के समक्ष दिल्ली सरकार समेत अन्य की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता सत्यकाम ने कहा कि इस संबंध में तारीख तय कर ली गई है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष उपराज्यपाल से भी इसकी मंजूरी मिल गई है। इस संबंध में अधिसूचना बहुत जल्द जारी की जाएगी।

शिअद बादल ने चुनाव कराने के लिए गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय व दिल्ली सरकार को निर्देश देने की मांग की थी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अविनाश के मिश्रा ने पीठ से कहा कि चुनाव संबंधी शेष प्रक्रिया जल्द पूरा करने का निर्देश दिया जाए।

25 अप्रैल को पहले मतदान होना था, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया था। कोरोना के मामले कम होने के बाद सिख राजनीति से जुड़ी पार्टियां जल्द चुनाव कराने की मांग कर रही थीं। इस समय डीएसजीएमसी पर शिअद बादल का कब्जा है। पार्टी को पिछले दो चुनाव में जीत मिली है। पार्टी के सामने लगातार तीसरी बार जीत दोहराने की चुनौती है। डीएसजीएमसी के 55 सदस्यों में से 46 संगत द्वारा चुने जाते हैं।

14 जुलाई तक कोविड-19 से एयर इंडिया के करीब 56 कर्मचारियों की जान गई है। नागरिक उड्डयन मंत्री वीके सिंह ने लोकसभा में गुरुवार को एक सवाल के लिखित उत्तर में यह बताया।

देश में किसी की गैरकानूनी निगरानी संभव नहीं : वैष्णव

केंद्रीय मंत्री ने कहा, इस सनसनीखेज मामले में नहीं है कोई सच्चाई

पेगासस स्पाइवेयर बनाने वाली कंपनी ने भी जासूसी के दावों को किया है खारिज

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली



पेगासस जासूसी मामले को लेकर गुरुवार को राज्यसभा में बयान देते सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव। प्रेट्र

किसी फोन का तकनीकी विश्लेषण किए बगैर यह कह पाना कि उस पर किसी साइबर हमले का प्रयास सफल हुआ या नहीं, उचित नहीं होगा। डाटा बेस में फोन नंबर का मिलना किसी प्रकार की निगरानी को सिद्ध नहीं करता है।
– अश्विनी वैष्णव, इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

पेगासस जासूसी मामले में इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस विषय को तर्कसंगत तरीके से देखने से पता चलता है कि इस सनसनीखेज विषय में कोई सच्चाई नहीं है। संसद में दी गई जानकारी में उन्होंने कहा कि पेगासस से जुड़ी रिपोर्ट के प्रकाशक के अनुसार यह नहीं कहा जा सकता है कि इस रिपोर्ट में दिए गए फोन नंबरों की निगरानी की जा रही थी। उन्होंने कहा कि जिस कंपनी की तकनीक का कथित दुरुपयोग किया जा रहा था, उसने इन दावों को सिरे से खारिज किया है। इसके अलावा लंबे समय से देश में स्थापित कानूनी प्रक्रियाएं यह सुनिश्चित करती हैं कि किसी प्रकार की गैरकानूनी निगरानी संभव नहीं है।

चार दिन पहले स्पाइवेयर पेगासस के जरिये फोन के डाटा से छेड़छाड़ कर संबंधित व्यक्ति की जासूसी से जुड़ी खबर एक पोर्टल पर प्रकाशित होने के बाद काफी हो-हल्ला मचा था। गुरुवार को वैष्णव ने कहा कि पहले भी इसी प्रकार से पेगासस स्पाइवेयर के वाट्सएप पर दुरुपयोग के दावे किए गए थे। इन दावों का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं था और सर्वोच्च न्यायालय सहित सभी पक्षों ने उन्हें खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि पेगासस स्पाइवेयर के माध्यम से जासूसी की खबर का आधार एक समूह है, जिसने कथित तौर पर 50 हजार फोन नंबरों के लीक किए गए डाटा बेस को प्राप्त किया। आरोप यह है कि इन फोन नंबरों से संबंधित व्यक्तियों की निगरानी की जा रही थी, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि डाटा बेस में फोन नंबर मिलने से यह सिद्ध नहीं होता है कि फोन पेगासस स्पाइवेयर से प्रभावित था या उस पर कोई साइबर हमला किया गया था।

आइटी मंत्री ने कहा कि इस तकनीक का स्वामित्व रखने वाली एनएसओ मानती है कि ये सेवाएं किसी को भी कहीं भी किसी भी समय उपलब्ध हैं, जिनका सामान्य प्रयोग सरकारी संस्थाएं और प्राइवेट कंपनियां दुनियाभर में कर रही हैं। निश्चित रूप से इस डाटा का निगरानी या एनएसओ से कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए इस डाटा की निगरानी के लिए उपयोग होने की बात का कोई आधार नहीं है। वैष्णव ने कहा कि भारत में एक स्थापित प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से ही निगरानी के सभी मामले अनुमोदित किए जाते हैं। भारत के कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति के रूप में निगरानी की एक स्थापित व्यवस्था है।

डाटा प्रोटेक्शन बिल को रोकने की साजिश है पेगासस विवाद : भाजपा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सही नहीं आरोप

- मीनाक्षी लेखी ने कहा, संयुक्त संसदीय समिति लोस अध्यक्ष को सौंप चुकी है बिल
- येलो पेजेज जैसे डाटा से कुछ नाम और पते निकालकर जासूसी से जोड़ा गया



नई दिल्ली में गुरुवार को भाजपा मुख्यालय में प्रेस कान्फ्रेंस में सवालों के जवाब देतीं विदेश राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी। प्रेट्र

बिना किसी आधार के खड़ा किए गए पेगासस जासूसी विवाद के पीछे एक बड़ी वजह संसद में लंबित डाटा प्रोटेक्शन बिल भी है। भाजपा की वरिष्ठ नेता और विदेश राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी के अनुसार, संसदीय समिति ने डाटा प्रोटेक्शन बिल के मसौदे को हरी झंडी दे दी है और अब यह लोकसभा अध्यक्ष के पास स्वीकृति के लिए पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस विवाद की वजह डाटा प्रोटेक्शन बिल को रोकना है।

मीनाक्षी लेखी ने पेगासस जासूसी विवाद के पीछे बड़ी साजिश की ओर इशारा करते हुए कहा कि आनलाइन उपलब्ध येलो पेजेज जैसे डाटा से कुछ नाम और पते निकालकर एक सूची तैयार की गई और उसे पेगासस स्पाइवेयर से जासूसी कराए जाने से जोड़ दिया गया। दूसरी तरफ, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने साफ कर दिया है कि पेगासस जासूसी से जुड़ी जिस सूची को फैलाया जा रहा है, उसका मूल डाटा से कोई लेना-देना नहीं है। यही नहीं, पेगासस स्पाइवेयर बनाने वाली इजरायली कंपनी एनएसओ ने बयान जारी कर कहा कि उसके ग्राहकों से इस कथित सूची का कोई लेना-देना नहीं है।

भारत और उसकी संस्थाओं को कमजोर किए जाने का प्रयास : मीनाक्षी लेखी के अनुसार, बिना किसी आधार के विवाद खड़ा किए जाने की एक वजह भारत और उसकी संस्थाओं को कमजोर करना है, ताकि भारतीयों के निजी डाटा को सुरक्षित बनाने के लिए कड़े प्रविधानों वाला कानून लाने जा रही सरकार दबाव में आ जाए और सरकार की मंशा पर ही सवालिया निशान लग जाए। उन्होंने कहा कि सरकार आम आदमी से जुड़े डाटा को सुरक्षित करने का प्रयास कर रही है। उसे पटरी से उतारने के लिए फर्जी खबर फैलाई जा रही है। ध्यान देने की बात है कि सरकार ने 2018 में डाटा प्रोटेक्शन बिल लोकसभा में पेश किया था और उसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया था। लेखी के अनुसार सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों ने आम सहमति के विधेयक के प्रविधानों को अंतिम रूप दिया है।

पेगासस जासूसी मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : कथित पेगासस जासूसी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शीर्ष अदालत में गुरुवार को एक जनहित याचिका दाखिल हुई, जिसमें मामले की कोर्ट की निगरानी में एसआइटी से जांच कराए जाने की मांग की गई है।

वकील मनोहर लाल शर्मा की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया है कि पेगासस जासूसी मामले की कोर्ट की निगरानी में विशेष जांच दल (एसआइटी) से जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मांग यह भी है कि कोर्ट घोषित करे कि जासूसी के लिए पेगासस स्पाइवेयर मंगाना गैरकानूनी, असंवैधानिक व अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि पेगासस प्रकरण गंभीर चिंता का मामला है। पेगासस से सिर्फ बातचीत ही नहीं सुनी जा सकती, बल्कि किसी का पूरा डिजिटल प्रिंट हासिल किया जा सकता है। याचिका में दावा किया गया है कि वर्ष 2016 से कंपनी के क्लाइंट एनएसओ ने करीब 50 हजार फोन नंबरों को निशाना बनाया है, जो मेजर न्यूज आउटलेट में लीक हुए हैं। पेगासस सिर्फ सर्विलांस टूल नहीं है, बल्कि साइबर हथियार है जिसने भारतीय राजनीति को निशाना बनाया है।

750 करोड़ की लागत से लद्दाख में खुलेगा केंद्रीय विश्वविद्यालय

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- पीएम की अगुआई में कैबिनेट ने दी मंजूरी, अगले चार वर्षों में पूरा होगा पहले चरण का काम



नई दिल्ली में गुरुवार को प्रेस कान्फ्रेंस में कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर। एएनआइ

केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख के विकास के लिए पूरी ताकत से जुटी केंद्र सरकार ने गुरुवार को इसे दो और बड़े तोहफे दिए। इनमें पहला करीब 750 करोड़ की लागत से बनने वाला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसके पहले चरण का काम अगले चार वर्षों में पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही स्थानीय उद्योग और कारोबार को बढ़ावा देने के लिए लद्दाख में एक इंटीग्रेटेड मल्टीपरपस कारपोरेशन का भी गठन होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में लद्दाख को लेकर इन दोनों फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख के अस्तित्व में आने के बाद यह पाया गया कि यहां उच्च शिक्षा का कोई शीर्ष संस्थान नहीं है। इसके बाद ही केंद्र सरकार ने लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने का फैसला लिया था, जिसे अब मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि इस केंद्रीय विश्वविद्यालय के खुलने से इस पूरे क्षेत्र में उच्च शिक्षा को लेकर असमानता खत्म होगी। साथ ही स्थानीय शिक्षण संस्थानों को भी मजबूती मिलेगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अभी यह तय नहीं हुआ है कि इसमें शिक्षण कार्य कब से शुरू होगा। हालांकि, जब तक भवन का निर्माण नहीं हो जाता है, तब तक इसकी शुरुआत किराये के भवन से की जा सकती है। यह फैसला स्थानीय स्तर पर संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ही लिया जाएगा।

कैबिनेट में इसके साथ ही लद्दाख को लेकर दूसरा जो बड़ा फैसला लिया गया है, वह स्थानीय उद्योग को बढ़ावा देने से जुड़ा है। इसके तहत एक इंटीग्रेटेड मल्टीपरपस कारपोरेशन का गठन किया जाएगा। यह 25 करोड़ की पूंजी से अपना काम शुरू करेगा। इसका सालाना खर्च करीब 2.42 करोड़ का होगा। इसके साथ ही इसका एक प्रबंध निदेशक भी होगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मौजूदा समय में लद्दाख में ऐसा कोई संगठन नहीं है। इससे उद्योग, पर्यटन, परिवहन, हस्तशिल्प आदि को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

निजता का सम्मान होना चाहिए : अब्दुल्ला शाहिद

- संयुक्त राष्ट्र महासभा के निर्वाचित अध्यक्ष का पहला विदेश दौरा



नई दिल्ली में गुरुवार को मीडिया से बातचीत करते संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष (निर्वाचित) अब्दुल्ला शाहिद। एएनआइ

नई दिल्ली, प्रेट्र : पेगासस जासूसी प्रकरण पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष (निर्वाचित) अब्दुल्ला शाहिद ने कहा है कि निजता मनुष्य का अधिकार है, इसका सम्मान होना चाहिए। कहा, सभी सभ्य देशों के संविधान में निजता को प्रत्येक नागरिक का अधिकार माना गया है और उसके सम्मान का संकल्प व्यक्त किया गया है। शाहिद इस समय मालदीव के विदेश मंत्री हैं, लेकिन वह संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष (निर्वाचित) की हैसियत से तीन दिवसीय भारत यात्रा पर आए हुए हैं।

शाहिद ने कहा, डिजिटल युग में प्रशासन को इस बात का ज्यादा गंभीरता से ध्यान रखना होगा कि निजता का सम्मान बना रहे। यह बात दुनिया के सभी देशों पर लागू होती है। उल्लेखनीय है कि भारत समेत दुनिया के कई देशों में पेगासस स्पाइवेयर के जरिये जासूसी होने की बात सामने आई है। आरोपों की जांच भी हो रही है।

पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात : गुरुवार को विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने शाहिद से मुलाकात कर भारत और मालदीव के संबंधों पर बात की। साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में शाहिद को पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया। विदेश मंत्रालय के अनुसार, शाहिद अपने दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात करेंगे। सात जून को महासभा का अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद शाहिद का यह पहला विदेश दौरा है।

'सरकार को दिल्ली सीमा पर प्रदर्शन कर रहीं महिला किसानों की चिंता'

नई दिल्ली, प्रेट्र : दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन कर रहीं महिला किसानों के कुशल-क्षेम को लेकर सरकार बहुत चिंतित है। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्यसभा में गुरुवार को एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कृषि मंत्रालय ने प्रदर्शन कर रहे किसान यूनियनों से अपील की है कि महिलाओं से मौसम की गंभीर स्थिति और कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए घर लौटने का आग्रह किया जाना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री ने लिखित उत्तर में कहा, 'महिला किसानों के कुशल-क्षेम को लेकर सरकार बहुत चिंतित है। कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय ने वार्ता के दौरान किसान यूनियनों से बच्चे और बुजुर्ग, खास तौर से महिलाओं से मौसम की गंभीर स्थिति और कोविड महामारी का ध्यान रखते हुए घर लौटने का आग्रह करने की अपील की। महिला किसान समेत नागरिकों की हालत का ध्यान रखते हुए स्थानीय निकाय और राज्य, केंद्र शासित सरकार बुनियादी सुविधाएं मुहैया करा रही हैं।'

कोविड लाकडाउन के कारण बाल उत्पीड़न में वृद्धि की सूचना नहीं : एक सवाल के जवाब में ईरानी ने कहा कि सरकार के पास अभी तक कोविड के कारण लाकडाउन के कारण बाल उत्पीड़न के मामलों में वृद्धि के आंकड़े से संबंधित कोई सूचना नहीं है। इसके साथ ही कोरोना वायरस से उत्पन्न आर्थिक कठिनाइयों के कारण देश भर में बाल विवाह में वृद्धि का भी आंकड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को महामारी के दौरान बच्चों के संरक्षण और देखभाल के लिए परामर्श और दिशानिर्देश जारी किए हैं।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय का भुगतान ट्रैकर से लिंक : महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि मार्च से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय का भुगतान पोषण ट्रैकर डाउनलोडिंग और उनके द्वारा एप में तेजी से डाटा डालने से लिंक किया गया है। उन्होंने कहा कि इस कदम का लक्ष्य पोषण ट्रैकर के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देना और लाभार्थियों के लाभ की वास्तविक निगरानी है।

रुसा योजना के तहत पिछड़े जिलों में 130 डिग्री कालेजों को मंजूरी : केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उच्च सदन में एक लिखित सवाल के उत्तर में बताया कि शैक्षणिक रूप से पिछड़े जिलों में केंद्रीय वित्त पोषित योजना राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा) ने 130 माडल डिग्री कालेज के केंद्रीय समर्थन को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित विशेष समिति ने जहां 2001 की जनगणना के आधार पर उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात राष्ट्रीय औसत 12.4 फीसद से कम था, वहां 374 ईबीडी की पहचान की है।

जो संघ लोकसेवा परीक्षा नहीं दे सके, उन्हें दूसरा मौका नहीं : कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार संघ लोकसेवा आयोग की परीक्षा में जो प्रतिभागी 2020 की परीक्षा में भाग नहीं ले पाए उन्हें दूसरा मौका देने पर विचार कर रही है, के जवाब में कहा, 'नहीं महोदय। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।'

राज्यसभा प्रश्नोत्तर

अप्रैल-मई में कोविड से 645 बच्चों के माता-पिता का निधन

ईरानी ने एक अन्य सवाल के उत्तर में बताया कि अप्रैल से 28 मई तक कोविड-19 से कुल 645 बच्चों के माता-पिता का निधन हो गया। केंद्रीय मंत्री ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अनाथ हुए बच्चे का आंकड़ा दिया।

सीईआरटी ने लोगों को धोखा देने वाले करीब 140 मामलों की पहचान की

इलेक्ट्रानिक्स एवं आइटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक लिखित उत्तर में बताया कि 2021 के पहले छह महीने के दौरान इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-इन) ने करीब 140 धोखा देने वाले मामलों की पहचान की। सीईआरटी-इन द्वारा पकड़ी और दी गई जानकारी के अनुसार, जाली ईमेल, एसएमएस संदेश और लोगों को फंसाने वाली वेबसाइटों ने यूजर्स को धोखा देने के प्रयास किए।

संयुक्त राष्ट्र की कर समिति में वित्त मंत्रालय के अफसर की नियुक्ति

संयुक्त राष्ट्र, प्रेट्र : वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव रश्मि रंजन दास को संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है और उनका कार्यकाल 2021 से 2025 तक होगा।



रश्मि रंजन दास की फाइल फोटो (इंटरनेट मीडिया)

दुनिया भर के 25 दिग्गज कर विशेषज्ञों वाली यह समिति औपचारिक रूप से कर मामलों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर विशेषज्ञों की समिति है, जो वैश्विक व्यापार और निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था और पर्यावरण सुरक्षा के संबंध में मजबूत और अधिक दूरदर्शी कर नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए देशों का मार्गदर्शन करती है। यह समिति देशों को दोहरे या एकाधिक कराधान से रोकने, उनके कर आधार को व्यापक बनाने, कर प्रशासन को मजबूत करने और अंतरराष्ट्रीय कर चोरी को रोकने में सहायता करती है। दास वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में संयुक्त सचिव हैं।

जी-20 देशों के साथ मिल भारत ने काम करने का जताया भरोसा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

प्रयास

- इन देशों के पर्यावरण मंत्रियों के साथ वन एवं पर्यावरण मंत्री की चर्चा
- कहा, विकासशील देशों को पहले से अधिक समर्थन की जरूरत



केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। फाइल/इंटरनेट मीडिया

पर्यावरण सुधार की दिशा में उठाए गए कदमों को जी-20 देशों के सामने रखते हुए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि वह अपने लोगों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए जी-20 देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हालांकि, यह प्रयास तभी सफल होगा, जब इस मुहिम का पूरी दुनिया साथ देगी। फिलहाल इस मुहिम में विकासशील देशों को पहले से कहीं अधिक समर्थन की जरूरत है।

वन एवं पर्यावरण मंत्री यादव गुरुवार को जी-20 देशों के पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन में बोल रहे थे। इटली में आयोजित इस सम्मेलन में उन्होंने 'प्रकृति आधारित समाधान' (एनबीएस) और सतत विकास पर अपनी राय रखी। उन्होंने इस दौरान समुद्री और प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए उठाए गए कदमों को भी प्रमुखता से रखा। इनके अलावा बेकार भूमि को बेहतर बनाने, समुद्री किनारों को स्वच्छ रखने, जैव विविधता और वन क्षेत्र को बढ़ाने जैसे अहम कदम को भी साझा किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण सुधार को लेकर उठाए गए भारत के कदमों को दुनिया पहले से सराहना कर चुकी है। इसके साथ ही भारत ने सुधार को लेकर जो लक्ष्य तय किए है, वह उसे जल्द ही हासिल करने को लेकर प्रतिबद्ध है।

पेंशन नियमों में बदलाव का सरकार ने किया बचाव

नई दिल्ली, प्रेट्र : कार्मिक मंत्रालय ने राज्यसभा को बताया है कि देश को नुकसान से बचाने के लिए पेंशन नियमों में हाल ही में बदलाव किए गए हैं। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को एक लिखित जवाब में बताया कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) संशोधन नियम, 2021 के नियम आठ में बदलाव किए गए हैं। इस नियम में बदलाव से पहले इससे संबद्ध लोगों से परामर्श किया गया था।

कार्मिक मंत्रालय ने मई में संशोधित पेंशन नियमों को अधिसूचित किया था। इसके जरिये उन सभी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को जो चयनित खुफिया या सुरक्षा संबंधी संगठनों में रहे हैं, उन्हें अपने किसी भी प्रकाशन से पहले अपने विभाग के प्रमुख से स्वीकृति लेनी होगी। जितेंद्र सिंह ने बताया कि संशोधन के संबध में यह संबंधित अधिकारी को तय करना होगा कि सामग्री का प्रकाशन होना चाहिए या नहीं। अगर अधिकारियों को लगता है कि प्रकाशन की सामग्री प्रतिबंधित श्रेणी की नहीं है तो वह उसका प्रकाशन सरकार से मंजूरी लिए बगैर भी कर सकते हैं।

पिछले एक साल में उच्च न्यायालयों में नियुक्त हुए 45 जज : केंद्र सरकार

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा में बताया कि सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने पिछले एक साल में विभिन्न हाई कोर्ट में 80 जजों की नियुक्ति की सिफारिश की। इनमें 45 जजों की नियुक्ति हो चुकी है, जबकि बाकी प्रस्ताव प्रक्रिया के अधीन हैं।

कानून मंत्री किरण रिजिजू ने लिखित जवाब में बताया कि एक जुलाई, 2020 से 15 जुलाई 2021 तक सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने विभिन्न हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए 80 नामों की सिफारिशें कीं। इनमें 45 की नियुक्ति की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट जज की नियुक्ति की प्रक्रिया थोड़ी लंबी है। राज्य व केंद्र स्तर पर कई संवैधानिक प्राधिकारों से अनुमोदन लेना होता है। इसलिए जजों की नियुक्ति में वक्त लगता है। 25 हाई कोर्ट में जजों के कुल 1,098 पद स्वीकृत हैं। हालिया जानकारी के मुताबिक, 645 जज काम कर रहे हैं, जबकि 453 पद खाली हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए कोलेजियम ने 11 नामों की संस्तुति की, जिनमें सात की नियुक्ति हो चुकी है। दिल्ली हाई कोर्ट के लिए छह नामों की सिफारिश की गई थी, जिनमें दो की नियुक्ति हुई है।

धर्मसंकट

ऐसी किसी संभावना को न तो स्वीकार किया और न ही खारिज, अभी तक भारत ने पड़ोसी देश को सिर्फ हेलीकाप्टर मुहैया कराए

अफगानिस्तान को सैन्य मदद पर भारत की कूटनीतिक चुप्पी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

तालिबान के साथ लड़ाई बढ़ते देख भारत, अफगानिस्तान सरकार को सैन्य मदद भेजेगा या नहीं, इस पर भारत ने कूटनीतिक चुप्पी साधी हुई है। इन संभावनाओं को भारत न तो खारिज कर रहा है और न ही स्वीकार कर रहा है। इसे भारत के रवैये में एक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि भारत अभी तक अफगानिस्तान को सैन्य मदद देने के सवालों को एक सिरे से खारिज करता रहा है।

अफगानिस्तान सेना के प्रमुख अगले कुछ दिनों में भारत के दौरे पर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि उनकी नई दिल्ली में सैन्य सहयोग को लेकर बातचीत होगी। क्या भारत अफगान को सैन्य मदद देने जा रहा है। यह सवाल गुरुवार को जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची से पूछा गया तो उनका जवाब था कि भारत व अफगान के रिश्ते इनके बीच अक्टूबर, 2011 में हुए रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हुए हस्ताक्षर से तय होते हैं।

एक पड़ोसी देश होने के नाते भारत अफगानिस्तान सरकार व वहां की जनता को एक शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक व समृद्ध भविष्य बनाने में मदद देता है, ताकि वहां के समाज के महिलाओं व अल्पसंख्यकों समेत हर वर्ग के हितों की रक्षा हो सके। वर्ष 2020 में जेनेवा में हुई अफगानिस्तान कान्फ्रेंस में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अफगानिस्तान के विकास को लेकर भारत ने अपनी प्रतिबद्धता जताई थी। साफ है कि बागची ने यह नहीं कहा कि भारत अफगानिस्तान को सैन्य मदद नहीं देगा। भारत अभी तक यही कहता रहा है कि वह अफगानिस्तान के सिर्फ विकास कार्यों व प्रशासन चलाने में मदद देने की नीति पर चलता है।

दैनिक जागरण ने यही सवाल कुछ दिन पहले अफगानिस्तान के नई दिल्ली स्थित राजदूत फरीद मामुंदजई से पूछा तो उनका जवाब था कि अभी भारत से सैन्य मदद की जरूरत नहीं है क्योंकि अमेरिकी सेना की तरफ से कुछ साजो सामान व हथियार हमें मुहैया कराये गये हैं, लेकिन हो सकता है कि अमेरिकी सेना की पूरी वापसी के बाद यह मदद न मिले तब हमें भारत से सैन्य मदद चाहिए। भारत को वहां अपनी सेना भेजने की जरूरत नहीं है लेकिन एक साथ कई आतंकी संगठनों से लंबे समय तक लड़ने के लिए हमें हेलीकाप्टर, हथियार व दूसरे साजों सामान चाहिए।

जानकारों का कहना है कि पूर्व में भी भारत ने अफगानिस्तान के सैनिकों को प्रशिक्षण दिया है और कुछ हेलीकाप्टर भी उपलब्ध कराये हैं। अभी अफगानिस्तान को सबसे ज्यादा हेलीकाप्टरों व विमानों की जरूरत है। माना जाता है कि इनके बगैर तालिबान की बढ़ते कदम को रोकना मुश्किल होगा।

भारत पर आरोप मढ़ कर अपने स्तर से और नीचे गिरा पाकिस्तान

नई दिल्ली : पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अफगानिस्तान के राजदूत की बेटी का दिनदहाड़े हुआ अपहरण को भारत ने हतप्रभ करने वाली घटना करार दिया है। साथ ही पाकिस्तान सरकार के एक बड़े कैबिनेट मंत्री की तरफ से इस विवाद में भारत को घसीटने की भारत ने कड़े शब्दों में भर्त्सना भी की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि यह मामला अफगानिस्तान व पाकिस्तान के बीच का मामला है और आम तौर पर हमें इस पर टिप्पणी नही करनी चाहिए। हालांकि पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री ने इसमें भारत को घसीटा है और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से भी अपहृता के बयान को खारिज करना एक नया निम्न स्तर है।



विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची। जागरण आर्काइव

कह के रहेंगे माधव जोशी



24 से 25 जुलाई तक गोवा दौरे पर रहेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। अगले वर्ष होने जा रहे विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस यात्रा के दौरान नड्डा पार्टी की विभिन्न शाखाओं और नेताओं से वार्ता करेंगे।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 23 जुलाई, 2021

लोस के सवालों के जवाब पर ममता ने बंगाल में बैठाया पहरा

टकराव ▸ मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश, सभी सवालों के जवाब अब उच्च प्राधिकारी की मंजूरी से ही दिए जाएंगे

दो साल पहले जिलाधिकारियों के सीधे केंद्र को जवाब देने पर लगाई थी रोक

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

बंगाल में जिलाधिकारियों पर रोक लगाने के बाद ममता सरकार ने अब सभी विभागों पर भी लगाम लगा दी है कि बिना उच्च प्राधिकारी की अनुमति के किसी भी सवाल का जवाब सीधे लोकसभा को नहीं भेजा जाएगा। राज्य सरकार ने निर्देश जारी कर कहा है कि लोकसभा के सभी सवालों के जवाब उच्च प्राधिकारी की मंजूरी से ही दिए जा सकेंगे और सब कुछ आवंटित समय के भीतर किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक कुछ मामलों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी मंजूरी मांगी जा सकती है। माना जा रहा है कि ममता सरकार ने यह आदेश केंद्रीय स्तर से किए जाने वाले सवालों पर किसी संवेदनशील जानकारी के राज्य से बाहर जाने पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने के लिए उठाया है।

राज्य के मुख्य सचिव हरिकृष्ण द्विवेदी ने इस बाबत सभी विभागों के सचिवों को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि 2019 में विभागों को लिखित तौर पर चेतावनी दिए जाने के बावजूद देखा गया कि सवालों के जवाब समय पर तैयार नहीं हो रहे थे। लोकसभा को भेजे जाने वाले जवाब निर्धारित समय से पहले तत्काल आधार पर तैयार करने होंगे और जवाब का मसौदा मुख्य सचिव के पास भेजना होगा। उनकी मंजूरी मिलने के बाद ही इसे लोकसभा में भेजा जाएगा।

सवालों को हल्के में नहीं लेना चाहती सरकार : गौरतलब है कि केंद्र और ममता सरकार के बीच तनाव बढ़ गया है। राज्य पर केंद्र का दबाव बढ़ रहा है, खासकर कानून-व्यवस्था के सवाल पर। ममता सरकार इसे हल्के में नहीं ले रही है इसलिए लोकसभा से पूछे जाने वाले सवालों को लेकर सतर्कता बरती जा रही है ताकि अहम मुद्दों पर प्रतिक्रिया केंद्र के लिए हथियार न बन सके।

सूचनाओं पर राज्य की स्थिति नहीं खाती मेल : प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार के साथ विभिन्न मुद्दों से संबंधित सूचनाओं पर राज्य की स्थिति अक्सर मेल नहीं खाती। राज्य किसी विशेष मुद्दे पर केंद्र द्वारा दी गई जानकारी को स्वीकार नहीं करना चाहता है, बल्कि इसकी प्रतिसूचना पर प्रकाश डालता है। विधानसभा चुनाव में मतदान से पहले ही राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में राज्य की प्रगति पर केंद्रीय सूचना का विरोध किया था। मुख्यमंत्री ने खुद केंद्र की सूचना की सत्यता पर सवाल उठाया था।

एनसीआरबी भी करता रहा है शिकायत : दो साल पहले अपने पिछले कार्यकाल में ममता ने समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे राज्य सरकार की अनुमति के बिना कोई भी सूचना केंद्र के साथ साझा न करें। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) भी ममता सरकार पर बंगाल में होने वाले आपराधिक घटनाओं का डाटा उपलब्ध नहीं कराने की शिकायत करता रहा है।

26 को दिल्ली जाएंगी ममता, पीएम से मिलेंगी

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

- पांच दिन तक राष्ट्रीय राजधानी में रहेंगी, राष्ट्रपति से भी होगी मुलाकात
- बंगाल की सीएम ने पेगासस विवाद को बताया सुपर इमरजेंसी

पेगासस जासूसी विवाद के बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक ममता 26 जुलाई, सोमवार को दिल्ली पहुंच रही हैं। वह पांच दिनों तक दिल्ली में ही रहेंगी और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी तथा राष्ट्रपति के साथ मुलाकात करेंगी। संभवत: 28 जुलाई को प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात होगी। ममता बनर्जी ने जासूसी विवाद को लेकर गुरुवार को कहा कि पेगासस विवाद इमरजेंसी से भी बड़ी सुपर इमरजेंसी है।

दिल्ली यात्रा को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे मिलने का समय दिया है, उनसे मुलाकात करूंगी। हालिया बंगाल चुनाव के बाद ममता का यह पहला दिल्ली दौरा होगा और वह कई विपक्षी दलों के नेताओं से भी मिलेंगी।

जासूसी विवाद में लगाए गंभीर आरोप : ममता ने जासूसी विवाद को वाटरगेट स्कैंडल से भी बड़ा घोटाला बताया और कहा कि यह लोगों को डराने के हथकंडे हैं। कहा कि भाजपा की अगुआई वाली केंद्र सरकार ने न्यायपालिका से लेकर मीडिया सभी को बंधक बना लिया है। इस सरकार के खिलाफ जो भी आवाज उठाता है उसे कुचल दिया जाता है। देश में सुपर इमरजेंसी जैसे हालात हैं। सभी से एकजुट होकर आंदोलन का आह्वान करते हुए ममता ने दावा किया कि मंत्रियों व अधिकारियों ही नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के नेताओं का भी फोन टैप किया जाता है। ममता ने कहा कि पेगासस मुद्दे पर पीएम को बयान देना चाहिए। यह करने की जगह इसके खिलाफ आवाज उठाने वालों को कुचला जा रहा है। उन्होंने इसे खतरनाक बताते हुए कहा कि देश की जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। ममता ने आगे कहा कि हमने अपने फोन पर टेप (ल्यूकोप्लास्ट) लगा लिया है। यह सांकेतिक विरोध है। सभी को सिविक सोसाइटी, छात्र बुद्धिजीवी को एकजुट होकर विरोध करना होगा।

महिलाएं क्या खाना बना रही, यह भी टैप हो रहा :उन्होंने कहा कि महिलाएं क्या खाना बना रही हैं, पति के साथ क्या बात कर रही हैं, सबकुछ टैप किया जा रहा है। पहले समझते थे कि वाट्सएप सुरक्षित है लेकिन वह भी अब सुरक्षित नहीं है। मैं अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित नहीं हूं, बल्कि देश के लोगों के लिए चिंतित हूं। ममता ने यह भी आरोप लगाया कि हमने मीटिंग की, उसकी भी रिकार्डिंग की गई।

16 अगस्त को खेला होबे दिवस पर एक लाख फुटबाल बाटेंगी सीएम

ममता कहा कि 16 अगस्त को खेला होबे दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने एक बार फिर कहा कि जब तक पूरे देश से भाजपा को नहीं हटा देतीं, खेला जारी रहेगा। उन्होंने घोषणा की कि खेला होबे दिवस के मौके पर राज्य सरकार प्रदेश के विभिन्न फुटबाल क्लबों व गांवों में एक लाख फुटबाल वितरित करेगी। ममता ने कहा कि 16 अगस्त का दिन इसलिए चुना है क्योंकि इसी दिन 1970 में कुछ लोग एक क्रिकेट इवेंट में मारे गए थे। उन्होंने कहा कि यह 15 अगस्त के बाद का दिन है। लोगों की स्वाधीनता बनी रहे और भारत पराधीनता से मुक्ति पाए, इसीलिए उन्होंने इस दिन को चुना।

बंगाल हिंसा पर ममता सरकार को हलफनामा देने का आखिरी मौका

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल में चुनाव बाद हिंसा के मामलों में पक्ष रखने के लिए बंगाल सरकार को 26 जुलाई तक हलफनामा पेश करने को कहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अधिवक्ता ने कोर्ट से कहा कि राज्य में अब भी हिंसा जारी है। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता ने कहा कि चुनाव बाद हिंसा पर हाई कोर्ट को सौंपी गई एनएचआरसी की रिपोर्ट में कई विसंगतियां हैं तथा यह राजनीति से प्रेरित है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को है। बता दें, एनएचआरसी ने रिपोर्ट में चुनाव के बाद हिंसा को सत्तारूढ़ दल के समर्थकों द्वारा मुख्य विपक्षी दल के समर्थकों के खिलाफ प्रतिशोधात्मक हिंसा करार दिया है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल, न्यायाधीश आइपी मुखर्जी, न्यायाधीश हरीश टंडन, न्यायाधीश सौमेन सेन व न्यायाधीश सुब्रत तालुकदार की बेंच ने कहा कि राज्य सरकार को एनएचआरसी की रिपोर्ट के जवाब में हलफनामा दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया जा रहा है।

बंगाल संभलता नहीं, देश चलाने का सपना देख रहीं ममता : रूपा गांगुली

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भाजपा नेता व राज्यसभा सदस्य रूपा गांगुली ने हमला बोला है। ममता पर तंज कसते हुए रूपा गांगुली ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की मुखिया से राज्य संभलता नहीं है और वह देश चलाने का सपना देख रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी राज्य में एक भी मामले को ठीक करने में सक्षम नहीं हैं। रूपा का यह बयान एक दिन पहले ममता द्वारा तृणमूल के शहीद दिवस कार्यक्रम के मंच से 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के खिलाफ सभी विपक्षी दलों से एकजुट होने के आह्वान के बाद आया है।

एक समाचार एजेंसी से बातचीत में रूपा ने कहा कि राज्य में चुनाव बाद हिंसा के दौरान करीब 35,000 महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। उन्होंने कहा, आपको (ममता) लगता है कि भारत के सभी लोगों को नहीं पता कि बंगाल में किस तरह की हिंसा हुई। ममता के कार्यकाल 2015-16 के बाद से यहां जो कुछ भी हुआ है, क्या वह सही है? ममता के खेला होबे दिवस के रूप में 16 अगस्त की तारीख चुनने को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि यह स्वतंत्रता से पहले कलकत्ता की हत्याओं की तारीख के साथ मेल खाता है। उन्होंने कहा, देखिए, सबसे पहले तो ममता बनर्जी बहुत झूठ बोलती हैं। बंगाल में उन्होंने जो हालात पैदा किए हैं, वह पूरे भारत में कभी नहीं हुए। उन्होंने 16 अगस्त को खेला दिवस के रूप में मनाने के लिए क्यों चुना? यह भी चिंता का विषय है क्योंकि उस दिन से जुड़ा एक काला इतिहास है।

येदियुरप्पा ने पद छोड़ने का दिया संकेत, हाई कमान के निर्देश का इंतजार

- कहा, केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशों का करूंगा पालन, उत्तराधिकारी का नाम बताने से किया इन्कार



बीएस येदियुरप्पा। फाइल/इंटरनेट मीडिया

बेंगलुरु, प्रेट्र : कर्नाटक के मुख्यमंत्री की कुर्सी बचेगी या नहीं, इन अटकलों को लेकर बीएस येदियुरप्पा ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए संकेत दिया कि उनका पद छोड़ना सन्निकट है। कहा-मैं इस पद पर तब तक रहूंगा, जब तक केंद्रीय नेतृत्व उन्हें हटने के लिए नहीं कहता।

गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में 78 वर्षीय लिंगायत नेता ने कहा कि मैंने दो माह पहले भी इस्तीफे की पेशकश की थी ताकि दूसरों के लिए रास्ता निकले। उन्होंने कहा कि यदि पूछा गया तो भी वह अपने संभावित उत्तराधिकारी का नाम नहीं बताएंगे। यह केंद्रीय नेतृत्व पर है। येदियुरप्पा ने कहा कि हाल के दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय नेतृत्व ने उनसे इस बारे में कोई बात नहीं की। मुख्यमंत्री के रूप में मेरे भविष्य को लेकर हाई कमान 25 जुलाई को कोई निर्देश दे सकता है और आखिरी मिनट तक मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता रहूंगा।

येदियुरप्पा ने कहा, मैंने अभी तक कोई संदेश प्राप्त नहीं किया है। मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। यदि 25 जुलाई तक कोई संदेश आता है तो मैं केंद्रीय नेतृत्व के फैसले का पालन करूंगा। मैंने यह बात पहले भी कही है और अब फिर कह रहा हूं। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा, कुर्सी रहे या न रहे मैं पूरे राज्य का दौरा करूंगा और संगठन को मजबूत करने के लिए काम करूंगा ताकि वह फिर सत्ता में आ सके।

भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा, शुक्रवार को बेंगलुरु में विकास कार्यों की समीक्षा करूंगा। आखिरी मिनट तक मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता रहूंगा। देखते हैं आगे क्या होता है। किसी प्रकार के भ्रम को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी एकजुट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह तथा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश का पालन करना 'हमारी ड्यूटी' है।

यह पूछे जाने पर कि क्या उनका उत्तराधिकारी लिंगायत समुदाय से होना चाहिए तो वरिष्ठ नेता ने कहा कि मैं कोई दबाव नहीं दूंगा। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का मेरे प्रति विशेष स्नेह एवं विश्वास है।

उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि उन लोगों को कोई पद नहीं दिया जाता जिनकी उम्र 75 साल से अधिक हो गई है, लेकिन मेरे काम की सराहना करते हुए उन्होंने 78 वर्ष की आयु होने के बावजूद मुझे मौका दिया।

उन्होंने गुरुवार को कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक को मुख्यमंत्री के रूप में उनकी आखिरी बैठक माना जा रहा है। येदियुरप्पा की इस सरकार के 26 जुलाई को दो वर्ष पूरे हो जाएंगे।

अभिषेक ने दिल्ली में पार्टी सांसदों संग की बैठक

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए विपक्षी एकता के आह्वान के ठीक अगले दिन गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सुप्रीमो ममता बनर्जी के भतीजे व सांसद अभिषेक बनर्जी ने दिल्ली में अपनी पार्टी के सभी सांसदों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में संसद के मौजूदा सत्र में केंद्र सरकार को पेगासस फोन टैपिंग विवाद सहित ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी, महंगाई, बेरोजगारी, वैक्सीन समेत विभिन्न मुद्दों पर जोरदार तरीके से घेरने की रणनीति तय की गई।

यह बैठक दोपहर में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के दिल्ली के महादेव रोड स्थित आवास पर हुई। बताया जाता है कि बैठक में तृणमूल के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी मौजूद थे। सूत्रों का कहना है कि इसके पहले अभिषेक ने सुबह भी राज्यसभा और लोकसभा में टीएमसी के सभी सांसदों के साथ बैठक की। इन बैठकों में संसद में पार्टी की रणनीति, सत्ताधारी दल भाजपा से कैसे मुकाबला किया जाए और सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले विधेयकों जैसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई और अभिषेक ने अपने सांसदों को पार्टी की स्थिति के बारे में बताया।

अब होगा फैसला, राजस्थान की सुलह समिति ने सोनिया को रिपोर्ट सौंपी

जागरण संवाददाता, जयपुर

- अशोक गहलोत की जल्द हो सकती है सोनिया से मुलाकात

राजस्थान कांग्रेस में कलह को खत्म करने के लिए बनाई गई सुलह कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंप दी है। रिपोर्ट में मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत के कामकाज, उनके जनता व कार्यकर्ताओं से जुड़ाव को बेहतर बताया गया है। लेकिन यह भी कहा गया है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पार्टी के लिए एसेट हैं।

सूत्रों के मुताबिक पिछले दिनों सौंपी गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पायलट को संगठन में महत्व देने में जितना विलंब होगा, पार्टी को उतना ही नुकसान होगा। रिपोर्ट में पायलट की मांग के अनुसार उनके खेमे के चार से पांच विधायकों को मंत्री बनाने व राजनीतिक नियुक्तियों में महत्व देने की बात कही गई है। समिति के अनुसार, आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत स्थिति में लाने के लिए गहलोत और पायलट का विवाद शीघ्र खत्म होना आवश्यक है। इसी बीच गहलोत शुक्रवार को दिल्ली जा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार गहलोत की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से टेलीफोन पर बात हुई है। उनका दिल्ली में सोनिया गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल व अन्य नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम है। सूत्रों के अनुसार आलाकमान चाहता है कि पहले मंत्रिमंडल विस्तार, विधानसभा में उपाध्यक्ष और संसदीय सचिव बनाने का काम पूरा कर लिया जाए। इनमें जिन विधायकों को स्थान नहीं मिलता है उन्हे राजनीतिक नियुक्तियों में महत्व दिया जाए। गहलोत का कहना है कि पायलट की बगावत के समय बसपा से कांग्रेस में शामिल होने वाले जिन विधायकों के कारण सरकार सुरक्षित रही, उन्हें महत्व दिया जाए।

प्रियंका ले रहीं दिलचस्पी : पिछले साल पायलट की बगावत के बाद वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पिछले कुछ दिनों में गहलोत व पायलट से बात की है। वह सुलह समिति के सदस्यों वेणुगोपाल और अजय माकन से लगातार संपर्क में हैं। दोनों नेताओं रिपोर्ट तैयार करने से पहले भी प्रियंका से बात की है। अब वह जल्द निर्णय कराने की कोशिश में हैं। सूत्रों के अनुसार गहलोत ने प्रदेश प्रभारी अजय माकन को लेकर अपनी नाराजगी प्रियंका के समक्ष जाहिर की है। दरअसल, पिछले दिनों माकन ने एक ट्वीट को रीट्वीट किया था, जिसमें लिखा गया था कि किसी भी राज्य में कोई क्षत्रप अपने दम पर नहीं जीतता है। गांधी, नेहरू परिवार के नाम पर ही गरीब, कमजोर वर्ग, आम आदमी का वोट मिलता है। मगर, अमरिंदर सिंह हों या गहलोत या पहले शीला या कोई और, मुख्यमंत्री बनते ही समझ लेते हैं कि उनकी वजह से ही पार्टी जीती है।

गहलोत और पायलट को सिद्धू का बुलावा : पंजाब के नए कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू शुक्रवार को अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। उन्होंने गहलोत और पायलट को आमंत्रित किया है। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी को भी बुलाया गया है। चौधरी लंबे समय तक पंजाब के प्रभारी रहे हैं।

उत्तराखंड में आप ने सीएम के चेहरे के तौर पर कर्नल कोठियाल का नाम उछाला

जागरण संवाददाता, रुड़की

- दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने कर्नल कोठियाल के भावी मुख्यमंत्री होने को लेकर जनता से पूछा सवाल
- कहा, प्रदेश में अच्छी शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं न मिलना बड़ी समस्या

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में कर्नल अजय कोठियाल का नाम उछाल दिया है। उन्होंने कहा कि वह जनता से यह सवाल पूछने आए हैं कि क्या कर्नल अजय कोठियाल जैसे व्यक्ति को भावी मुख्यमंत्री होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस सवाल पर समाज के विभिन्न तबकों से सकारात्मक जवाब मिला है।

दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गुरुवार को रुड़की पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता के पास दो विकल्प हैं। पहली भाजपा सरकार है जो बार-बार मुख्यमंत्री का चेहरा बदल रही है।

त्रिवेंद्र सिंह रावत व तीरथ सिंह रावत के बाद अब पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं। सिसोदिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे में जनता के पास एक तरफ भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाले नेता हैं, तो दूसरी तरफ कर्नल अजय कोठियाल जैसे देशभक्त और देवभूमि के लाल हैं, जिनका जीवन देश के लिए समर्पित रहा है।

उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे से संबंधित सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यह पार्टी, कार्यकर्ता और प्रदेश की जनता तय करेगी। कहा कि आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी।

उत्तराखंड में पलायन और बेरोजगारी के मुद्दे पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि प्रदेश में अच्छी शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं न मिलना एक बड़ी समस्या है। यही पलायन व बेरोजगारी की मुख्य वजह हैं। आम आदमी पार्टी ऐसी शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेगी, जिससे रोजगार उत्पन्न किया जा सकेगा।

सिद्धू के अमृतसर आवास पर बनी हस्ताक्षर वाले न्योते की रणनीति



चंडीगढ़ के पंजाब भवन में कांग्रेस पार्टी नेताओं के साथ मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह। एएफपी

प्रथम पृष्ठ से आगे

कांग्रेस सूत्रों के अनुसार कैप्टन को विधायकों के हस्ताक्षर वाला न्योता देने की रणनीति बुधवार को सिद्धू के अमृतसर स्थित आवास पर बनाई गई। तय हुआ कि न्योता देने के लिए कुलजीत नागरा के नेतृत्व में शिष्टमंडल को भेजा जाएगा। इस बात पर भी चर्चा हुई कि कैप्टन व सिद्धू के बीच की जमी बर्फ कैसे पिघले। फिर सहमति बनी कि समारोह से पहले पंजाब भवन में सभी विधायकों, सांसदों और वरिष्ठ नेताओं को इकट्ठा कर एकजुटता का संदेश दिया जाए। बाद में कैप्टन भी इसके लिए तैयार हो गए। सूत्रों के अनुसार चाय कार्यक्रम में कैप्टन व सिद्धू के आपसी मनमुटाव दूर हो सकते हैं।

पांच हजार लोगों के एकत्र होने की इजाजत मांगी: कोरोना के दिशानिर्देशों के कारण चंडीगढ़ में धारा 144 लागू है। इसे देखते हुए कांग्रेस ने समारोह के लिए चंडीगढ़ प्रशासन से 5000 लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत मांगी है। पंजाब के एडीजीपी ला एंड आर्डर ईश्वर सिंह ने समारोह स्थल का दौरा कर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया।

गोदियाल बने उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रीतम सिंह होंगे नेता प्रतिपक्ष

राज्य ब्यूरो, देहरादून

- हरीश रावत को चुनाव प्रचार कमेटी की कमान, आर्येंद्र शर्मा कोषाध्यक्ष

चुनावी साल में कांग्रेस ने पंजाब की तर्ज पर उत्तराखंड में भी प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव पर मुहर लगा दी। पूर्व विधायक गणेश गोदियाल प्रदेश कांग्रेस के नए मुखिया होंगे। प्रीतम सिंह को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर नेता प्रतिपक्ष की नई भूमिका सौंपी गई है। प्रो. जीत राम, भुवन कापड़ी, पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलकराज बेहड़ व पूर्व विधायक रंजीत रावत कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। आर्येंद्र शर्मा कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। पार्टी ने तीन सदस्यीय चुनाव प्रचार कमेटी की कमान पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस महासचिव हरीश रावत को सौंपी है।

उत्तराखंड में कांग्रेस विधायक दल के नए नेता और प्रदेश संगठन में बदलाव को लेकर इंतजार 26 दिन बाद खत्म हो गया। नए नेता प्रतिपक्ष के चयन के साथ प्रदेश अध्यक्ष को भी बदला गया है। बीती 13 जून को डा. इंदिरा हृदयेश का निधन होने से नेता प्रतिपक्ष का पद रिक्त हो गया था। 27 जून को नेता प्रतिपक्ष पद पर चयन को लेकर दिल्ली में बुलाई गई प्रदेश कांग्रेस विधायक दल की बैठक में संगठन में बदलाव की मांग भी उठी। दोनों पदों पर फैसला लेने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अधिकृत किया गया था।

बीती 12 व 13 जुलाई को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल समेत प्रदेश के कई नेताओं ने अलग-अलग कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की थी। ये मुलाकात निर्णायक साबित हुई। देर शाम कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने नई नियुक्तियों के संबंध में पार्टी हाईकमान का आदेश जारी कर दिया।

कांग्रेस ने प्रदेश में कोषाध्यक्ष की नियुक्ति भी कर दी। आगामी चुनाव की दृष्टि से यह अहम नियुक्ति की गई है। पार्टी ने चुनाव प्रचार कमेटी भी घोषित कर दी है। इसके अध्यक्ष हरीश रावत हैं, जबकि उपाध्यक्ष राज्यसभा सदस्य प्रदीप टम्टा और संयोजक पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल बनाए गए हैं।

उत्तराखंड में भू-कानून का विरोध, तेज हुई सियासत

राज्य ब्यूरो, देहरादून

- जन विरोध मुखर होता देख कांग्रेस मोर्चाबंदी में जुटी

उत्तराखंड में भू-कानून में संशोधन कर रियायत देने का विरोध शुरू होने के साथ ही सियासत भी तेज हो गई है। भूमि खरीद के नए रास्ते खुलने से उपजे असंतोष को भांपकर राजनीतिक दलों ने सरकार और सत्तारूढ़ दल भाजपा को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। इंटरनेट मीडिया में शुरू हुई मुहिम अब धरातल पर भी आकार लेने लगी है। कांग्रेस भी मोर्चाबंदी में जुट गई है।

20 साल में भू-कानून में तीन बड़े बदलाव किए जा चुके हैं। वर्ष 2017 में बदलाव के बाद नगर निकाय क्षेत्रों में शामिल किए गए ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन की खरीद-फरोख्त का रास्ता साफ हो गया है। शहरी निकाय क्षेत्रों में भूमि खरीद के लिए अनुमति लेने की जरूरत नहीं रह गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में भी भूमि खरीद की सीमा को विस्तारित किया जा चुका है। हालांकि सरकार ने भू-कानून को लचीला बनाने का यह कदम राज्य में पूंजी निवेश को ज्यादा से ज्यादा आमंत्रित करने के लिए उठाया है, लेकिन इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कानून में सख्त व्यवस्था नहीं होने को लेकर विरोध मुखर हो गया है।

सरकार के खिलाफ आवाज को हवा देने में जुटे विपक्षी दल: 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में विपक्षी दलों ने विरोध की इस आवाज को हवा देनी शुरू कर दी है। केदारनाथ से कांग्रेस विधायक मनोज रावत ने विधानसभा के भीतर भू-कानून का विरोध किया था। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और उत्तराखंड दौरे पर आए राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट भी भू-कानून के खिलाफ उठ रही आवाज को समर्थन देने का एलान कर चुके हैं।

रावत बोले-भू-कानून में बदलाव तकलीफदेह

हरीश रावत ने कहा कि राज्य में लीज पर भूमि देने के लिए भी स्क्रूटनी की जाती रही है। अधिनियम में बड़ा परिवर्तन कर भूमि की खरीद के लिए पूरा दरवाजा खोल दिया गया है। कोई भी जमीन खरीदे, कोई रोक-टोक नहीं है। रावत ने कहा कि हिमाचल के एक्ट में सुधार करते हुए कुछ बातों का समावेश कर भूमि सुधार के प्रश्न को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। वह सुनिश्चित करेंगे कि यह मुद्दा कांग्रेस के एजेंडे में रहे।

कर्मचारियों को आधे वेतन पर मिलेगी पांच साल की छुट्टी

नईदुनिया, भोपाल

बचत का नया फंडा

- मध्य प्रदेश में अवकाश की अवधि में व्यवसाय या निजी क्षेत्र में नौकरी की छूट मिलेगी
- योजना और वित्त विभाग ने प्रारंभिक प्रारूप किया तैयार

मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार कर्मचारियों को शासकीय सेवा में रहते हुए निजी काम या नौकरी का मौका देने की तैयारी कर रही है। इसके तहत कर्मचारी अधिकतम पांच साल की लंबी छुट्टी लेकर कोई भी काम कर सकेंगे। इस अवधि में उन्हें आधा वेतन भी मिलता रहेगा। इस व्यवस्था में उनकी वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी। यह कवायद सरकार का खर्च कुछ कम करने के लिए की जा रही है। अभी राज्य सरकार करीब 60 हजार करोड़ रुपये सालाना वेतन-भत्तों पर खर्च कर रही है। हालांकि, शिक्षक, डाक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस सहित ऐसे कई विभागों के कर्मचारी इसके दायरे में नहीं आएंगे, जिनकी सेवाएं अत्यावश्यक होती हैं।

गौरतलब है कि सरकार के खर्च को कम करने के लिए 2002 में दिग्विजय सरकार ने भी मध्य प्रदेश सिविल सेवाएं (फरलो) योजना शुरू की थी। यह योजना 2007 में भाजपा शासनकाल में बंद कर दी गई। करीब चार हजार कर्मचारियों ने इसका लाभ भी उठाया था। इसका फायदा यह रहा कि स्थापना व्यय कुछ कम हुआ।

कोरोना संकट की वजह से प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। इसे देखते हुए सरकार आय के स्रोत बढ़ाने के साथ खर्च कम करने की दिशा में काम कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सचिवालय ने वित्त विभाग से कर्मचारियों को अवकाश देकर दूसरा काम करने की अनुमति देने की योजना का खाका बनाकर प्रस्तुत करने के लिए कहा है। वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक प्रारूप तैयार है। यह वर्ष 2002 की फरलो योजना जैसा ही है। इसमें स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, स्कूल शिक्षा, तकनीक से जुड़े कर्मचारी और पुलिस कर्मचारियों को दायरे से बाहर रखा जाएगा।

प्रदेश सरकार की इस योजना में शामिल होने वाले कर्मचारियों को आधा वेतन तो मिलेगा पर वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा। वरिष्ठता भी प्रभावित नहीं होगी और पेंशन भी मिलेगी। अवकाश के दौरान यदि कर्मचारी का निधन हो जाता है तो स्वजन को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता पहले की तरह रहेगी। हालांकि कामकाज प्रभावित होने को लेकर अब तक कोई विशेष आकलन नहीं किया गया है। आवेदन के बाद भी इस पर विचार किया जा सकता है।

प्रदेश पर ढाई लाख करोड़ रुपये से अधिक कर्ज

मध्य प्रदेश सरकार पर अब ढाई लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज हो चुका है। पिछले साल कोरोना की विशेष परिस्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने लगभग साढ़े 14 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति दी थी। इसके माध्यम से अधिक ऋण लेकर प्रदेश सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित नहीं होने दिया था। इस बार भी यही रणनीति बनाई गई है।

03 सलाहकार समूहों का गठन किया है विमानन मंत्रालय ने। यह समूह कोरोना महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित विमानन क्षेत्र को उबारने और क्षमता बढ़ाने की योजनाओं पर रिपोर्ट देगा।

न्यूज गैलरी

अंतरजातीय विवाह करने पर ढाई लाख देने पर गांव में इंट्री

पूर्णिया : अंतरजातीय प्रेम विवाह पर ग्रामीणों के तुगलकी फरमान से एक बार फिर समाज का स्याह चेहरा सामने आया है। बिहार के पूर्णिया जिले के चंपानगर ओपी क्षेत्र के चरैया रहिका गांव के इस विवाहित जोड़े को ढाई लाख रुपये देने पर ही गांव में इंट्री का फरमान सुनाया गया है। इस स्थिति के चलते बीते एक साल से विवाहित जोड़ा गांव में प्रवेश नहीं कर सका है। अब बात जुर्माना नहीं देने पर घर-द्वार लूट लेने की धमकी तक पहुंच गई है। इस स्थिति में विवाहित जोड़े ने गुरुवार को पुलिस अधीक्षक से मिलकर उन्हें आवेदन सौंपा और न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस अधीक्षक ने चंपानगर ओपी पुलिस को इस मामले में आवश्यक निर्देश दिया गया है। (जासं)

हल्द्वानी में कैदी की मौत की होगी सीबीआइ जांच

नैनीताल : हाई कोर्ट ने काशीपुर (ऊधमसिंहनगर) के कैदी प्रवेश कुमार की हल्द्वानी जेल में न्यायिक अभिरक्षा में मौत की जांच गुरुवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) को सौंप दी। कोर्ट ने हल्द्वानी के तत्कालीन पुलिस क्षेत्राधिकारी व जेल के चार आरोपित बंदी रक्षकों का जिले से बाहर तबादला करने का आदेश भी पारित किया। जांच में लापरवाही पर उत्तराखंड सरकार से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) नैनीताल के तबादले का भी अनुरोध किया। दुष्कर्म के आरोपित प्रवेश कुमार की छह मार्च 2021 को हल्द्वानी जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्रवेश की पत्नी भारती ने बंदी रक्षकों पर हत्या का आरोप लगाया था। (जासं)

चिटफंड मामलों की जांच कर रहे दो अफसरों का तबादला

कोलकाता : बंगाल में बहुचर्चित सारधा, रोजवैली सहित कई चिटफंड मामलों की जांच में शामिल केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) के दो पुलिस अधीक्षक (एसपी) स्तर के अधिकारियों का अचानक तबादला कर दिया गया है। दोनों अधिकारी कोलकाता के साल्टलेक में सीजीओ कांप्लेक्स स्थित सीबीआइ कार्यालय में पदस्थापित थे। इन में एक एसपी अतिरिक्त प्रभार में हैं। (राब्यू)

जिस बस से जंतर-मंतर गए थे, उसी से लौटे किसान

कृषि कानूनों का विरोध ▸ प्रदर्शन स्थल पर चलाई किसान संसद, बेहद कड़ी रही पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ कई महीनों ने प्रदर्शन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने गुरुवार को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया। संसद भवन से कुछ दूरी पर स्थित इस जगह पर उन्होंने किसान संसद का आयोजन किया। शाम पांच बजे तक कार्यवाही चलाई जो आगे भी जारी रहेगी।

26 जनवरी को हुए उपद्रव से सबक लेते हुए सरकार ने पूरी एहतियात बरती। सुबह जिस बस से प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर पर लाए गए थे, शाम को उसी वापस सिंघु बार्डर पहुंचा दिया गया। एक दिन पहले बनी सहमति के मुताबिक 200 लोग सिंघु बार्डर से बसों में सवार होकर जंतर-मंतर पर पहुंचे। यहां उन्होंने किसान संसद चलाया। इसके लिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बनाए। पहले दिन मंडियों को खत्म करने का आरोप लगाते हुए चर्चा हुई। तीन चरण में हुई चर्चा में 45 प्रदर्शनकारियों ने अपनी राय रखी। यह चर्चा शुक्रवार को भी जारी रहेगी, फिर इसे लेकर प्रस्ताव पारित किया जाएगा। केरल के कांग्रेस, सीपीएम और आरएसपी के 23 सांसदों ने जंतर-मंतर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की।

संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं का कहना है कि उन्हें नौ अगस्त तक ही प्रदर्शन की अनुमति मिली है, लेकिन वे इसे आगे बढ़ाने की अपील करेंगे और 13 अगस्त तक प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन के लिए हर दिन छह मंडलीय सदस्य नियुक्त किए जाएंगे, इन्हीं में से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बनाया जाएगा। पहले दिन शिवकुमार कक्का, हनन मौला, रमिंद्र पटियाला, योगेंद्र यादव, मंजीत राय और हरमीत कालका को किसान संसद का स्पीकर व डिप्टी स्पीकर बनाया गया। 26 जुलाई व नौ अगस्त को प्रदर्शन का नेतृत्व महिलाएं करेंगी। प्रदर्शनकारियों ने जासूसी कराए जाने का अंदेशा जताया।

कोरोना नियमों का दिखा उल्लंघन: जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ीं। प्रदर्शनकारी बिना मास्क के बैठे नजर आए। न तो प्रदर्शनकारियों ने मास्क लगा रखा था, न ही उनके नेताओं ने शारीरिक दूरी के नियम का पालन किया। प्रदर्शनकारी पास-पास बैठकर खाना भी खा रहे थे।

लेखी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव: केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी को लेकर प्रदर्शनकारियों ने निंदा प्रस्ताव पारित किया। कहा कि उन्हें लेखी ने मवाली कहा है, जो निंदनीय है। कहा कि यदि हम मवाली हैं तो हमारे द्वारा उपजाए अनाज को खाना बंद कर देना चाहिए।

भारी संख्या में पुलिस बल तैनात: 26 जनवरी की घटना से सबक लेते हुए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। प्रदर्शन स्थल के साथ ही नई दिल्ली जिले में पांच हजार से अधिक जवानों की तैनाती की गई है। चार स्तरीय बैरिकेडिंग की गई है, जहां दिल्ली पुलिस के साथ ही सीआरपीएफ, सीआइएसएफ व आरपीएफ के दो हजार से अधिक जवान तैनात हैं। पहली पंक्ति में दिल्ली पुलिस व आरपीएफ की महिला कर्मियों की तैनाती की गई है।



कृषि सुधार कानूनों के विरोध में जंतर मंतर पर आयोजित किसान संसद में आंदोलनकारियों को संबोधित करते हुए भाकियू के प्रवक्ता राकेश टिकैत। संजय



कृषि सुधार कानूनों के विरोध में जंतर मंतर पर आयोजित किसान संसद के समाप्त होने के बाद बस से वापस लौटते प्रदर्शनकारी। संजय

महिला पत्रकार से अभद्रता

एक प्रदर्शनकारी ने एक टीवी चैनल की महिला पत्रकार के साथ अभद्रता की। इससे मीडिया कर्मियों व प्रदर्शनकारियों में कुछ देर तक झड़प भी हुई। हंगामे में एक मीडिया कर्मी घायल भी हो गया। पुलिस अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। अभद्रता करने वाले को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिसे शाम को छोड़ दिया गया।

अस्थायी कंट्रोल रूम, सीसीटीवी और वीडियोग्राफी से नजर

प्रदर्शनकारियों को भी सिंघु बार्डर से जंतर-मंतर तक स्काट करके लगा गया। चयनित सभी दो सौ प्रदर्शनकारियों को संयुक्त किसान मोर्चा ने पहचान पत्र दिया था। प्रदर्शन स्थल पर पुलिस ने सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। हर पल वीडियोग्राफी की जा रही है। प्रदर्शनस्थल पर ही अस्थायी कंट्रोल रूम भी बनाया गया है।

आठ माह बाद सरकार ने हमें किसान माना है। यह हमारी जीत है। हम संसद चलाना जानते हैं। संसद में जो लोग बैठे हैं, वे चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के, अगर वे हमारी आवाज नहीं उठाएंगे तो हम उनके संसदीय क्षेत्रों में जाकर आवाज उठाएंगे।
-राकेश टिकैत, प्रवक्ता, भारतीय किसान यूनियन

किसान संसद के जरिये हमने दिखा दिया है कि आंदोलन अब भी जीवंत है। हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। हालांकि, गणतंत्र दिवस की घटना को देखते हुए हमने कम संख्या में एकत्र होने का फैसला लिया है।
-शिव कुमार कक्का, नेता, संयुक्त किसान मोर्चा

आज दूसरे देशों में तीन कृषि कानूनों को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन भारत में यह चर्चा नहीं हो रही। भारत की संसद को भी यह चर्चा करनी चाहिए और इन्हें वापस लेना चाहिए।
-योगेंद्र यादव, नेता, संयुक्त किसान मोर्चा

सरकार खुले मन से किसान संगठनों से वार्ता को तैयार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कृषि सुधार के कानूनों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसान संगठनों से सरकार एक बार फिर बातचीत को तैयार है। जंतर-मंतर पर जहां आंदोलनकारी किसान संगठनों की किसान संसद लगी, वहीं संसद परिसर में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि उन्हें वार्ता में खुले मन से आना चाहिए। सरकार इसके लिए पूरी तरह तैयार है। अगर कृषि कानूनों में कोई आपत्तिजनक प्रविधान है तो सरकार उसके समाधान के लिए तैयार है। वैसे ये कानून किसानों के हित में हैं और फायदेमंद हैं। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन का रास्ता छोड़कर वार्ता के लिए आगे आएं।

कृषि कानूनों को लेकर लंबे समय से आंदोलन करने वाले किसान संगठनों की जिद इन कानूनों को रद करने की है, जबकि सरकार इन कानूनों की खामियों पर उनसे चर्चा करने को तैयार है। इस बारे में कई दौर की वार्ता पहले हो चुकी है। लेकिन किसान संगठनों की जिद के चलते वार्ता में इनके प्रविधानों पर कोई चर्चा ही नहीं हो सकी। इसके चलते कई महीनों से गतिरोध बना हुआ है। कृषि कानून विरोधी किसान संगठन दिल्ली की सीमाओं पर मोर्चा लगाकर आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान अपने आंदोलन को देशव्यापी बनाने की कोशिश भी की, लेकिन बात नहीं बनी। कृषि मंत्री तोमर ने गुरुवार को यहां बातचीत में स्पष्ट किया कि अगर किसान संगठनों के नेता कानूनों को लेकर बिंदुवार समस्याएं लेकर आएंगे तभी सरकार उनसे बात करेगी। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी।

कांग्रेस सांसदों ने संसद के बाहर किया विरोध प्रदर्शन

नई दिल्ली, प्रेट्र : कांग्रेस ने मंगलवार को केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को अपना समर्थन दिया और कांग्रेस के सांसदों ने कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत पार्टी के अन्य सांसद इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए।

संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के बाहर हुए इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के दोनों सदनों के सदस्यों ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। तख्तियां और होर्डिंग लिए हुए कांग्रेस सांसदों ने आंदोलनकारी किसानों और उनकी मांगों के समर्थन में भी नारे लगाए।



राहुल गांधी का पलटवार। फाइल फोटो

राहुल बोले, सब याद रखा जाएगा

समाचार एजेंसी आइएएनएस के अनुसार, राहुल गांधी ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान आक्सीजन संकट को लेकर केंद्र सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा। उन्होंने 'आक्सीजन शार्टेज' हैशटैग के साथ ट्वीट किया, सब याद रखा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें लोगों को आक्सीजन सिलेंडर की खोज करते देखा जा सकता है।

महाराष्ट्र में दो नदियां उफान पर, शहरों में घुसा पानी

आफत

राज्य ब्यूरो, मुंबई

महाराष्ट्र के तटवर्ती कोंकण क्षेत्र एवं पश्चिम महाराष्ट्र में बुधवार रात से गुरुवार सुबह तक हुई जोरदार बारिश से पूरा कोंकण जलमय हो गया है। चिपलूण शहर तो डूब सा गया। यहां 5,000 से अधिक लोग बाढ़ में फंसे हैं। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ व एसडीआरएफ के अलावा कोस्टगार्ड की भी मदद ली जा रही है। नौसेना को तैयार रहने के लिए कहा गया है।

बीती रात समुद्र तट से लगे कोंकण क्षेत्र, पश्चिम महाराष्ट्र का कोल्हापुर, पुणे, मुंबई के निकट कल्याण, पालघर एवं नासिक आदि क्षेत्रों में भारी बारिश हुई। पुणे एवं कोंकण के बीच स्थित पहाड़ी पर्यटन केंद्र महाबलेश्वर में 480 मिलीमीटर बारिश रिकार्ड की गई। कोल्हापुर की पंचगंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी। यही स्थिति कोंकण के चिपलूण शहर में हुई, जहां वाशिष्ठी नदी का जलस्तर काफी बढ़ जाने के कारण शहर में पानी घुस गया और कई इलाकों में घरों की पहली मंजिल तक को डुबा गया।

परिवहन निगम की बसों की दिखाई दे रही सिर्फ छत : बाढ़ की भयावहता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि चिपलूण के बस अड्डे में खड़ी राज्य परिवहन की बसें लगभग डूब गईं। सिर्फ उनकी छत नजर आ रही थी। कई कारें एवं हल्के वाहन वाशिष्ठी नदी के बहाव की दिशा में बहते दिखाई दे रहे थे। चिपलूण से पास से गुजरनेवाला मुंबई-गोवा हाईवे भी डूब गया और उसपर वाहनों का लंबा जाम लग गया।

09 ट्रेनों को बीच रास्ते में अलग-अलग जगहों पर रोकना पड़ा। कुछ को मार्ग बदलकर किया गया रवाना

17 घंटे तक फंसे रहे बीच रास्ते में यात्री। कोंकण रेलवे का दावा सभी सुरक्षित। की गई खाने-पीने की व्यवस्था



महाराष्ट्र में भारी बारिश के बाद गुरुवार को कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए। कोहलापुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालते म्यूनिसिपल कारपोरेशन के कर्मचारी। प्रेट्र

जहां-तहां रोकी गईं ट्रेनें, छह हजार से ज्यादा यात्री फंसे

समाचार एजेंसी प्रेट्र के अनुसार, भारी बारिश व नदियों में आई बाढ़ की वजह से महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में रेल सेवा निलंबित कर दी गई। इसके कारण कोंकण रेल मार्ग पर कम से कम नौ ट्रेनों को जहां-तहां रोकना या उनका मार्ग बदलना पड़ा और छह हजार से ज्यादा यात्री बीच रास्ते में फंस गए। कोंकण रेलवे ने बताया कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और उनके खाने-पीने की व्यवस्था की गई है। इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बाढ़ से बिगड़े हालात की समीक्षा की। मध्य रेलवे के कासरा घाट स्टेशन व सीएसएमटी के बीच 17 घंटे बाद रेल सेवा बहाल कर दी गई। उत्तर व पूर्वी भारत से आने-जाने वाली ट्रेनें कासरा घाट से होकर गुजरती हैं। लंबी दूरी की ट्रेनों के संचालन में अभी वक्त लगेगा। यात्रियों की मदद के लिए बसों का संचालन किया जा रहा है।

...तो इसलिए डूबा चिपलूण : कोंकण का व्यावसायिक केंद्र माना जानेवाला चिपलूण शहर चारों ओर पहाड़ियों से घिरा है। इसलिए, इसकी भौगोलिक स्थित एक कटोरे जैसी बन जाती है। पहाड़ियों से बरसात का पानी शहर की ओर ही आता है, जबकि निकासी का एकमात्र मार्ग वाशिष्ठी नदी ही बचती है। महाबलेश्वर से भी चिपलूण की सीधी दूरी सिर्फ 46 किलोमीटर है। इसका असर न सिर्फ चिपलूण, बल्कि कोंकण व रायगढ़ के अन्य क्षेत्रों में भी देखा गया। शिवसेना सांसद विनायक राउत ने मुख्यमंत्री से नौसेना की मदद लेने की अपील की है।

कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी

जेएनएन, नई दिल्ली : मौसम पूर्वानुमान जारी करने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट ने अगले कुछ दिनों में देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। विशेषतौर पर बिहार के कई जिलों में 26 से 29 जुलाई तक रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ, शुक्रवार को मध्य महाराष्ट्र के आसपास के हिस्सों, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के आसार हैं।

स्काईमेट का कहना है कि बंगाल की खाड़ी पर लगातार दो निम्न दबाव के क्षेत्र बन रहे हैं। पहला 23 जुलाई और दूसरा 26 जुलाई के आसपास। इससे नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र और बिहार के उत्तरी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। 27 को बारिश अपने पीक पर होगी और तेज बारिश का यह सिलसिला 29 तक बना रह सकता है। 29 के बाद बारिश धीमी तो होगी, लेकिन कुछ-कुछ अंतराल पर बारिश जारी रहने से बाढ़ का पानी जल्द कम होता नहीं दिख रहा।

भारतीय मौसम विभाग (आइएमडी) ने भी अगले दो से तीन दिन देश के पूर्वी एवं मध्य हिस्से में भारी बारिश का अनुमान जताया है।

देखते ही देखते कई फीट उठ गई जमीन

जागरण संवाददाता, करनाल

हरियाणा में करनाल जिले के निसिंग क्षेत्र में नर्दक नहर की पटरी के साथ लगते खेत में एक रोमांचक घटना देखने को मिली। दो दिन पहले यहां बारिश के पानी से भरे खेत में तेजी के साथ जमीन की परत उभरकर कई फीट ऊपर आ गई और एक बड़े टीलानुमा आकार में ढल गई। सारा पानी इसके नीचे समा गया। परत में काफी बड़ी दरारें भी साफ नजर आ रही हैं। आसपास के लोगों ने इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया। केंद्रीय मृदा लवणता एवं अनुसंधान संस्थान (सीएसएसआरआइ) के विशेषज्ञों ने संभावना जताई है कि खेत की जमीन में रेजिड्यू यानी किसी विशेष प्रकार के तत्व के अवशेषों की अधिकता के कारण मिथेन गैस बनने से यह स्थिति बन सकती है। संस्थान के निदेशक डा. पीसी शर्मा ने कहा कि घटनाक्रम की जांच के लिए एक टीम शुक्रवार को मौके पर जाएगी। तभी सही स्थिति साफ हो पाएगी। खेत के मालिक कुचपुरा निवासी नफे सिंह ने बताया कि करीब एक एकड़ खेत में धान की फसल लगाई थी। इससे पूर्व खोदाई के कारण जमीन की सतह काफी नीचे चली गई थी।



खेत में ऊपर उठी जमीन की परत और इसमें पड़ी दरारें। इंटरनेट मीडिया

दैनिक भास्कर समूह पर आयकर का छापा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

मीडिया से जुड़े दैनिक भास्कर समूह के विभिन्न शहरों में स्थित कार्यालयों पर गुरुवार को आयकर विभाग की छापेमारी की गई। सूत्रों के मुताबिक दैनिक भास्कर समूह के मुंबई, दिल्ली, भोपाल, इंदौर, जयपुर, कोरबा, नोएडा और अहमदाबाद स्थित कार्यालयों पर आयकर अधिकारियों ने छापे की कार्रवाई की। इस कार्रवाई के बाद विपक्षी पार्टियां सरकार पर काफी हमलावर दिखीं। ट्वीट के साथ संसद तक में भास्कर समूह पर छापेमारी के विरोध में हो-हल्ला मचा।

इस मामले में सरकार से पूछे जाने पर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 'एजेंसी अपना काम करती है। इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। पूरी जानकारी जरूर लेनी चाहिए।

कई बार जानकारी के अभाव में बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जो सत्य से परे होते हैं।' कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने जहां छापे को मीडिया का गला दबाने की कोशिश बताया वहीं सरकारी सूत्रों का दावा है कि एजेंसी ने विभिन्न विभागों के डाटा बेस का अध्ययन करने तथा बैंकिंग व दूसरी खास एनक्वायरी के बाद छापे डाले।

पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत नाजुक

जासं, लखनऊ : एसजीपीजीआइ (लखनऊ) में भर्ती उप्र के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत लगातार नाजुक बनी हुई है। अब वह खुद से आक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं। इसकी वजह से उनके फेफड़ों और खून में पर्याप्त आक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इससे फेफड़े, दिल, गुर्दा, लिवर पर दबाव बढ़ गया है। इसका असर दिमाग पर भी पड़ रहा है, जिसके चलते मंगलवार की रात डाक्टरों ने उनके गले में ट्यूब डालकर फेफड़ों को आक्सीजन देनी शुरू की। इसे इंट्यूबेट (मैकेनिकल वेंटिलेशन) कहते हैं। उनकी स्थिति के मद्देनजर गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष हृदयनरायण दीक्षित उनकी सेहत का हाल जानने पीजीआइ पहुंचे। पीजीआइ निदेशक डा.आरके धीमन ने बताया अभी भी हालत नाजुक बनी हुई है। कोई खास सुधार नहीं हो रहा है।

बदरी नाथ धाम में नमाज पढ़ने पर संतों में उबाल

संस, गोपेश्वर : बकरीद के मौके पर मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों द्वारा बदरी नाथ धाम में नमाज पढ़े जाने पर ज्योतिष एवं द्वारका-शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य एवं प्रतिनिधि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि यह सार्वजनिक किया जाना चाहिए कि नमाज पढ़ने के लिए किसने मंजूरी दी और किसके संरक्षण में यह सब हुआ।

प्रेस को जारी बयान में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि बदरी नाथ धाम की परंपराएं निरंतर टूट रही हैं और अब धाम में मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों द्वारा नमाज अदा की गई है। उन्होंने उत्तराखंड सरकार से मांग की है कि इस मामले में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

पन्ना राजघराने की महारानी जीतेश्वरी कुमारी गिरफ्तार



पन्ना राजघराने की महारानी जीतेश्वरी कुमारी को जेल ले जाती पुलिस। नईदुनिया

नईदुनिया, पन्ना : बेशकीमती हीरों व अकूत संपत्ति को लेकर लंबे समय से विवादों में घिरे मध्य प्रदेश के पन्ना राजघराने में गुरुवार को एक और काला अध्याय शामिल हो गया। राजमाता दिलहर कुमारी की शिकायत पर महारानी जीतेश्वरी कुमारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सीजेएम (मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी) कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। दिलहर कुमारी ने जीतेश्वरी व अन्य के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने की शिकायत की थी। कोतवाली पन्ना के टीआइ अरुण सोनी ने बताया कि 19 जून को राज मंदिर पैलेस में विवाद हुआ था। शिकायत के मुताबिक जीतेश्वरी कुमारी और उनके पति महाराज राघवेंद्र सिंह सहित छह लोगों ने पैलेस में राजमाता दिलहर कुमारी के क्षेत्र में घुसकर उन्हें अपशब्द कहे और धमकी दी थी। जीतेश्वरी कुमारी ने कहा कि षड्यंत्रपूर्वक फंसाया गया है।

पाक से आया 'सफेद जहर', पूर्व सैनिक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, जम्मू

जम्मू कश्मीर में आतंकवाद दम तोड़ रहा है। बौखलाया पाकिस्तान अब युवा पीढ़ी को नशे के गर्त में धकेलने की साजिश में जुटा है, लेकिन मुस्तैद सुरक्षाबल हर मंसूबे नाकाम बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने पाक से तस्करी कर लाई दो किलो हेरोइन बरामद कर एक पूर्व सैनिक सहित तीन तस्करों को गिरफ्तार किया। अफगानिस्तान में तैयार हेरोइन की पैकिंग पाकिस्तान में हुई है। तीनों आरोपितों के मोबाइल फोन को खंगाले जा रहे हैं। आरोपितों की पहचान खौड़ के पूर्व सैनिक बलबीर सिंह, कमल सिंह के अलावा नरेश कुमार निवासी अखनूर से पूछताछ जारी है।

एसएसपी एएनटीएफ विनय शर्मा ने वीरवार को पत्रकारों को बताया कि 19 जुलाई को उन्हें पुख्ता सूचना मिली कि अखनूर से खौड़ जा रही एक स्कूटी में हेरोइन की बड़ी खेप है। इस सूचना पर एएनटीएफ जवानों ने नाका लगा जांच शुरू कर दी। स्कूटी सवार युवक नरेश कुमार को जांच के लिए रोका। उसके पास से हेरोइन का एक पैकेट मिला। पैकेट में एक किलो हेरोइन थी। पैकेट में लिखा था कि हेरोइन अफगानिस्तान में तैयार हुई है। नरेश ने गहन पूछताछ के दौरान बताया कि हेरोइन का एक और पैकेट खौड़ की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पड़ा है। इस पैकेट को वहां से लाने की जिम्मेदारी पाकिस्तानी हैंडलर ने पूर्व सैनिक बलबीर सिंह और कमल सिंह को दी है। एएनटीएफ ने दोनों को दबोच उनकी निशानदेही से हेरोइन की बरामद की। चूंकि हेरोइन अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास पड़ी थी। इसलिए सेना की भी मदद ली गई।

इंटरपोल का लिया जाएगा सहारा : एएनटीएफ ने हेरोइन की तस्करी के आरोप में पकड़े गए नरेश कुमार, बलबीर सिंह और कमल सिंह के मोबाइल फोन नंबर से पाकिस्तान में बैठे हैंडलर के बारे में अहम जानकारियां जुटाई हैं। जिन पाकिस्तानी मोबाइल नंबरों से आरोपितों को एसएमएस भेजे हैं के बारे में पता लगा कर उनकी जानकारी इंटरपोल को दी जाएगी ताकि उन्हें पाक से गिरफ्तार कर भारत में लाया जा सके। हैंडलरों को भारत लाने के लिए अन्य अंतरराष्ट्रीय कानूनों का भी सहारा लिया जाएगा। सरहद पार से मादक पदार्थ भेजने वाले आरोपितों को पाक सेना का पूरा सरंक्षण है।

तारबंदी के पार से फेंकी गई थी हेरोइन : आरोपितों ने गहन पूछताछ में कुबूला है कि उनके पाकिस्तानी हैंडलर ने हेरोइन के पैकेट अंतरराष्ट्रीय सीमा पर लगी कंटीले तार के ऊपर से उछाल भारतीय सीमा में फेंके थे।

एलओसी पर दिखे तीन संदिग्ध

राज्य ब्यूरो, जम्मू : जम्मू संभाग में पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने की घटनाओं के बीच बुधवार-गुरुवार रात को जम्मू जिले के अखनूर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास छंब इलाके में तीन संदिग्ध देखे जाने से सुरक्षा एजेंसियां चौकन्ना हो गई हैं। पुलिस, सेना और अन्य सुरक्षाबल जम्मू जिले के इस सीमावर्ती इलाके के साथ राजौरी जिले के सुंदरबनी में भी तलाशी अभियान चला रहे हैं। तीनों संदिग्ध नाले से होते हुए सुंदरबनी की ओर जाते हुए बताए गए हैं। जोमगा के अशोक कुमार ने बताया कि वह रात करीब एक बजे क्षेत्र में निर्माण कार्य कर रही एक कंपनी की नाइट ड्यूटी पर था। उसने काले कपड़े पहने एक संदिग्ध को गांव की ओर जाते देखा था।

ट्विटर ने निजता नीति में किए कई बदलाव, 19 अगस्त से होंगे लागू

नई दिल्ली, जेएनएन : माइक्रोब्लागिंग साइट ट्विटर ने पिछले कुछ महीनों में कई नई सुविधाएं और सेवाएं विकसित की हैं। इन सुविधाओं और सेवाओं के संचालन के लिए कंपनी ने अपनी सेवा शर्तों व निजता नीति में भी कई बदलाव किए हैं, जो 19 अगस्त, 2021 से प्रभावी होंगे।

माइक्रोब्लागिंग प्लेटफार्म ने निजता नीतियों में बदलाव के संबंध में गत दिनों नए ब्लाग के जरिये बताया है। जिन सुविधाओं और सेवाओं में बदलाव किए गए हैं, उनमें ट्विटर स्पेसेज, ट्विटर ब्ल्यू व भुगतान आदि शामिल हैं। निजता नीति में बदलाव का प्राथमिक भाग ट्विटर स्पेसेज है। इसके जरिये ट्विटर यूजर आपस में आडियो संवाद कर सकते हैं। ट्विटर ने कहा है कि वह स्पेसेज में होने वाले संवाद का आडियो बनाता है। इसमें देखा जाता है कि कहीं नीतियों का उल्लंघन तो नहीं किया गया। साथ ही वह सुविधा में सुधार के लिए भी आडियो का उपयोग करता है। ट्विटर ने कहा है कि स्पेसेज पर होने वाले सभी संवाद सार्वजनिक हैं, इसलिए सूचनाओं की निजता का सवाल ही पैदा नहीं होता। नीति में एक अन्य बदलाव ट्विटर ब्ल्यू से संबंधित है।

वाट्सएप की नई निजता नीति के खिलाफ सुनवाई टली

जासं, नई दिल्ली : वाट्सएप की नई निजता नीति को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहते हुए सुनवाई 27 अगस्त तक स्थगित कर दी कि इन्हें तत्काल सुने जाने की जरूरत नहीं है। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि वाट्सएप ने साफ कर दिया है कि अधिनियम को अंतिम रूप दिए जाने तक वह अपना डाटा फेसबुक को ट्रांसफर नहीं करेगा।

लगातार दूसरे दिन बढ़े मामले, 24 घंटे में 2,224 नए केस

मौत को कम बताने संबंधी मीडिया रिपोर्टों को सरकार ने गलत बताया

जेएनएन, नई दिल्ली

देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 41,383 मामले सामने आए हैं। इसके चलते कुल संक्रमित लोगों की संख्या 3,12,57,720 हो गई है। इस बीच, लगातार दूसरे दिन सक्रिय मामलों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, गुरुवार को सक्रिय मामलों की संख्या 4,09,394 हो गई। इससे एक दिन पहले बुधवार को सक्रिय मामलों की संख्या 4,07,170 थी। इस तरह गुरुवार को सक्रिय मामलों की संख्या में 2,224 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे पहले बुधवार को सक्रिय मामलों में एक हजार से अधिक की वृद्धि हुई थी। मंत्रालय के अनुसार, इस बीमारी से देश में अब तक 3,04,29,339 लोग ठीक भी हो चुके हैं। हालांकि तीसरी लहर को लेकर चिंता बनी हुई है।

दूसरी तरफ, कोरोना से मौत को कम बताने संबंधी मीडिया रिपोर्टों का खंडन करते हुए सरकार ने कहा है कि ऐसा लगता है कि हर मौत का कारण कोरोना को मान लिया गया है। यह तथ्यों पर आधारित नहीं है और पूरी तरह गलत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत में मजबूत और कानून-आधारित मृत्यु रजिस्ट्रेशन प्रणाली है। इसे देखते हुए कुछ मामले संक्रामक रोग और उसके प्रबंधन के सिद्धांतों के अनुसार ज्ञात नहीं हो सकते हैं। लेकिन बड़ी संख्या में इसका पता नहीं चलने की संभावना नहीं है।


मुंबई में दादर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की कोरोना जांच के लिए एंटीजेन टेस्ट किए गए। मिड-डे

देश में कोरोना की स्थिति

24 घंटे में नए मामले	41,383
कुल सक्रिय मामले	4,09,394
24 घंटे में टीकाकरण	50.07 लाख
कुल टीकाकरण	41.78 करोड़

गुरुवार सुबह आठ बजे तक कोरोना की स्थिति

नए मामले	41,383
कुल मामले	3,12,57,720
सक्रिय मामले	4,09,394
मौतें (24 घंटे में)	507
कुल मौतें	4,18,987
ठीक होने की दर	97.35 फीसद
मृत्यु दर	1.34 फीसद
पाजिटिविटी दर	2.41 फीसद
सा. पाजिटिविटी दर	2.12 फीसद
जांचें (बुधवार)	17,18,439
कुल जांचें (बुधवार)	45,09,11,712

खतरनाक साबित हो रही यात्रा, 60 फीसद संक्रमितों में ट्रैवल हिस्ट्री

अतुल वासिंग, बिलासपुर: कोरोना संक्रमण की रफ्तार भले ही कम हो गई है, लेकिन अभी दूसरे शहर व राज्य जाकर सैर सपाटा करना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग की ओर से नए कोरोना मरीजों की जांच में करीब 60 फीसद की ट्रैवल हिस्ट्री मिली है। यह सभी हाल फिलहाल किसी दूसरे शहर व राज्य से आए हैं।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डा. प्रमोद महाजन ने बताया कि जिले में जुलाई में 21 तारीख तक 239 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसमें से 143 मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री है। इसने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। गैरजरूरी यात्रा करने वाले लोग जोखिम बढ़ा रहे हैं। सफर के दौरान ऐसे लोग कोरोना वायरस के संपर्क में आ रहे हैं और वायरस को लेकर जिले में प्रवेश कर रहे हैं। इनके संपर्क में आने से जिले के 96 मरीज संक्रमित हुए हैं। **महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश व केरल से लौटे हैं ज्यादा संक्रमित:** रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य विभाग की टीम रोजाना 400 से 500 यात्रियों की जांच कर रही है। इसमें से औसतन चार से पांच यात्री संक्रमित मिलते हैं। 11 जुलाई से अब तक रेलवे स्टेशन में 43 कोरोना पाजिटिव मरीज की पहचान की गई है। ज्यादातर महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश व केरल से आए हैं।

कुंभ के कोरोना टेस्टिंग फर्जीवाड़े में पहली गिरफ्तारी, खातों सहित 31 लाख रुपये फ्रीज

जागरण संवाददाता, हरिद्वार

कुंभ के कोरोना टेस्टिंग फर्जीवाड़े में विशेष जांच टीम (एसआइटी) ने हरियाणा के भिवानी के एक लैब संचालक को गिरफ्तार किया है। इस प्रकरण में यह पहली गिरफ्तारी है। पुलिस ने अदालत से आरोपित का तीन का रिमांड भी हासिल कर लिया। फर्जीवाड़े में नामजद मेसर्स मैक्स कारपोरेट सर्विसेज, नई दिल्ली के साझीदारों शरत पंत और मल्लिका पंत के खिलाफ भी एसआइटी को सुबूत मिले हैं। फर्म के पांच बैंक खातों सहित कुल सात खातों में 31.41 लाख रुपये फ्रीज कर दिए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) सेंथिल अवूदई कृष्णराज एस ने इसकी पुष्टि की।

शरत पंत व मल्लिका पंत ने अपने स्तर पर ही डेलफिया लैब को टेस्टिंग में शामिल कर लिया था। जबकि उनका अनुबंध हिसार की नलवा लैबोरेटरी और नई दिल्ली की डा. लालचंदानी लैब से था। हरिद्वार कुंभ में जिन दो दर्जन फर्मों को कोरोना टेस्टिंग का ठेका दिया गया है, उनमें मैक्स कारपोरेट सर्विसेज भी है। करीब सवा महीने पहले कोरोना फर्जीवाड़ा सामने आया था। इस संबंध में हरिद्वार के मुख्य चिकित्साधिकारी (सीएमओ) डा. शंभू कुमार झा ने 17 जून को शहर कोतवाली में मैक्स कार्पोरेट सर्विसेज दिल्ली, नलवा लैब हिसार, हरियाणा व डा. लालचंदानी लैब, दिल्ली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।


कुंभ कोरोना टेस्टिंग फर्जीवाड़े में गिरफ्तार लैब संचालक आशीष वशिष्ठ। जागरण

विवेचनाधिकारी राजेश साह ने एसआइटी के साथ मिलकर इस मामले की पड़ताल की। छानबीन में सामने आया कि शरत पंत व उसकी पत्नी मल्लिका पंत ने कुंभ मेला स्वास्थ्य अधिकारी को गुमराह करते हुए नलवा लैब हिसार और लालचंदानी लैब दिल्ली के साथ किए गए एक एमओयू के आधार पर कुंभ मेले में कोरोना टेस्टिंग का ठेका लिया। इसके बाद उन्होंने आपराधिक षडयंत्र रचकर हरियाणा के भिवानी की डेलफिया लैब को भी ठेके में शामिल कर लिया। जबकि यह लैब भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) से कोरोना टेस्ट के लिए अधिकृत भी नहीं थी। स्वास्थ्य विभाग के साथ हुए अनुबंध में भी यह लैब शामिल नहीं थी। इस लैब को आशीष वशिष्ठ संचालित करता है।

विवेचनाअधिकारी के अनुसार जांच में सामने आया कि शरत पंत व मल्लिका पंत के कहने पर आशीष वशिष्ठ ने अपनी लैब और जगजीतपुर, हरिद्वार की एक संस्था से अकुशल कर्मचारियों से टेस्टिंग कराई। इस दौरान उसने लगभग 1.10 लाख टेस्ट करना दर्शाए। इनमें अधिकांश टेस्ट फर्जी दिखाए गए, उसने इन्हें आइसीएमआर पोर्टल पर अपलोड भी किया। उन्होंने बताया कि गुरुवार को एसआइटी ने आरोपित आशीष वशिष्ठ निवासी ग्राम बधाना, थाना दुझाना जिला झज्जर हरियाणा को गिरफ्तार कर लिया। उससे लैपटाप व अन्य दस्तावेज बरामद कराने के लिए कोर्ट से तीन दिन का रिमांड भी हासिल कर लिया।

चार करोड़ लेने के लिए बनाए फर्जी बिल: पड़ताल में सामने आया है कि आशीष वशिष्ठ ने कोरोना टेस्टिंग के एवज में करीब चार करोड़ रुपये हासिल करने के लिए नलवा लैब हिसार से फर्जी बिल तैयार कर शरत पंत व मल्लिका पंत को उपलब्ध कराए।

दोनों आंखें निकालीं, पर नहीं बची जान, मरीज की मौत

जासं, अमृतसर

- गुरदासपुर का रहने वाला था मरीज, आपरेशन के बीस दिन बाद दम तोड़ा
- आंखों व साइनस की हड्डी रिमूव करने के बाद भी दिमाग तक पहुंच गया था फंगस

ब्लैक फंगस ने एक इंसान की पहले आंखों की रोशनी और फिर जिंदगी ही छीन ली। मृतक की पहचान गुरदासपुर के गांव ठीकरीवाल के रहने वाले 53 वर्षीय रशपाल सिंह के रूप में हुई है। रशपाल सिंह पिछले दिनों ब्लैक फंगस की चपेट में आए थे। इस कारण उनकी दोनों आंखें, नाक और आंखों के बीच की साइनस हड्डी भी निकालनी पड़ी थी। इसी बीच फंगस उनके दिमाग तक पहुंच गया और गुरुवार सुबह गुरु नानक देव अस्पताल में उनकी मौत हो गई।

तरसेम सिंह के अनुसार जून में उनके भाई रशपाल का शुगर लेवल काफी बढ़ गया था। उन्हें गुरदासपुर के एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया। डाक्टर ने जनेऊ होने की पुष्टि की और उपचार शुरू कर दिया। रशपाल की हालत बिगड़ती जा रही थी। फिर ईएनटी डाक्टर से जांच करवाई तो उन्होंने कहा कि इन्हें ब्लैक फंगस है। इसलिए अमृतसर स्थित गुरु नानक देव अस्पताल ले जाएं। सात जुलाई को वह रशपाल को यहां ले आए। जीएनडीएच के डाक्टरों ने भी ब्लैक फंगस की पुष्टि की। यह उनकी आंखों व साइनस में फैल चुका था। लिहाजा आंखें निकालने के सिवाय और विकल्प न था। बीस दिन पूर्व डाक्टरों ने उनकी दोनों आंखें और साइनस की हड्डी निकाल दी। रशपाल की जिंदगी में बेशक अंधेरा हो गया था, पर वह इस बात से संतुष्ट थे कि उनकी जान बच गई। इसी बीच ब्लैक फंगस उनके दिमाग में पहुंचने लगा। डाक्टरों ने दवाएं देकर इसे रोकने का प्रयास किया, पर सफल नहीं हो पाए।

आइआइटी के शोध से बढ़ी कोरोना की दवा बनाने की उम्मीद

जागरण विशेष

कानपुर में विज्ञानियों को मानव शरीर में मौजूद ब्रैडीकिनिन और एंजियोटेंसिन प्रोटीन की सिग्नलिंग में मिली सफलता

शशांक शेखर भारद्वाज • कानपुर

कोरोना के खिलाफ जंग के बीच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) कानपुर के एक शोध की सफलता ने महामारी पर जीत पाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। वहां के विशेषज्ञ शरीर में मौजूद 'जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स' ब्रैडीकिनिन और एंजियोटेंसिन की सिग्नलिंग (कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन से दूसरे प्रोटीन को संदेश देना या रासायनिक परिवर्तन करना) कराने में सफल हुए हैं। इसके आधार पर गंभीर कोरोना संक्रमितों के लिए न्यूनतम साइड इफेक्ट वाली सटीक दवा बनाई जा सकती है, जो इन रिसेप्टर्स को स्वीकार होगी और बीमारी पर कारगर होगी।

आइआइटी के बायोलाजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग विभाग के प्रो. अरुण शुक्ला के निर्देशन में डा. मिटू वैद्य ने यह शोध किया है। इसमें ब्रैडीकिनिन और एंजियोटेंसिन का पेप्टाइड (हार्मोन) से मिलान कराया गया। इससे कोशिकाओं में मौजूद प्रोटीन ने दूसरे प्रोटीन को संदेश दिया। शोध के परिणाम के आधार पर डाक्टर संक्रमितों की गंभीरता का पहले ही पता लगाकर समय पर इलाज कर सकेंगे। प्रो. शुक्ला के मुताबिक कुछ दवा कंपनियों से बात चल रही है। जो इस तकनीक का इस्तेमाल कर जल्द परीक्षण शुरू कर सकती हैं। दवा जल्द आएगी तो लोगों का जीवन सुरक्षित होगा।

रिसेप्टर का कोरोना में प्रभाव: शरीर में कोशिकाएं रिसेप्टर के माध्यम से बदलाव को महसूस करती हैं। रिसेप्टर के बड़े समूह को जीपीसीआर कहते हैं। इसकी सिग्नलिंग से न्यूनतम साइड-इफेक्ट वाली दवाएं बनाने में मदद मिलती है। कोरोना वायरस एसीई2 रिसेप्टर के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है, जो नाक, गला, फेफड़े, दिल और किडनी की सतह पर प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है।

फेफड़ों में द्रव से होती परेशानी: भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (आइएनएसए) युवा वैज्ञानिक अवार्ड से सम्मानित डा. वैद्य के अनुसार, कोरोना मरीजों में ब्रैडीकिनिन स्टार्म की समस्या रहती है, जिससे फेफड़ों में द्रव्य जमा हो जाता है। सांस फूलने लगती है। यही स्थिति घातक हो जाती है। शोध पर जीएसवीएम मेडिकल कालेज के मेडिसिन विभाग के प्रो. प्रेम सिंह का कहना है कि दवा की खोज के लिए तकनीक कारगर हो सकती है। इसके जरिए मानव जीवन की रक्षा होगी।


आइआइटी के प्रो. अरुण शुक्ला • जागरण

कोरोना से अंगों को ऐसे होता है नुकसान

कोरोना वायरस का हमला होते ही प्रोटीन में सिग्नलिंग जरूरत से अधिक तेज हो जाती है। कोशिकाएं मरने लगती हैं। फेफड़े की कोशिकाएं प्रभावित होते ही आक्सीजन लेवल नीचे गिरने लगता है। यह स्थिति फेफड़े के साथ दिल, गुर्दे, लिवर, दिमाग आदि को नुकसान पहुंचा सकती है।

वेस्टर्न ब्लोटिंग तकनीक का इस्तेमाल

डा. मिटू वैद्य ने बताया कि वेस्टर्न ब्लोटिंग तकनीक प्रोटीन को अलग करने और पहचानने में इस्तेमाल होती है। कोशिकाओं से प्रोटीन निकलने के बाद खास तरह के द्रव में चलाया जाता है। बड़े आकार के प्रोटीन ऊपर और छोटे नीचे हो जाते हैं। अब इन्हें मेंबरेन (झिल्ली) में ट्रांसफर कर दिया जाता है। मेंबरेन में एंटीबाडी डाल दी जाती है। एंटीबाडी डालते ही यह चमकने लगता है। जो ज्यादा चमकता है, उसकी सिग्नलिंग उतनी ज्यादा होती है और उसी आधार पर दवा ज्यादा कारगर होने का प्रमाण मिलता है।


प्रयोगशाला में डा. मिटू वैद्य • जागरण

इस खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए स्कैन करें

राष्ट्रीय फलक

पूर्व छात्रों ने आइआइटी बांबे को भेजे पांच करोड़ डालर

वाशिंगटन, प्रेट्र: अमेरिका में 25 साल पहले स्थापित आइआइटी बांबे के पूर्व छात्रों की संस्था ने अपने पुराने संस्थान को 5 करोड़ डालर (करीब 370 करोड़ रुपये) का दान भेजा है। यह धनराशि अमेरिका की आइआइटी बांबे हेरिटेज फाउंडेशन (आइआइटीबीएचएफ) के 3300 सदस्यों से इकट्ठा की गई है। अमेरिका में रहने वाले सभी पूर्व छात्र इस संस्था के सदस्य हैं। संस्था के 19 जुलाई को 25 साल पूरे होने पर वर्चुअल कार्यक्रम में धनराशि को सौंपा गया। कार्यक्रम में सभी पूर्व छात्र उपस्थित रहे। इस धनराशि से आइआइटी बांबे में शोध-अनुसंधान के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। आइआइटीबी हेरिटेज फाउंडेशन के अध्यक्ष डीसी अग्रवाल ने कहा कि पूर्व छात्रों ने अमेरिका में आइआइटी बांबे को एक ब्रांड के रूप में स्थापित किया है। 575 स्कालरशिप दी हैं इससे पांच हजार छात्रों को लाभ मिला।

झारखंड हाई कोर्ट ने कहा, कोरोना काल में पैसे की उगाही कर रहे अस्पताल

राज्य ब्यूरो, रांची

झारखंड हाई कोर्ट में ब्लैक फंगस मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई। अदालत ने मरीज उषा देवी की मौत पर कड़ी नाराजगी जताते हुए राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) निदेशक को फटकार लगाई और कहा कि पीड़िता का देरी से इलाज शुरू किया गया। इसके चलते उसकी मौत हो गई। इस मामले में चिकित्सकों ने अनदेखी की है। अदालत ने कहा कि जब महिला एक महीने से रिम्स में भर्ती थी तो उसका आपरेशन पहले क्यों नहीं किया। अदालत ने टिप्पणी की, कोरोना काल में निजी अस्पताल सेवा के बजाय पैसा कमाने की मशीन बन गए हैं। उनमें अब संवेदना ही नहीं रही है। कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज में नए चिकित्सकों को नैतिकता का पाठ पढ़ाए जाने की जरूरत है।

अदालत ने पीड़िता के मौत मामले में रिम्स निदेशक से जांच रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने कहा कि रिम्स निदेशक अपनी टीम के साथ इस मामले की जांच करें और रिपोर्ट दाखिल करें कि आखिर किस वजह से महिला की मौत हुई है। राज्य सरकार को सभी जिला अस्पतालों में फंगस से निपटने के लिए प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

रिम्स निदेशक को उपस्थित होने का दिया निर्देश : इस दौरान रिम्स की ओर से किसी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने पर अदालत ने तुरंत रिम्स निदेशक को वीसी के जरिए जुड़ने का आदेश दिया। कुछ देर बाद रिम्स निदेशक वीसी से जुड़कर अदालत में हाजिर हुए। अदालत ने उनसे पूछा कि ब्लैक फंगस की पीड़ित महिला का क्या हुआ। रिम्स निदेशक ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद तीन सर्जनों की निगरानी में सर्जरी हुई। महिला की तबीयत खराब होने पर उसे आइसीयू में भर्ती कराया गया। लेकिन ब्लड प्रेशर और शुगर नियंत्रित नहीं होने की वजह से उनकी मौत हो गई।

स्वतंत्र एजेंसी से कराना चाहते हैं जांच

अदालत ने कहा हम इस मामले की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराना चाहते हैं। रिम्स एक सरकारी संस्था है, उसमें इतनी बड़ी लापरवाही कैसे की जा सकती है। मरीजों के परिजनों को इस बात की जानकारी लेने का पूरा हक है कि चिकित्सक मरीज का कैसे इलाज कर रहे हैं। उन्हें मरीजों के स्वजन से अच्छा बर्ताव करना चाहिए। रिम्स निदेशक ने कोर्ट की बातों से सहमति जताई और कहा कि जांच की जाएगी।

बाहरी राज्यों के कांवड़ियों को टैंकर से गंगाजल उपलब्ध कराएगा उत्तराखंड

जासं, हरिद्वार : श्रावण मास में कांवड़ यात्रा के स्थगन के बाद उत्तराखंड बाहरी राज्यों के निवासियों की धार्मिक परंपराओं के पालन को हरिद्वार से उनकी आवश्यकता के मुताबिक टैंकर के माध्यम से गंगाजल भेजा जाएगा।

गुरुवार को जिलाधिकारी हरिद्वार सी रविशंकर ने बताया कि राज्य सरकार ने कांवड़ मेला-2021 के दृष्टिगत कांवड़ यात्रियों की सुविधा को यह निर्देश दिया है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, यमुनानगर, करनाल में टैंकरों के माध्यम से गंगाजल उपलब्ध कराया जाएगा। उपरोक्त सभी जगहों के जिला मजिस्ट्रेट, उपायुक्त से गंगाजल वितरित किए जाने के लिए स्थान और गंगाजल की जरूरत बताने का आग्रह किया गया है।

हिमाचल के कद्दावर पूर्व मंत्री पर बहू ने लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोप

जागरण संवाददाता, मंडी

- अनिल शर्मा ने बहू को भेजा था वसूली का नोटिस, बहू ने आरोप लगाकर इंटरनेट मीडिया पोस्ट हटाई

हिमाचल प्रदेश के कद्दावर राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले व सूबे के पूर्व ऊर्जा मंत्री एवं सदर विधायक अनिल शर्मा पर उनकी बड़ी बहू राधिका गंभीर ने दहेज प्रताड़ना व घर से निकालने का आरोप लगाया है। राधिका गंभीर ने ससुराल पक्ष से सभी रिश्ते खत्म करने का एलान कर दिया। ससुर को पैसे व सत्ता का भूखा बताया। अनिल शर्मा पर पैसे की खातिर अपने पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम को घर से निकालने का भी आरोप लगाया। हालांकि राधिका ने इस मामले में पुलिस में लिखित शिकायत नहीं दी है। इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट शेयर कर राधिका गंभीर ने ये आरोप लगाए हैं। राधिका ने बाद में पोस्ट हटा दी।

यह है विवाद का कारण: मंडी शहर में द रीजेंट पाम्स होटल संचालित करने वाली कंपनी के निदेशक अनिल शर्मा व उनका बड़ा बेटा आश्रय शर्मा हैं। बहू राधिका गंभीर को भेजे नोटिस में अनिल शर्मा का कहना है कि होटल में सैलून चलाने के लिए राधिका ने करार किया था। सैलून तैयार करने के लिए अनिल शर्मा के बेटे आश्रय शर्मा ने 24 लाख खर्च किए थे। यह पैसा उन्होंने आश्रय शर्मा को अपने यूको बैंक के खाते से ट्रांसफर किया था। 65,000 रुपये मासिक किराये के साथ बिजली-पानी का बिल अदा करने की बात हुई थी। होटल की कैशबुक की जांच करने पर पता चला कि किराये का एक पैसा जमा नहीं हुआ। 15 जुलाई को निदेशक मंडल की बैठक में राधिका को नोटिस देने का निर्णय लिया था। 33 माह का किराया 21.45 लाख रुपये जमा करवाने को कहा गया है।

जब आजाद के अस्थिकलश से चुटकी भर राख लेने को उमड़ पड़े थे लोग

अमलेंदु त्रिपाठी, प्रयागराज

आजादी की लड़ाई में जीवन की आहुति देने वाले चंद्रशेखर आजाद का बलिदान 90 साल बाद भी युवाओं को देश के लिए मर मिटने की प्रेरणा देता है। आजाद की शहादत से उस समय हर कोई आहत था। सभी चाहते थे कि आजादी के इस दीवाने का अंतिम संस्कार विधि विधान से हो। कुछ कांग्रेसी नेता असहयोग कर रहे थे पर आम जनमानस ने पूरा प्यार लुटाया। सभी की आंखें नम थीं। प्रयागराज (तब इलाहाबाद) में उनके अस्थिकलश से एक चुटकी राख लेने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था।

आजाद की चुस्ती फुर्ती ने उन्हें हमजोलियों में 'क्विक सिल्वर' की उपाधि दिलाई थी। कुशल नेतृत्व क्षमता, चतुर्मुखी निरीक्षण-शक्ति, सावधानी और तत्काल उपयुक्त काम करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति उन्हें खास बनाती थी। आज उनकी जन्मतिथि (23 जुलाई) है और देश उन्हें याद कर रहा है। आजाद का कथन था, 'बलं वाव भूयोअपि ह शतं विज्ञानवतामेको बलवानाकम्पयते' अर्थात बलशाली बनो, एक बलशाली सौ विद्वानों को कंपा देता है।

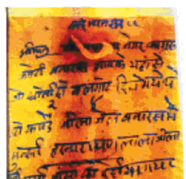

शहीद चन्द्रशेखर आजाद पार्क स्थित इलाहाबाद संग्रहालय में शहीद चंद्रशेखर आजाद की मौत की संरक्षित तस्वीर। साभार- संग्रहालय

प्रतापगढ़ से भी रहा है जुड़ाव

आजाद का कौशांबी और प्रतापगढ़ से भी गहरा नाता रहा। प्रतापगढ़ में सराय मतुई नमक शायर गांव में मथुरा प्रसाद सिंह की वह हवेली आज भी है, जहां आजाद साथियों के साथ विस्फोटक बनाते थे और प्रिंटिंग प्रेस चलाते थे। यह स्थान सई नदी के करीब है। जब भी पुलिस वाले उनकी भनक लगने पर पहुंचते, वह नदी में तैरकर निकल जाते।

अस्थिकलश यात्रा में जुटी भीड़

पोस्टमार्टम के बाद रसूलाबाद घाट पर आजाद की अंत्येष्टि हुई तो चिता की राख सहेज ली गई। चौक स्थित अभ्युदय प्रेस से अगले दिन शुरू हुई अस्थिकलश यात्रा पुरुषोत्तम दास पार्क में सभा के साथ खत्म हुई। सुधीर विद्यार्थी की पुस्तक अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद में उल्लेख है कि अस्थि कलश पार्क में रखे जाने पर सभा शुरू होते ही क्रांतिकारी शचींद्रनाथ सान्याल की पत्नी प्रतिभा सान्याल साक्षात दुर्गा के रूप में नजर आईं। चंद शब्द बोले। कहा, खुदीराम बोस की भस्म को लोगों ने ताबीज में रखकर अपने बच्चों को पहनाया था ताकि उनके बच्चे भी बहादुर देशभक्त बनें। मैं उसी भावना से भाई आजाद के अस्थियों की चुटकी भर राख लेने आई हूं। चंद पलों में अस्थि कलश में रखी राख नहीं बची। बड़ी मुश्किल से कुछ अंश काशी ले जाने के लिए सहेजा गया।


शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क स्थित इलाहाबाद संग्रहालय में शहीद चंद्रशेखर आजाद द्वारा लिखा गया पत्र। साभार- संग्रहालय


इलाहाबाद संग्रहालय में शहीद चन्द्रशेखर आजाद की पिस्टल। साभार- संग्रहालय


शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क स्थित इलाहाबाद संग्रहालय में शहीद चंद्रशेखर की युवावस्था की संरक्षित तस्वीर। साभार- संग्रहालय

चंदशेखर आजाद पार्क है बलिदान का गवाह

प्रयागराज के चंद्रशेखर आजाद पार्क की उम्र करीब 150 साल है और इसका फैलाव 133 एकड़ में है। 27 फरवरी 1931 की सुबह इसने अपने वीर सपूत की दिलेरी और बलिदान भी देखा। कालांतर में इसका नाम अल्फ्रेड पार्क से चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया गया। यहां स्थापित संग्रहालय में आजाद की पिस्तौल संरक्षित है। पार्क में गाथिक शैली में बनी पब्लिक लाइब्रेरी में ब्रिटिश युग के महत्वपूर्ण दस्तावेज संरक्षित हैं। नार्थ वेस्टर्न प्राविंसेज एंड अवध लेजिस्लेटिव काउंसिल की पहली बैठक आठ जनवरी 1887 को यहीं हुई थी।

शहीद स्थली पर जाकर रोई थीं मां

उन दिनों एक पत्रिका निकलती थी कर्मयोगी और अभ्युदय। घंटाघर के पास उसके कार्यालय में वह बदले नाम और भेष में रहते थे। किसी से मिलने या मंत्रणा करने प्रायः अल्फ्रेड पार्क आते थे। इलाहाबाद केंद्रीय विवि के मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग के हेरम्ब चतुर्वेदी बताते हैं कि वह उत्साह और जोश से लबरेज नवयुवकों से मिलते थे तो तमाम प्रबुद्ध लोगों से भी संबंध थे। मददगारों की सूची में एक और प्रमुख नाम था मोतीलाल नेहरू का। आजाद के बलिदान के बाद उनकी मां शहीद स्थल पर गईं और भाव विभोर होकर खूब रोईं थीं।

अनुसूचित जाति के युवक की जबरन दाढ़ी-मूंछ काटी

जागरण संवाददाता, सहारनपुर : उप्र के सहारनपुर के गांव शिमलाना में अनुसूचित जाति के एक युवक की जबरन दाढ़ी-मूंछ काट दी गई। इसका वीडियो भी वायरल हो गया। भीम आर्मी के सदस्यों ने पहले थाने पर तहरीर दी और फिर एसपी देहात के आफिस में ज्ञापन दिया। पंचायत भी हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। गुरुवार देर शाम पीड़ित की तहरीर पर सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

रजत अनुसूचित जाति से है। रजत का आरोप है कि जान पहचान के ही ठाकुर समाज के कुछ युवक उसे जबरन सैलून पर ले गए और उसकी जबरन दाढ़ी और मूंछ कटवा दी। आरोप है कि दाढ़ी-मूंछ न कटवाने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई। इस दौरान एक युवक ने वीडियो बना लिया। आरोपितों ने इसे फेसबुक पर अपलोड कर दिया। वीडियो वायरल होने पर गांव में पंचायत हुई, जिसमें माफी मांगने तक की बात आई, लेकिन बात नहीं बनी। एसपी देहात अतुल कुमार शर्मा ने बताया कि नीरज, सत्यम, मोहकम, रूपांतु, मोंटी राणा, संदीप व राजेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

निवेशकों की संपत्ति 2.93 लाख करोड़ रुपये बढ़ी

नई दिल्ली : तीन कारोबारी सत्रों की गिरावट के बाद गुरुवार को शेयर बाजारों में आई तेजी से निवेशकों की संपत्ति में एक ही दिन में 2,93,054.25 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ। इसके बाद बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 2,33,94,917.25 करोड़ रुपये पर जा पहुंचा। दिन के कारोबार में बीएसई का 30-शेयरों वाला प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 638.70 अंक मजबूत हुआ। बीएसई के मिडकैप व स्मालकैप में 1.52 फीसद तक का उछाल देखा गया। (प्रेट्र)



हम आयात पर निर्भरता घटाने के पक्षधर रहे हैं। स्पेशलिटी स्टील के लिए पीएलआइ की घोषणा से सेक्टर को बड़ा लाभ होगा।
– टीवी नरेंद्रन
एमडी, टाटा स्टील

सेंसेक्स	निफ्टी	सोना (प्रति दस ग्राम)	चांदी (प्रति किलोग्राम)	डॉलर	क्रूड (ब्रेंट) (प्रति बैरल)
52,837.21	15,824.05	₹ 46,452	₹65,484	₹74.64	$ 72.95
▲ 638.70	▲ 191.95	▼ ₹264	▲ ₹4	▼ ₹0.15	

ई-कामर्स प्लेटफार्म पर नहीं बिकेगा संचालक का सामान

- शुरुआती दाम सस्ता दिखाने और भुगतान के वक्त अलग-अलग शुल्क जोड़ने का खेल भी नहीं चलेगा
- उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने ई-कामर्स नियमों में बड़ा बदलाव किया



अब ई-कामर्स प्लेटफार्म पर कोई आनलाइन स्टोर भी नहीं चलेगा ● फाइल फोटो

नई दिल्ली, आइएएनएस : उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने ई-कामर्स नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। इसके अनुसार ई-कामर्स प्लेटफार्म को संचालित करने वाली कंपनियां उस प्लेटफार्म पर अपना कोई सामान नहीं बेच सकेंगी। साथ ही ई-कामर्स प्लेटफार्म पर शुरुआती कीमत कम दिखाने और भुगतान के वक्त अन्य शुल्क जोड़कर ज्यादा दाम दिखाने का अब खेल नहीं चलेगा।

नए नियमों के अनुसार प्लेटफार्म अब ग्राहक को वस्तु या सेवा का कुल मूल्य दिखाएंगे और भुगतान के वक्त बताएंगे कि उसमें किस मद में कितना शुल्क लिया जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार अब ई-कामर्स प्लेटफार्म पर कोई भी आनलाइन स्टोर नहीं चलेगा। नए नियमों के मुताबिक प्लेटफार्म पर सिर्फ तीसरा पक्ष यानी थर्ड-पार्टी ही अपने सामान बेच सकेगा। मंत्रालय ने ग्राहक सुरक्षा (ई-कामर्स) कानून, 2020 के तहत ये बदलाव किए हैं और सरकार ने इस पर सभी पक्षों की राय मांगी है। इन नियमों के अधिसूचित हो जाने के बाद विदेशी ई-कामर्स कंपनियों द्वारा दिए जा रहे भारी डिस्काउंट संबंधी शिकायतों में कमी आने की उम्मीद है।

ई-कामर्स प्लेटफार्म का मतलब ऐसी इकाई से है, जो खरीदार और विक्रेता के बीच लेनदेन पूरा करने के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रानिक नेटवर्क पर सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म मुहैया कराती है।

नए नियमों में यह भी कहा गया है कि कोई भी ई-कामर्स इकाई एक ही वर्ग के ग्राहकों में ऐसा भेदभाव नहीं करेगी जिससे उनके अधिकारों का हनन होता हो। प्लेटफार्म पर ग्राहक विशेष के लिए कोई आफर नहीं दिया जाएगा और ऐसा कोई भी आफर सभी ग्राहकों के लिए समान होगा। उन्हें यह भी बताना होगा कि प्लेटफार्म पर सामान बेचने के लिए विक्रेता को कितना भुगतान करना पड़ रहा है और उसे किस तरह के अन्य शुल्क देने पड़ रहे हैं। प्लेटफार्म को विक्रेता और उसके बीच की सभी शर्तों और बाध्यताओं की जानकारी देनी होगी। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक ही कैटेगरी के विक्रेताओं को प्लेटफार्म द्वारा दिया जाने वाला डिस्काउंट भी अब समान होगा। ई-कामर्स प्लेटफार्म अब अपनी तरफ से पसंदीदा विक्रेता का दर्जा किसी एक, दो या किसी वर्ग विशेष के विक्रेताओं को नहीं दे सकेंगे।

इन सभी कवायदों का मकसद ई-कामर्स प्लेटफार्म को ग्राहकों और विक्रेताओं के प्रति अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ समय के दौरान ई-कामर्स प्लेटफार्म के खिलाफ ग्राहकों और उनके विक्रेताओं की तरफ से ऐसी कई शिकायतें सरकार को मिली हैं कि प्लेटफार्म पर उनके साथ भेदभाव हो रहा है।

अन्य महत्वपूर्ण नियम

- प्लेटफार्म द्वारा जुटाई गई सूचना का उपयोग कोई अपने उत्पाद बेचने के लिए नहीं करेगा
- प्लेटफार्म या उससे जुड़ी सहायक कंपनियां अपने प्राइवेट लेबल का लाइसेंसिंग अधिकार उस प्लेटफार्म पर मौजूद किसी भी थर्ड पार्टी सेलर को नहीं देंगी
- दो प्लेटफार्म एक ही या मिलते-जुलते ब्रांड नाम का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे
- विक्रेताओं को अपना लाजिस्टिक्स पार्टनर चुनने की छूट होगी और प्लेटफार्म अपने लाजिस्टिक्स पार्टनर नहीं थोप सकेंगे
- कोई भी लाजिस्टिक्स पार्टनर एक ही कैटेगरी के दो विक्रेताओं में भेद नहीं कर पाएगा

फ्यूचर ग्रुप में निवेश के वक्त अमेजन ने छुपाए थे तथ्य : सीसीआइ

समीक्षा

- फ्यूचर ग्रुप के साथ वर्ष 2019 में हुए सौदे में तथ्य छुपाने का आरोप
- फ्यूचर-रिलायंस सौदे के बीच में खड़ी अमेजन की राह मुश्किल

नई दिल्ली, रायटर : भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआइ) ने अमेरिकी आनलाइन रिटेलिंग दिग्गज अमेजन इंक पर वर्ष 2019 में फ्यूचर ग्रुप के साथ हुए सौदे में तथ्य छुपाने का आरोप लगाया है। सीसीआइ का कहना है कि फ्यूचर ग्रुप की एक यूनिट में निवेश की इजाजत मांगने वाले दस्तावेज में अमेजन ने झूठे तथ्य पेश किए थे। आयोग ने इस बारे में इस वर्ष चार जून को अमेजन इंक को एक पत्र लिखा है। कारण बताओ नोटिस के रूप में चार पन्नों के इस पत्र में सीसीआइ ने अमेजन से यह भी पूछा है कि झूठी सूचना देने के आरोप में कंपनी पर क्यों नहीं कार्रवाई हो और उसे दंडित किया जाए। हालांकि सूत्र के अनुसार अमेजन ने अभी नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है।

अमेजन ने रायटर को दिए एक बयान में माना है कि उसे एक पत्र मिला है और कंपनी भारतीय कानूनों का पूरी तरह पालन करने को प्रतिबद्ध है। कंपनी के अनुसार वह सीसीआइ की शंका के समाधान में पूरी तरह सफल रहेगी। वैसे, इस पत्र ने फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्रीज में पिछले वर्ष हुए सौदे के बीच में खड़ी अमेजन इंक के लिए रास्ते मुश्किल कर दिए हैं। फ्यूचर ग्रुप ने पिछले वर्ष अगस्त में अपना अधिकांश कारोबार रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआइएल) की रिटेल शाखा रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड (आरआरवीएल) के हाथों बेचने संबंधी करार किया था। अमेजन का कहना है कि उसने वर्ष 2019 में फ्यूचर कूपंस की 49 फीसद हिस्सेदारी खरीदी थी और यह सौदा फ्यूचर ग्रुप को उसका रिटेल कारोबार रिलायंस के हाथों बेचने से रोकता है।

अब सीसीआइ का कहना है कि फ्यूचर रिटेल में रणनीतिक रुचि होने की बात छुपाकर अमेजन ने सौदे के तथ्यात्मक पहलुओं को सामने आने से रोका। ऐसे में आयोग के समक्ष अमेजन का आचार भ्रमित करने, झूठे बयान देने तथा तथ्यात्मक और मौलिक सच को छुपाने वाला है। अपने पत्र में आयोग ने यह भी कहा कि उसे फ्यूचर ग्रुप की तरफ से शिकायतें मिली थीं, जिसके बाद उसने सौदे के पहलुओं की समीक्षा की। स्पर्धा कानून विशेषज्ञ और जे. सागर एसोसिएट्स के पार्टनर वैभव चौकसे ने कहा कि सीसीआइ की तरफ से ऐसे पत्र सामान्य नहीं हैं।

स्टील सेक्टर में पीएलआइ मंजूर

40,000 करोड़ के निवेश के साथ पांच लाख से अधिक रोजगार का अनुमान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : स्पेशलिटी स्टील यानी विशेष प्रकार के स्टील उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए गुरुवार को कैबिनेट कमेटी ने 6,322 करोड़ रुपये की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआइ) योजना को मंजूरी दे दी। इस स्कीम की अवधि वर्ष 2023-24 से वर्ष 2027-28 तक पांच वर्षों की होगी।

इस स्कीम के तहत लगभग 40,000 करोड़ रुपये का निवेश होने का अनुमान है जिससे लगभग 5.25 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इनमें से 68,000 प्रत्यक्ष रोजगार होंगे। अभी विशेष प्रकार के स्टील का काफी मात्रा में आयात हो रहा है।

विशेष इस्पात की पांच श्रेणियों को पीएलआइ स्कीम में शामिल किया गया है। इनमें कोटेड-प्लेटेड स्टील, हाई स्ट्रेंथ, स्पेशलिटी रेल, अलाय स्टील उत्पाद और स्टील वायर एवं इलेक्ट्रिकल स्टील शामिल हैं। इस योजना के पूरा होने के बाद भारत एपीआइ ग्रेड पाइप, हेड हार्डेन्ड रेल, इलेक्ट्रिकल स्टील जैसे उत्पादों की मैन्यूफैक्चरिंग शुरू कर देगा। इनकी फिलहाल बहुत ही सीमित मात्रा में या नहीं के बराबर मैन्यूफैक्चरिंग होती है।

पीएलआइ स्कीम के तीन स्लैब होंगे। सबसे कम स्लैब चार फीसद और सबसे अधिक 12 फीसद का होगा। लेकिन किसी भी कंपनी को एक वर्ष में 200 करोड़ से अधिक का प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा।

वर्ष 2020-21 में 10.2 करोड़ टन टन इस्पात का उत्पादन किया गया। इनमें से मूल्य-वर्धित (वैल्यू एडेड) और विशेष इस्पात का उत्पादन 1.8 करोड़ टन का था। बीते वित्त वर्ष में विभिन्न प्रकार के 67 लाख टन स्टील का आयात किया गया इनमें से लगभग 40 लाख टन आयात विशेष इस्पात का था। इस आयात में लगभग 30,000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का व्यय हुआ।

वर्ष 2026-27 के अंत तक विशेष इस्पात का उत्पादन 4.2 करोड़ टन होने का अनुमान है। इनमें से 2.5 लाख करोड़ रुपये मूल्य के विशेष इस्पात की खपत घरेलू बाजार में होगी।

इस अवधि तक विशेष इस्पात का निर्यात वर्तमान के 17 लाख टन से बढ़कर लगभग 55 लाख टन हो जाएगा जिससे 33,000 करोड़ रुपय की विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी।

तेल कंपनियों में 100 फीसद एफडीआइ की मंजूरी



रणनीतिक बिक्री के लिए तैयार सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों में सरकार ने 100 फीसद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) की मंजूरी दे दी है। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक गुरुवार को कैबिनेट कमेटी की बैठक में आयल कंपनियों में 100 फीसद एफडीआइ का फैसला किया गया। इससे सरकार को भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन (बीपीसीएल) के निजीकरण में सहूलियत होगी और कंपनियों की अच्छी कीमत भी प्राप्त होगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने उन तेल व गैस कंपनियों में आटोमेटिक रूट से 100 फीसद एफडीआइ की इजाजत दी है जिनके विनिवेश की सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। वर्तमान में सरकारी तेल व गैस कंपनियों में 49 फीसद एफडीआइ की इजाजत है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी कंपनी बीपीसीएल में सरकार अपनी लगभग 53 फीसद हिस्सेदारी को बेचना चाहती है। चालू वित्त वर्ष में सरकार ने विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है।

एमएसएमई के 13 लाख लोन अकाउंट की हुई रिस्ट्रक्चरिंग

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकारी बैंकों ने अब तक 13.06 लाख एमएसएमई लोन अकाउंट की रिस्ट्रक्चरिंग की है। एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने गुरुवार को संसद में बताया कि इस वर्ष 25 जून तक एमएसएमई के इन अकाउंट्स के तहत 55,333 करोड़ रुपये कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग हो चुकी है। इसके साथ ही एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) के तहत दो जुलाई तक 2.73 लाख करोड़ कर्ज का आवंटन हो चुका है।

ईसीएलजीएस के तहत एमएसएमई सेक्टर की कंपनियों को 4.5 लाख करोड़ तक का कर्ज वितरण होना है। इस कर्ज की 100 फीसद गारंटी केंद्र की होगी। एक सवाल के जवाब में राणे ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 16,688.17 करोड़ की मार्जिन मनी (एमएम) से 96,97,612 यूनिट की स्थापना की जा चुकी है।

पेट्रोलियम उत्पादों पर टैक्स से हो रहा इन्फ्रा विकास



नितिन गडकरी ● फाइल फोटो

नई दिल्ली, प्रेट्र : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों पर लगाए गए उत्पाद शुल्क का इन्फ्रास्ट्रक्चर समेत विकास के अन्य कार्यों में उपयोग हो रहा है। गडकरी ने लोकसभा को बताया कि उत्पाद शुल्क का निर्धारण मौजूदा राजकोषीय स्थिति को देखते हुए इन्फ्रा समेत विकास के अन्य कार्यों में मदद के आधार पर किया गया है। उन्होंने कहा कि परिवहन की कुल लागत में ईंधन की हिस्सेदारी 34 फीसद रहती है। शेष खर्च अन्य मदों के हैं। गडकरी ने बताया कि बीते वित्त वर्ष के दौरान रोजाना 37 किमी के हिसाब से कुल 13,327 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हुआ है।

सितंबर मध्य तक एयर इंडिया के लिए वित्तीय बोली मिलने की उम्मीद

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय विमानन राज्यमंत्री वीके सिंह ने गुरुवार को कहा कि सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया के लिए पात्र इच्छुक बोलीकर्ताओं (क्यूआइबी) की तरफ से वित्तीय बोलियां 15 सितंबर तक मिल जाने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष 27 जनवरी को एक्सप्रेशन आफ इंटरेस्ट (ईओआइ) मंगाई थी। सरकार द्वारा चयनित लेनदेन सलाहकार को 14 दिसंबर, 2020 तक बहुत सी ईओआइ मिलीं। इनके मूल्यांकन के बाद सलाहकार ने वित्तीय बोली को निविदाएं मांगी थीं।

जल्द खुद की डिजिटल मुद्रा लाने का विचार : आरबीआइ

नई दिल्ली, प्रेट्र : आरबीआइ के डिप्टी गवर्नर टी. रबी शंकर ने गुरुवार को कहा कि बैंक चरणबद्ध तरीके से खुद की डिजिटल मुद्रा लाने की रणनीति पर काम कर रहा है। बैंक इसे पायलट आधार पर थोक तथा खुदरा क्षेत्रों में पेश करने की प्रक्रिया में है। उन्होंने कहा कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) को लेकर सोच-विचार काफी आगे बढ़ चुका है और दुनिया के कई केंद्रीय बैंक इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं।

शंकर के अनुसार सीबीडीसी के तहत उपभोक्ताओं को उन डिजिटल मुद्राओं में देखी गई डरावनी अस्थिरता से बचाने की जरूरत है, जिन्हें कोई सरकारी गारंटी हासिल नहीं है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंक सीबीडीसी की संभावना तलाशने में लगे हैं और कुछ देशों में इस दिशा में काम काफी आगे भी बढ़ा है। विधि सेंटर फार लीगल पालिसी के आनलाइन कार्यक्रम के दौरान चर्चा के दौरान शंकर का कहना था सीबीडीसी को लेकर विचार अब क्रियान्वयन के करीब पहुंच गया है।

राष्ट्रीय फलक

न्यूज गैलरी

चेन्नई में अग्निशमन विभाग ने 38 लोगों की जान बचाई

चेन्नई : अग्निशमन विभाग ने एक भवन की तीसरी मंजिल में फंसे 38 लोगों को बचा लिया। गुरुवार दोहपर इस भवन में आग लग गई थी। स्काई लिफ्ट के सहारे आठ बच्चों को निकाला गया। 12 महिलाओं समेत शेष 30 अन्य लोगों को दरवाजा तोड़कर निकाला गया। (आइएएनएस)

अमरावती भूमि घोटाला में आंध्र प्रदेश ने याचिका वापस ली

नई दिल्ली : आंध्र प्रदेश सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली। राज्य सरकार ने अमरावती में पूर्व की तेदेपा सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई जमीन संबंधी अनियमिता की एसआइटी से जांच पर हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को चुनौती दी थी। (प्रेट्र)

मशहूर मलयाली अभिनेता केटीएस पदनायिल का निधन

कोच्चि : मलयालम फिल्मों के मशहूर अभिनेता केटीएस पदनायिल का कोच्चि के एक अस्पताल में गुरुवार सुबह निधन हो गया। वे 88 वर्ष के थे। फिल्मों में अपनी हास्य भूमिकाओं के लिए लोकप्रिय रहे केटीएस उम्र संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे थे। (प्रेट्र)

जासूस कांड : रिमांड अवधि समाप्त, जेल पहुंचा आरोपित

पलवल : पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ के लिए जासूसी करने के आरोपित पूर्व सैनिक व हरियाणा पुलिस में सिपाही सुरेंद्र को जिला पुलिस ने रिमांड अवधि समाप्त होने पर बृहस्पतिवार को अदालत में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। (जासं)

गुजरात में कांस्टेबल की हत्या करने के दोषी को उम्रकैद

अहमदाबाद : अपराध शाखा के कांस्टेबल चंद्रकांत मकवाणा की हत्या कर हिरासत से भाग निकले आरोपित को सत्र न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये जुर्माना किया है। नार्कोटिक्स मामले में पूछताछ के लिए अप्रैल 2016 में मनीष बलाई नामक एक युवक को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच कार्यालय तक लाया गया था। (राब्यू)

हाई कोर्ट से अनिल देशमुख और महाराष्ट्र सरकार को झटका

राज्य ब्यूरो, मुंबई

> पुलिस कमिश्नर किसी का नहीं, बल्कि कानून का सेवक होता है।
> – बांबे हाई कोर्ट की टिप्पणी



सख्त रवैया...बांबे हाई कोर्ट। फाइल फोटो

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और महाराष्ट्र सरकार को मुंबई हाई कोर्ट में मुंह की खानी पड़ी है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और देशमुख की ओर से दायर याचिकाएं खारिज कर दी हैं। देशमुख ने अपने विरुद्ध सीबीआइ द्वारा दर्ज एफआइआर रद करने और महाराष्ट्र सरकार ने एफआइआर में से दो पैरा हटाने के लिए याचिका दायर की थी। राज्य सरकार कोर्ट के जांच के आदेश पर कुछ दिन के लिए रोक भी लगवाना चाहती थी।

अनिल देशमुख पर पुलिस अधिकारियों के जरिये हर महीने 100 करोड़ रुपयों की वसूली करवाने का आरोप लगने के बाद मुंबई हाई कोर्ट की ही एक पीठ ने पांच अप्रैल को सीबीआइ जांच के आदेश दिए थे। सीबीआइ ने इस मामले में एफआइआर दर्ज करते हुए उसमें मुंबई पुलिस के बर्खास्त एपीआइ सचिन वाझे की 15 साल बाद पुलिस विभाग में बहाली और अनिल देशमुख पर पुलिस अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग में हस्तक्षेप के मामलों की जांच भी शामिल कर ली थी। राज्य सरकार इन दोनों मामलों की जांच से संबंधित पैरा सीबीआइ की एफआइआर से हटवाना चाहती थी। जबकि अनिल देशमुख ने अपनी याचिका में अपने विरुद्ध शुरू हुई सीबीआइ जांच को ही चुनौती दी थी जिसमें उन पर घूसखोरी, भ्रष्टाचार एवं आपराधिक साजिश के आरोप लगाए गए हैं। गुरुवार को जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एनजे जमादार की खंडपीठ ने ये दोनों याचिकाएं खारिज कर दीं।

खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि हमारे विचार से सीबीआइ सचिन वाझे की 15 साल बाद पुलिस बल में बहाली और पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग मामलों की जांच कर सकती है। खंडपीठ के अनुसार, उसके इस आदेश को पुलिस विभाग में सामान्य ट्रांसफर-पोस्टिंग मामलों से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि पूर्व गृह मंत्री और उनके सहयोगियों का मामला इससे अलग है। जस्टिस शिंदे ने अपने फैसले में विशेष तौर पर कहा कि पुलिसकर्मियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पुलिस आयुक्त की जिम्मेदारी होती है ताकि उनका शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सही तरीके से काम कर सके।

बता दें कि देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगने से बहुत पहले महाविकास अघाड़ी सरकार में ही ट्रांसफर-पोस्टिंग में तत्कालीन गृह मंत्री के हस्तक्षेप की रिपोर्ट राज्य की तत्कालीन खुफिया आयुक्त रश्मि शुक्ला ने मुख्यमंत्री को दे दी थी। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने पहले सुप्रीम कोर्ट और फिर मुंबई हाई कोर्ट में दायर अपनी याचिका में इस रिपोर्ट का भी विस्तार से उल्लेख किया है।

मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह पर एक और मुकदमा

कार्रवाई

राज्य ब्यूरो, मुंबई

मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के विरुद्ध महानगर के मरीन ड्राइव थाने में गुरुवार को एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। कुल आठ लोगों पर दर्ज प्राथमिकी में आइपीसी की 29 धाराएं लगाई गई हैं। परमबीर सहित 32 लोगों के विरुद्ध अप्रैल में भी आइपीसी की 27 धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

मुंबई के मरीन ड्राइव थाने में एक बिल्डर की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी में कहा गया है कि परमबीर सिंह ने उसके विरुद्ध दर्ज कुछ मामलों का निपटारा करने के लिए 15 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी। रिपोर्ट में परमबीर के अलावा पांच और पुलिस अधिकारियों को आरोपित बनाया गया है। सभी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धाराओं 387, 388, 389 (वसूली से संबंधित), 420 (धोखाधड़ी व संपत्ति से संबंधित बेईमानी), 464 (फर्जी दस्तावेज तैयार करना) व 465, 467, 468, 471 (जालसाजी से संबंधित) आदि के तहत मामला दर्ज किया गया है।

12 भाजपा विधायकों ने निलंबन को दी चुनौती

नई दिल्ली, प्रेट्र : भाजपा के 12 विधायकों ने महाराष्ट्र विधानसभा में पीठासीन अधिकारी से बदसलूकी करने के आरोप में अपने एक साल के निलंबन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

हाई कोर्ट पहुंचा मुस्लिम व ईसाइयों के अल्पसंख्यक दर्जे का मामला

कोच्चि, प्रेट्र : केरल में मुसलमान व ईसाई समाज के अल्पसंख्यक दर्जे के पुनर्मूल्यांकन के लिए गुरुवार को हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। इसमें कोर्ट से आग्रह किया गया है कि वह केंद्र को इस बात के पुनर्मूल्यांकन का निर्देश दे कि केरल में क्या अब भी मुस्लिम व ईसाई समुदायों को अल्पसंख्यकों की सूची में रखा जाना चाहिए। जस्टिस एस. मणिकुमार व जस्टिस शाजी पी. चैली की पीठ ने याचिकाकर्ता संगठन सिटीजन एसोसिएशन फार डेमोक्रेसी, इक्वलिटी, ट्रैंक्विलिटी एंड सेकुलरिज्म (सीएडीईटीएस) की दलील को सुनने के बाद कहा कि वह इस मुद्दे पर आदेश जारी करेगी। सीएडीईटीएस की तरफ से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता सी. राजेंद्रन व के. विजयन ने कहा कि केरल के अल्पसंख्यकों की सूची का पुनर्निर्धारण किया जाना चाहिए। इस मामले में देशभर की नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि फैसले के आधार पर देश के अन्य राज्यों में भी समुदायों का दर्जा तय हो सकता है।

'दुश्मनी मत लेना... हम भगवान के दर्शन बहुत जल्द करा देते हैं'

संस, कबरई (महोबा) : दिवंगत क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के मामले की जांच के दौरान बर्खास्त और गिरफ्तार किए गए सिपाही अरुण सिंह के भाइयों ने फेसबुक पर धमकी भरी पोस्ट की है। चचेरे भाई नीलेश ने पोस्ट में लिखा है- 'हमसे और हमारे परिवार से दुश्मनी मत लेना, क्योंकि हम लोगों को भगवान के दर्शन बहुत जल्द करा देते हैं।' सिपाही के सगे भाई नीरज ने अपनी पोस्ट में लिखा है- 'वक्त आंखें फेर लेता है तो शेर को भी कुत्ता घेर लेता है, क्योंकि कमजोर हम नहीं हमारा वक्त है। वक्त को वक्त दो, क्योंकि वक्त आने में वक्त लगता है।'

दिवंगत इंद्रकांत के भाई विजय त्रिपाठी ने शिकायत की। जिसके आधार पर नीलेश और नीरज के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। पिछले साल सितंबर में दिवंगत क्रशर कारोबारी ने तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाया था। दूसरे दिन गोली लगने से घायल कारोबारी की मौत हो गई थी।

गिरफ्तारी से बचने को राज कुंद्रा ने पुलिस को दी थी 25 लाख की घूस

मुंबई, एएनआइ : पोर्नोग्राफी मामले में फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को लेकर नई-नई जानकारियां सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने जानकारी दी है कि उसे एक ईमेल मिला है जिसमें आरोप लगाया गया है कि राज कुंद्रा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए मुंबई पुलिस को 25 लाख रुपये की रिश्वत दी थी।

एसीबी अधिकारियों ने बताया कि यह ईमेल उसे यश ठाकुर ने भेजा है। ठाकुर भी पोर्नोग्राफी मामले में एक अन्य आरोपित है। उसने कहा कि मुंबई पुलिस ने उससे भी गिरफ्तारी से बचने के लिए इतनी ही राशि मांगी थी। एसीबी ने इस ईमेल को आगे जांच के लिए मुंबई पुलिस को भेज दिया है। एसीबी महाराष्ट्र ने यश ठाकुर के इस संबंध में मिले ईमेल की पुष्टि की है, लेकिन उसके रिश्वत देने के आरोप ऐसे हैं जिसमें जांच जरूरी है, इसलिए इस ईमेल को 30 अप्रैल, 2021 को आगे की जांच के लिए मुंबई पुलिस को भेज दिया गया है।

शिल्पा शेट्टी की भूमिका की कोई जानकारी नहीं

पत्रकारों से बातचीत करते हुए भारांबे ने कहा कि पुलिस को पोर्नोग्राफी मामले में शिल्पा शेट्टी की भूमिका को लेकर कोई जानकारी नहीं मिली। पूछताछ में यह पता चला है कि कुंद्रा की कंपनी वियान में स्थित है और उसकी लंदन स्थित कंपनी केनरिन के साथ साझेदारी है। इसी कंपनी के पास 'हाटशाट्स' का स्वामित्व है। मुंबई में जो भी न्यूड सीन शूट किए जाते थे उसे 'हाटशाट्स' में अपलोड किया जाता था। 'हाटशाट्स' का संचालन मुंबई से किया जाता था।

बता दें कि अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में कुंद्रा समेत 11 अन्य लोगों को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सोमवार को गिरफ्तार किया था।

ओलंपियन सुशील कुमार का एक और साथी पहलवान गिरफ्तार

जासं, नई दिल्ली : पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक और पहलवान सुरजीत ग्रेवाल को गिरफ्तार कर लिया है। सुरजीत को हरियाणा के भिवानी स्थित उसके पैतृक गांव बामला से गिरफ्तार किया गया। सुशील कुमार के करीबी सुरजीत पर 50 हजार रुपये का इनाम रखा था।

डीसीपी स्पेशल सेल संजीव कुमार यादव के मुताबिक सागर धनखड़ हत्याकांड में अब तक सुशील कुमार सहित 13 आरोपित को गिरफ्तार किया जा चुका है। सुरजीत ग्रेवाल, प्रवीण डबास, प्रवीण उर्फ छोटी, जोगिंदर उर्फ काला, राहुल घाडा व अनिल धीमान फरार थे। इनके खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। 21 जुलाई को सेल को सूचना मिली कि सुरजीत घर पहुंच रहा है। इसके बाद पुलिस टीम ने उसे घर से दबोच लिया। मालूम हो कि चार मई को सुशील ने पहलवानों और बदमाशों को बुलाकर सागर धनखड़ को पीटा था। उपचार के दौरान धनखड़ की मौत हो गई।

आगरा में मां और तीन बच्चों की गला रेतकर हत्या

सनसनीखेज

जागरण संवाददाता, आगरा

अपराधियों से पुलिस को रोज नई चुनौती मिल रही है। आगरा में डा. उमाकांत अपहरण व गोल्ड लोन कंपनी की शाखा में डकैती के बाद गुरुवार को पुराने शहर के मोहल्ला कूचा साधूराम में तलाक के बाद अकेली रहती महिला व उसके तीन मासूम बच्चों की गला रेतकर हत्या कर दी गई। गुरुवार सुबह सभी के शव घर में पड़े मिले। कारण को लेकर पुलिस अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है।

मोहल्ला कूचा साधूराम निवासी 35 वर्षीय रेखा राठौर पति सुनील राठौर से तलाक के बाद दो वर्ष से 12 वर्षीय बेटे टुकटुक, 10 वर्षीय बेटे पारस और आठ वर्षीय बेटी माही के साथ रहती थी। पति माईथान में दूसरे मकान में रहता है, उसने दूसरी शादी कर ली है। रेखा के घर का दरवाजा बुधवार दोपहर 12 बजे से खुला था, रातभर भी खुला रहा। गुरुवार सुबह शक होने पर पड़ोसियों ने पुलिस चौकी पर सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, तो घर में घुसते ही अनहोनी की आशंका होने लगी। दरवाजे के पास ही जूते चप्पल बिखरे थे, पहली मंजिल पर कमरे में दो बच्चों के शव पलंग पर और एक बच्चे के साथ महिला का खून से लथपथ शव फर्श पर पड़ा था। चारों के गले रेते गए थे। खुली पड़ी अलमारियों का सामान बिखरा पड़ा था। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लेने के बाद फोरेंसिक टीम को बुलाया। पुलिस ने रेखा के पति सुनील राठौर को हिरासत में लिया है। एडीजी राजीव कृष्ण ने बताया कि चारों की हत्या में कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। जिस मकान में रेखा रहती थी, वह उसके पति ने सात साल पहले खरीदा था। अब उसी के नाम है।

दैनिक जागरण

खेल मानवीय एकता और प्रगति के प्रतीक हैं

अशोभनीय आचरण

विपक्ष किस तरह संसद में अपने दायित्वों के निर्वहन के प्रति गंभीर नहीं और विरोध के नाम पर हंगामा करने में अतिरिक्त दिलचस्पी दिखा रहा है, इसका प्रमाण है राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के सदस्य शांतनु सेन की ओर से आइटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथ से कागज छीनकर फाड़ देना। यह हर लिहाज से एक घटिया हरकत है। सबसे खराब बात यह रही कि यह ओछी हरकत उच्च सदन में हुई। इस हरकत से यह धारणा ही ध्वस्त हुई कि निचले सदन यानी लोकसभा की अपेक्षा राज्यसभा में कहीं अधिक धीर-गंभीर चर्चा होती है। यह अफसोस की बात है कि अब दोनों सदनों के कामकाज में अंतर करना कठिन हो रहा है। यह ठीक है कि विपक्ष जासूसी प्रकरण पर आंदोलित है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह इस मसले पर सरकार का पक्ष सुनने से इन्कार करने के साथ संसद की गरिमा गिराने वाला काम करे। आखिर यह क्यों न मान लिया जाए कि उसकी दिलचस्पी चर्चा और बहस में नहीं, हंगामा करने में है?

तृणमूल कांग्रेस सांसद शांतनु सेन ने अपने अशोभनीय आचरण से संसद में ऐसी ही शरारत करने वाले सांसदों की याद दिला दी। इनमें उनकी नेता ममता बनर्जी भी हैं। एक समय उन्होंने बतौर लोकसभा सदस्य अध्यक्ष के समक्ष जाकर उन पर कागज फेंके थे। तब उनकी नाराजगी का कारण बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को मिल रहा संरक्षण था। यह विडंबना ही है कि आज वह इन घुसपैठियों की सबसे बड़ी हितैषी बन गई हैं। हैरानी नहीं कि शांतनु सेन को अपनी हरकत पर ममता और अपने अन्य साथियों से शाबासी मिली हो। जो भी हो, ऐसे असंसदीय आचरण के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यदि शांतनु सेन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती तो आने वाले दिनों में संसद में वैसे ही दृश्य फिर से दिखने को मिल सकते हैं, जैसे गत दिवस देखने को मिले। संसद में सड़कछाप आचरण सहन नहीं किया जाना चाहिए। यदि सहन किया जाएगा तो फिर संसद और सड़क की राजनीति में फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि सत्तापक्ष ने शांतनु सेन के आचरण को शर्मनाक कहा, क्योंकि इससे उनकी सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। उन्हें दंड का भागीदार बनाया जाना चाहिए, क्योंकि मामला संसद की मर्यादा का है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि शांतनु सेन आइटी मंत्री अश्विनी वैष्णव से छीनाझपटी करने के दौरान एक अन्य मंत्री हरदीप पुरी से भी उलझे। आखिर सांसद संसद में बहस करने आते हैं या छीनाझपटी करने? सवाल यह भी है कि अन्य विपक्षी दल शांतनु सेन के अभद्र आचरण की आलोचना क्यों नहीं कर पा रहे हैं?

राहत पैकेज

कोरोना संक्रमण के कारण व्यापक आर्थिक तंगी से जूझ रहे पर्यटन व्यवसायियों के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा एक अच्छा कदम है। बशर्ते इसका लाभ व्यवसाय से जुड़े हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। पर्यटन उत्तराखंड में आर्थिकी का प्रमुख स्रोत है। प्रदेश में आबादी का बड़ा हिस्सा किसी न किसी रूप में पर्यटन व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। बीते वर्ष कोरोना संक्रमण के कारण लागू लाकडाउन के बाद से ही पर्यटन व्यवसाय पटरी से उतरा हुआ है। स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते वर्ष चारधाम यात्रा पर केवल तीन लाख श्रद्धालु पहुंचे, जबकि सामान्य तौर पर यह संख्या प्रतिवर्ष 25 से 30 लाख के बीच रहती है। इसी कारण बीते वर्ष भी सरकार ने पर्यटन उद्योग से जुड़े व्यक्तियों को राहत पैकेज देने का निर्णय लिया था, लेकिन इसका लाभ बहुत कम व्यक्तियों को ही मिल पाया। इसका मुख्य कारण यह रहा कि अधिकांश होटल, ढाबों व रेस्टोरेंट स्वामियों ने अपने यहां कार्य करने वाले कार्मिकों को पंजीकृत ही नहीं कराया था। यही स्थिति वाहनों में कंडक्टर व क्लीनर की रही। पंजीकृत न होने के कारण वे लाभान्वितों की श्रेणी में नहीं आ पाए। इस कारण कोरोना संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित और जरूरतमंद व्यक्तियों को राहत नहीं मिल पाई। इस बार भी सरकार ने इसी वर्ग को ध्यान में रखते हुए दो हजार रुपये प्रतिमाह की दर से छह माह तक आर्थिक सहायता के लिए व्यवस्था की है। आशंका जताई जा रही है कि बीते वर्ष की तरह यदि राहत बांटने के मानक यथावत रहे तो इस बार भी यह वर्ग सरकार की सहायता से वंचित रह सकता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार सरकार केवल पंजीकरण को ही सहायता देने का आधार नहीं बनाएगी और जरूरी जानकारी जुटाते हुए प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक यह सहायता पहुंचाने का रास्ता निकालेगी। इसके साथ ही यह व्यवस्था भी बनाई जानी जरूरी है कि गलत और अपात्र इसका अनुचित लाभ न ले सकें। इसके साथ ही सरकार को अब धीरे-धीरे पर्यटन को भी गति देने की जरूरत है। सरकार को चाहिए कि वह पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कदम उठाने के साथ ही कोविड की रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करे। पर्यटन स्थलों व होटलों पर नजर रखने के लिए आवश्यक कदम उठाते हुए अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जानी चाहिए।

विजयगाथा लिखने को बेताब बेटियां



अनुराग सिंह ठाकुर

महिलाओं को खेल में समर्थन मिलने से समाज में बड़े बदलाव देखने को मिले, जिससे कई पूर्वाग्रह खत्म हो गए। अब उम्मीद है कि टोक्यो ओलिंपिक से सफलता की एक नई गाथा शुरू होगी

बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ अभियान के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज में महिलाओं को सम्मान देने का एक अभिनव प्रयास किया। इसे दुर्भाग्य कहिए या दूरदर्शिता का अभाव कि वर्षों से बेटियों को समाज में उनका उचित स्थान नहीं दिया गया था। कई बेटियों के लिए तो शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं भी पहुंच से बाहर थीं। धीरे-धीरे बदलाव आया। माता-पिता ने बेटियों को पढ़ने और खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। आज वे हर क्षेत्र में सफलता की गाथा लिख रही हैं और दूसरों को प्रेरणा प्रदान कर रही हैं। एक राष्ट्र के रूप में, हमें अपनी बहनों और बेटियों द्वारा सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर गर्व है। आज लड़कियां समाज के हर क्षेत्र और पहलू को प्रभावित कर अपनी छाप छोड़ रही हैं। फिर वे खेलों में कैसे पीछे रह सकती हैं?

जब मैं लड़कियों को खेल के लिए प्रोत्साहित करने वाले अभियान को देखता हूं तो मुझे इस बात से खुशी मिलती है कि यह अभियान देश की उपलब्धियां बढ़ाने में भी कारगर साबित हो रहा है। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के साथ-साथ इसका विस्तार बेटी खिलाओ तक करना होगा। भारत के पास 1951 के एशियाई खेलों की मैरी डिसूजा से लेकर पीटी ऊषा और साक्षी मलिक तक महिला खिलाड़ियों का इतिहास है, जो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलकर आगे बढ़ रही हैं। महिला खिलाड़ियों ने जो पहचान हासिल की है, वह निरंतर हो रही प्रगति का एक अहम प्रतीक और संकेत है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खेलों के प्रति व्यक्तिगत रुचि से, जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को तराशने की प्रक्रिया की गति ने तेजी पकड़ी है। उनका हमेशा से मानना रहा है कि लड़कियों को नए मापदंड स्थापित करने की आवश्यकता है, जिससे अन्य महिलाओं को खेलों में बढ़ावा देने के लक्ष्य को हासिल करने से कोई नहीं रोक पाएगा। खेलो इंडिया अभियान ने एक लंबा सफर तय कर महिलाओं को प्रतिस्पर्धा के लिए बेहतर मंच उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया है, जो न केवल पुरुषों की बराबरी का है, अपितु कुछ पहलुओं में बेहतर भी है। विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों की लड़कियों को खेलों में अपनी पहचान बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते देख मुझे प्रसन्नता होती है। मुक्केबाजी और कुश्ती अब सिर्फ पुरुषों के खेल नहीं हैं। इन खेलों में महिलाओं ने भी अपना दबदबा कायम करना शुरू कर दिया है। मेरी कोम और साक्षी मलिक ने ओलिंपिक में जो कीर्ति हासिल की, वह राष्ट्रीय गौरव की बात है। उन्होंने बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ अभियान को भी दिशा दी है। महिलाओं को खेल में समर्थन मिलने से समाज में बड़े बदलाव देखने को मिले, जिससे हर प्रकार के पूर्वाग्रह खत्म हो गए।



अवधेश राजपूत

स्प्रिंटर दुती चंद की सफलता की कहानी कड़ी मेहनत के महत्व को दर्शाती है। उनमें सफल होने का दृढ़निश्चय था और वह कभी अपने लक्ष्य के पथ से नहीं भटकीं। वह एथलेटिक्स में एक प्रेरणा बनकर उभरी हैं। उनके जैसा संकल्प रखने वाले खिलाड़ियों के लिए कोई सीमा नहीं है। सारा आकाश उनका है। इसी तरह हमारी महिला हाकी टीम ने जो सफलता हासिल की है, वह एक मिसाल है। उनके बेहतर प्रदर्शन का एक कारण यह भी है कि टीम की सदस्य अब जानती हैं कि मैदान पर अच्छा प्रदर्शन उनके लिए एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करेगा। मैं रानी रामपाल के खेल को काफी समय से देख रहा हूं। इस आधार पर मुझे यह कहना होगा कि उनका करियर हम सभी के लिए एक मिसाल है। इस बार टोक्यो ओलिंपिक में अन्य अनेक खिलाड़ियों के साथ निशानेबाजों से भी बहुत उम्मीद है, खासकर मनु भाकर से, जिन्होंने कम समय में ही बहुत कुछ हासिल कर लिया है।

हम पीवी सिंधु, साइना नेहवाल और सानिया मिर्जा की उपलब्धियां तो जानते ही हैं और भारत का गौरव बढ़ाने के लिए उनके आभारी हैं। इन्होंने न केवल अपने लिए नाम बनाया, बल्कि बड़ी प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर अपने-अपने खेलों को भी लोकप्रिय बनाया। जब प्रधानमंत्री ओलिंपिक जा रहे खिलाड़ियों को संबोधित कर रहे थे तो उस दौरान महिलाओं की खेलों में भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने उनका विशेष आभार व्यक्त किया। मेरी कोम के धैर्य पर मैं भी अचंभित हूं। मातृत्व की शक्ति ने उन्हें बाक्सिंग रिंग में और एकाग्र बना दिया है। वह बाक्सिंग की एक महान खिलाड़ी हैं, जो देश का नाम रोशन करने के लिए बाक्सिंग रिंग में डटी रहती हैं। मेरी कोम का यह धैर्य और समर्पण एक मिसाल है। एक और उदाहरण मीराबाई चानू हैं, जो वेटलिफ्टिंग के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। चोट से लड़कर जीतने की मीराबाई की क्षमता भी सराहनीय है। मीराबाई एक अनुशासित खिलाड़ी हैं और मुझे पूरा यकीन है कि वह इस बार ओलिंपिक में अवश्य अच्छा प्रदर्शन करेंगी। लड़कियां बाक्सिंग, कुश्ती, सेलिंग और शूटिंग में बड़ा प्रभाव डाल रही हैं। यह उनकी बहुमुखी प्रतिभा और दृढ़संकल्प का एक नतीजा है।

खेलो इंडिया कार्यक्रम अब देश के कोने-कोने तक पहुंच गया है और अधिकतर खिलाड़ी भारतीय खेल प्राधिकरण की योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। मुझे विश्वास है कि यह ओलिंपिक पुरुष खिलाड़ियों के साथ-साथ महिला खिलाड़ियों को देश के प्रतीक के रूप में स्थापित करेगा। सरकार की ओर से मैं उन्हें हरसंभव समर्थन का भरोसा देता हूं। कोविड के समय सबसे बड़ी चुनौती खिलाड़ियों को ओलिंपिक के लिए तैयार करने की रही। इस दौरान हमारे खिलाड़ियों द्वारा हर चुनौती का मुकाबला पूरी मुस्तैदी के साथ करते देखना सुखद रहा। उम्मीद है कि हमारे सभी खिलाड़ी टोक्यो ओलिंपिक में अभूतपूर्व सफलता हासिल करेंगे और इनमें महिला खिलाड़ी भी होंगी। मैं देश के सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूं और उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की कामना करता हूं।

(लेखक केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री हैं)

response@jagran.com

बरकरार है अंग्रेजी की श्रेष्ठता का दंभ



जगमोहन सिंह राजपूत

भारत एकमात्र ऐसा देश होगा, जहां अपनी मातृभाषा पर गर्व न करने वाले लोग बड़ी संख्या में हैं



स्वास्थ्य मंत्री के अंग्रेजी ज्ञान पर बेजा सवाल। फाइल

बीते दिनों 40 से अधिक केंद्रीय मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। अनेक अवसरों पर यह चर्चा होती थी कि किस मंत्री ने किस भाषा में शपथ ली? इस बार इस प्रकार की चर्चा में एक नया आयाम जुड़ा। नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के कुछ पुराने ट्वीट निकालकर उनका मजाक उड़ाया गया। कहा गया कि उनकी अंग्रेजी ठीक नहीं। बाद में एक पत्रकार सम्मेलन में उनसे इस विषय पर सवाल भी पूछा गया। यह अफसोस की बात है कि देश में एक ऐसा वर्ग है, जो केवल आलोचना के सहारे ही अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। इसमें दूसरे पक्ष के प्रति किसी शालीनता की अपेक्षा निरर्थक ही मानी जानी चाहिए। यह वर्ग अपने मन-मानस में अंग्रेजी के ज्ञान को ही श्रेष्ठता का पर्याय मान बैठा है। यह समूह उस ग्रंथि से बाहर नहीं निकल सका है, जिसे अंग्रेजों ने सुनियोजित ढंग से इस देश के पढ़े लिखे लोगों में सफलता के साथ स्थापित कर दिया था। इन्हें अंग्रेजों ने सिखा दिया था कि जो कुछ श्रेष्ठ और स्वीकार्य है तथा प्रगतिशीलता का द्योतक है, वह केवल पश्चिम की संस्कृति और सभ्यता में निहित है। आज किसी भी सरकारी संस्थान में जाकर देखा जा सकता है कि अंग्रेजी न जानने वाले को उसके अंग्रेजी जानने वाले सहयोगी यह विश्वास दिलाते रहते हैं कि वे उससे श्रेष्ठ हैं। ऐसे लोग केंद्रीय मंत्री की भाषाई कमी को आधार बनाकर उनका उपहास करना चाहते थे, परंतु बदलती परिस्थितियों में स्वयं ही उपहास के पात्र बन गए।

भारत एकमात्र ऐसा देश होगा, जिसमें तमाम समृद्ध भाषाएं हैं, फिर भी अपनी ही मातृभाषा पर गर्व न करने वाले लोग आज भी बड़ी संख्या में हैं। आजादी के बाद भी भाषा को लेकर जो विकट स्थिति बाद की पीढ़ियों ने झेली, उसने शिक्षा में समान अवसरों के वायदे को धुंधला कर दिया। समाज का एक वर्ग अंग्रेजी की अनिवार्यता के विरोध में खड़ा होता रहा, मगर व्यवस्था की निरंतरता ने उस सबको हिकारत की निगाह से ही देखा। यदि राममनोहर लोहिया जैसे लोग न होते तो शायद आज भी बिना अंग्रेजी पढ़े कक्षा दस उत्तीर्ण करना संभव न हुआ होता।

मैंने जब विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया तो स्पष्ट कर दिया गया था कि माध्यम तो अंग्रेजी ही होगा। मेरे जैसे कितने ही छात्रों को इस कारण कठिनाइयां हुईं, मगर कुछ स्नेही प्राध्यापक इस स्थिति को जानते थे और ऐसे विद्यार्थियों की सहायता करते थे। इलाहाबाद विवि में भौतिकी विभाग में विभागाध्यक्ष प्रो. राजेंद्र सिंह और प्रवक्ता डा.मुरली मनोहर जोशी स्नातकोत्तर कक्षाओं में भौतिकी के जटिलतम विषय भी हिंदी में समझाने के लिए विशेष रूप से सराहे जाते थे।

आजादी के पहले तीन दशकों में स्कूल आने वाले अधिकांश छात्र उस पहली पीढ़ी के थे जिनके घर कोई पढ़ा-लिखा नहीं था। ऐसे विद्यार्थियों का कक्षा में उपहास उनके सहपाठियों द्वारा तो होता ही था, अनेक अवसरों पर कुछ अध्यापक भी झुंझलाकर यह कह देते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते। मेरे कई सहपाठी स्कूल छोड़ गए। देश में कितने बच्चों ने आजादी के बाद अंग्रेजी पढ़ने की बाध्यता के कारण स्कूल छोड़ा होगा। जो कुछ किसी तरह बने रहे, उनमें से अधिकांश का दसवीं की बोर्ड परीक्षा के बाद का जीवन भर का परिचय नौवीं पास मात्र रह गया। आज बोर्ड परीक्षा देने वाले बच्चे यह जानकार चकित होंगे कि 1950-60 के दशक में बोर्ड परीक्षा परिणाम मात्र 38-40 प्रतिशत रहते थे। बाकी सब फेल का बोझ लेकर जीते थे। ऐसा तब हो रहा था जब मातृभाषा के महत्व को गांधी जी और उनके सहयोगी परतंत्र देश में भी लगातार समझाते थे। वर्ष 1978 में यूनेस्को के आमंत्रण पर मैं एक अंतरराष्ट्रीय सम्मलेन में थाईलैंड गया। मुझे अपना शोधपत्र प्रस्तुत करना था। मैंने उसे लिखने के बाद अंग्रेजी के प्राध्यापकों को दिखाया, क्योंकि मुझे अपनी अंग्रेजी पर विश्वास नहीं था। औपचारिक उद्घाटन के पहले आयोजकों ने कहा कि प्रारंभिक वक्ता किसी कारण नहीं पहुंच रहे हैं, अतः मुझे उस स्थान पर अपना शोधपत्र प्रस्तुत करना है। मैंने किसी तरह अपने को तैयार कर रिक्त स्थान को भरा। उसी दिन रात्रिभोज के उपरांत लाओस तथा कंबोडिया के प्रतिनिधि मेरे पास आकर बोले, आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। कल हमें अपने प्रस्तुतीकरण देने हैं। क्या आप मदद करेंगे? हम तीनों प्रातः तीन बजे तक गहन चर्चा करते रहे। उनके प्रस्तुतीकरण में घोर आत्मविश्वास झलका और मुझे वहां बैठे-बैठे कुछ ऐसा मिला जो वापस आकर मैंने भोपाल के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के हर विद्यार्थी को बताया। मैंने कहा, 'यदि अंग्रेजी के उच्चारण और व्याकरण में त्रुटि हो तो चिंता करना छोड़ दो। मातृभाषा में व्याकरण और उच्चारण शुद्ध होने चाहिए, लेकिन अंग्रेजी में इन दोनों पक्षों को अपनी बौद्धिक या मानसिक अक्षमता से कभी नहीं जोड़ा जाना चाहिए। याद रखिए कि मैं आज भी अंग्रेजी लिखने में गलती करता हूं, मगर हतोत्साहित नहीं होता-ठीक उसी तरह जैसे लाओस और कंबोडिया के प्रतिभागी नहीं हुए थे।'

आज जब मैं पूरे परिदृश्य पर निगाह डालता हूं तो यह स्पष्ट दिखाई देता है कि स्वतंत्रता के बाद भी नीति निर्धारण और उसका क्रियान्वयन उन्हीं लोगों के हाथों में बना रहा, जो ब्रिटिश सत्तासीनों की आज्ञानुसार कार्य करने के अभ्यस्त थे। जो चाहते थे कि उनके आगे आने वाली पीढ़ियां भी अपनी विशिष्टता का लाभ उठाती रहें। जो तभी संभव था जब सरकारी कामकाज और नौकरी में अंग्रेजी को ही महत्व मिलता रहे। इस सोच में बदलाव आया है, मगर अभी भी पलड़ा अंग्रेजी की तरफ ही झुका रहता है। नई शिक्षा नीति इस स्थिति से उबरने का अवसर उपस्थित कराती है। क्षेत्रीय भाषाओं में तकनीकी विषयों की शिक्षा देने की तैयारी हो रही है। मनसुख मांडविया जी से अनुरोध है कि वह अपने विचार अंग्रेजी में भी लिखते रहें। विचारों की गहराई महत्वपूर्ण है, अन्य सभी कुछ उसके समक्ष गौण है।

(लेखक शिक्षाविद् हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

शक्ति और शांति

वही व्यक्ति, समाज और संस्कृति आगे बढ़ते हैं, जहां शक्ति की उपासना होती है। शांति का संदेश भी वहीं तक पहुंचता है जहां शक्ति की प्रबलता होती है। शांति के लिए शक्ति की सात्विकता आवश्यक है। अज्ञान, अंधविश्वास और पाखंड को खत्म करने के लिए ज्ञान और तर्क की शक्ति चाहिए। दरिद्रता, और हीनता पर विजय प्राप्ति के लिए भी धन-शक्ति चाहिए। विश्व कई तरह की शक्ति से संपन्न है, परंतु इस शक्ति से व्यक्ति, समाज और विज्ञान में पवित्रता के स्थान पर अहंकार बढ़ रहा है। इसीलिए शक्ति का सात्विक होना अत्यंत आवश्यक है। वास्तव में शोषण, जुल्म और प्रताड़ना से मुक्ति के लिए सभी को हर तरह से शक्तिशाली होना जरूरी है। शारीरिक शक्ति मानसिक शक्ति को आधार देती है। मानसिक शक्ति प्राण शक्ति को और प्राणि शक्ति आत्मिक शक्ति को संबल प्रदान करती है। जब तीनों शक्तियां संतुलित होती हैं तो शांति का प्रकाश अंतःकरण में फैल जाता है। इससे यह पता चलता है किसी को भी किसी रूप में कमजोर नहीं होना चाहिए। निर्बलता भी अशांति का एक कारण है।

ऋषि पतंजलि, आचार्य चाणक्य और विचारक हेगल ने शक्ति और शांति की पूरकता को समझा था। योगदर्शन में कहा गया है-इंद्रियों, प्राणों की शक्ति से ही जीवन को शक्ति मिलती है। जीवन की शक्ति से ध्यान में एकाग्रता आती है। यह एकग्रता अशांति, द्वंद्व, हीनता और सभी तरह के विकारों को समाप्त करने का कार्य करती है। एकाग्रता सफलता और आनंद का आधार है। आचार्य चाणक्य ऐसी शक्ति से संपन्न होने के लिए कहते हैं कि 'जिससे हर तरह के लक्ष्य का भेदन किया जा सके, उन शक्तियों को परास्त किया जा सके, जो शांति की स्थापना में रुकावट डालती हों, वे अत्यावश्यक हैं।' स्पष्ट है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए संकल्पित हो तो कोई कारण नहीं कि जीवन और समाज में शक्ति व शांति की पूरकता और साम्य स्थापित न हो सके।

शकुंतला देवी

पूरी हुई एक लंबी प्रतीक्षा

सुनीता मिश्रा

जम्मू-कश्मीर की महिला से विवाह करने वाले अन्य किसी राज्य के पुरुष को भी अब सूबे का डोमिसाइल मिल सकेगा

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने प्रदेश की महिलाओं से शादी करने वाले अन्य राज्य के पुरुषों को भी डोमिसाइल देने का अहम फैसला लिया है। इससे पूर्व की व्यवस्था में केवल 15 वर्ष तक जम्मू-कश्मीर में रहने, निर्धारित अवधि तक प्रदेश में सेवाएं देने और छात्रों के लिए निर्धारित नियमों के तहत ही डोमिसाइल का प्रविधान था, लेकिन अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद-309 का प्रयोग कर जम्मू-कश्मीर सिविल सर्विसेज (डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट) एक्ट 2010 की धारा-15 के तहत दिए गए नियमों के तहत सातवां क्लॉज जोड़ा गया है। इसमें 'स्पाउस ऑफ डोमिसाइल' की श्रेणी जोड़ी गई है। इसमें न तो पति और न ही पत्नी का जिक्र किया गया है। यानी इस श्रेणी के आवेदक को डोमिसाइल के लिए अपने जीवनसाथी का डोमिसाइल प्रमाणपत्र व विवाह प्रमाणपत्र जमा करवाना होगा।

इससे पहले राज्य में लागू अनुच्छेद-35ए ने स्थानीय नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार दिए थे, जो अस्थायी निवासियों के पास नहीं थे। उनमें अस्थायी नागरिक जम्मू-कश्मीर में न तो स्थायी रूप से बस सकते थे और न ही वहां संपत्ति खरीद सकते थे। यहां तक कि वे इस प्रदेश में सरकारी नौकरी, छात्रवृत्ति और किसी भी तरह की सरकारी मदद के हकदार नहीं थे। अनुच्छेद-35ए एक तरह से किसी स्थानीय महिला को उसकी पसंद के पुरुष से विवाह करने की राह में अवरोध उत्पन्न करता था। इसके उलट पुरुषों के मामले में ऐसा नहीं था। अगर पुरुष किसी अन्य राज्य की महिला से शादी करते थे तो उनके विशेषाधिकार खत्म नहीं होते थे।

स्पष्ट है कि पुरानी व्यवस्था प्रदेश की महिलाओं से भेदभाव करती थी। साल 2002 में जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा था कि अस्थायी निवासियों से शादी करने पर भी महिलाओं को संपत्ति में अधिकार जाएगा, लेकिन ऐसी महिलाओं के बच्चे न केवल उस संपत्ति के उत्तराधिकार से वंचित होंगे, बल्कि उन्हें राज्य की नागरिकता भी नहीं मिलेगी। वर्ष 2019 में मोदी सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 और 35ए को निरस्त कर एक निर्णायक पहल की गई थी। इसके बावजूद पुरानी व्यवस्था के चलते प्रदेश की बेटियों के परिवारों को दिक्कतें आ रही थीं। लोगों को डोमिसाइल प्रमाणपत्र धारक से शादी करने पर भी वहां आवश्यक प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा था। इसके लिए उनका 15 वर्ष तक प्रदेश में रहना जरूरी था। ऐसे में जम्मू-कश्मीर प्रशासन का यह फैसला स्वागतयोग्य है। अब राज्य में वैवाहिक रिश्ते कायम करने वाले पुरुषों को भी को यह प्रमाणपत्र हासिल करना सरल होगा। प्रदेश के लोग भी राज्य के बाहर वर तलाश कर सकेंगे। शादी के बाद वे लोग प्रदेश में सरकारी नौकरी हासिल करने के पात्र भी होंगे। साथ ही उनके बच्चों को भी डोमिसाइल का हकदार बनाया जा सकता है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

चुनाव से पहले बसपा को याद आए ब्राह्मण

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक दलों ने भी अपनी सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी को ब्राह्मणों की 'चिंता' सताने लगी है। खुद को ब्राह्मणों का हितैषी साबित करने के लिए पार्टी की मुखिया मायावती ने बसपा के ब्राह्मण चेहरे सतीश चंद्र मिश्र को एक अलग किस्म की जिम्मेदारी सौंपी है। मिश्र को कानपुर के कुख्यात बिकरू कांड के खलनायक विकास दुबे के भांजे अमर दुबे की विधवा खुशी दुबे के लिए कानूनी लड़ाई लड़नी है। इस मामले में उच्च न्यायालय ने भी खुशी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यहां यह अवश्य स्मरण रहे कि खुशी दुबे कोई ऐसी समाज सेविका या आदर्श महिला नहीं, जिसकी पैरवी और दोष मुक्ति पर ब्राह्मण समाज में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाए। वह एक अत्यंत लोमहर्षक आपराधिक घटना में अपराधी के रूप में निरुद्ध है। इस बीच ब्राह्मणों को लामबंद करने के प्रयासों में यह भी न भूला जाए कि वे कभी गोलबंद होकर मतदान नहीं करते। वास्तव में वे कोई 'वोट बैंक' न होकर, एक प्रबुद्ध वर्ग के रूप में अधिक जाने जाते हैं। अतीत में बसपा का दिया गया 'तिलक, तराजू और तलवार। इनको मारो जूते चार' जैसा घोर अपमानजनक नारा भी कैसे भुलाया जा सकता है। इतना ही नहीं, कांशीराम ने उस नारे को संशोधित कर 'बनिया माफ, ठाकुर हाफ और बाम्हन साफ' कर दिया, जिसका मर्म वैश्य वर्ग पर पूरी कृपा, क्षत्रिय को आधा दंड, किंतु ब्राह्मण का पूरी तरह सफाये में निहित था। ब्राह्मण जैसी स्वाभिमानी कौम अपना यह अपमान कैसे भूल सकती है? अपने शासनकाल में मायावती ने ब्राह्मणों के लिए कौनसा हितकर कानून बनाया? उलटे उनके कुछ मनमाने कानूनों के कारण न केवल ब्राह्मण, बल्कि तमाम सवर्ण परिवार झूठे मुकदमों के शिकार हो गए। जनता की याददाश्त भले कितनी ही कमजोर हो, ये बातें उनके जेहन से मिटाए नहीं मिटेंगी। अब मायावती ब्राह्मणों को लुभाने के कितने ही प्रयास कर लें, लेकिन उनकी ये कोशिशें राजनीतिक रूप से रंग नहीं लाएंगी। वैसे भी ब्राह्मणों की सुध उन्हें चुनाव के समय ही सूझती है।

रघोत्तम शुक्ल, लखनऊ

सुधार के लिए करने होंगे ठोस उपाय

संपादकीय पेज पर यशपाल सिंह ने अपने आलेख बंगाल पुलिस के पतन की पराकाष्ठा में बंगाल पुलिस के वामपंथी शासन के समय से ही गिरते चरित्र की विवेचना की है। इसके लिए उन्होंने दोष पुलिस के अधिकारियों को ही दिया है। लेखक स्वयं भी पूर्व में डीजीपी रह चुके हैं। इसलिए वह भी जानते होंगे कि सभी राज्यों में पुलिस की स्थिति उस राज्य की राजनीतिक व्यवस्था की वैध सेना की तरह होती है। यह बात अलग है कि हर जगह वामपंथियों जैसी निरंकुश व्यवस्था नहीं होती है। बीते दिनों सुशांत सिंह केस में मुंबई और बिहार की पुलिस के बीच का व्यवहार सब देख चुके हैं। मुंबई पुलिस के आयुक्त रहे परमवीर सिंह महाराष्ट्र सरकार के लिए बेकार साबित हो चुके हैं। कश्मीर में भी पुलिस का व्यवहार सदैव राजनीतिक व्यवस्था के अनुरूप ही रहा है। शेष राज्य भी कमोबेश इससे मुक्त नहीं हैं। राज्य सरकार के इरादे यदि नेक हों तो उसके अंतर्गत आने वाली प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी नेक नियति पर आ जाती हैं और यदि राजनीतिक व्यवस्था अपने समर्थकों की फौज खड़ी करने व उन्हें हर प्रकार से खुश करने में ही लगी हो तो पुलिस को भी उन्हीं की हां में हां मिलाने में अपना भविष्य सुरक्षित नजर आने लगता है। यदि सत्ता पक्ष के कार्यकर्ता कहीं उपद्रव मचाते हैं तो पुलिस मूकदर्शक बन कर उन्हें समझा-बुझाकर शांत करने का काम करती है। उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं की जाती है। लेकिन विरोधी दल के समर्थक कुछ करते हैं तो उन्हें विभिन्न आपराधिक धाराओं में लपेटने का प्रयास किया जाता है। केंद्रीय सत्ता भी अपने हितों के लिए राज्य पुलिस पर अपने साधनों से दबाव बना सकती है। इसलिए पुलिस सुधारों को लेकर बहुत ही गंभीर व ठोस उपाय करने की जरूरत है। इसमें जितनी देरी होगी, पुलिस की साख उतनी ही प्रभावित होगी और इसका असर गवर्नेंस पर भी दिखेगा।

डीडी सिंघल, फरीदाबाद

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721

15,930 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कारोबार इस वर्ष के अंत तक, जो 2016 में 12,620 करोड़ रुपये ही था, एसोचैम के अनुसार। विविध एफएमसीजी उत्पादों के बूते इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकेगा।

आजकल

अफगानिस्तान नीति पर असमंजस में भारत

अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के मद्देनजर भारत में अफगान नीति को लेकर असमंजस कायम है। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में उभार के संकेत ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। तालिबान से जारी संघर्ष के बीच अफगानिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मोहम्मद अहमदजई भारत दौरे पर आ रहे हैं। इस यात्रा को कई मायने में अहम माना जा रहा है। वहीं, तालिबान चाहता है कि भारत मौजूदा काबुल प्रशासन का समर्थन नहीं करे। ऐसे में भारत के समक्ष एक गंभीर प्रश्न यह है कि आने वाले दिनों में देश की अफगान नीति की दिशा और दशा क्या हो



डा. राजन झा
असिस्टेंट प्रोफेसर,
दिल्ली विश्वविद्यालय



अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते प्रभाव के साथ ही कई कारणों से भारत की भी चिंता बढ़ रही है। इंटरनेट मीडिया

पिछले अनुभवों और बदली हुई अंतरराष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य में हमें अफगान नीति को एक नया आयाम देने की जरूरत है। काबुल में राजनीतिक स्थिरता, भारत की अफगान नीति की पहली शर्त है। पूर्व में जब कभी भी अफगानिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल रहा भारत को इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। वर्ष 1999 में इंडियन एयरलाइंस का एक विमान काठमांडू से नई दिल्ली आने के क्रम में हाइजैक करते हुए कंधार ले जाया गया था।

वर्ष 1989 में अफगानिस्तान पर सोवियत संघ के दखल और 2001 के अमेरिकी युद्ध से भारत ने स्वयं को रणनीतिक तौर पर दूर ही रखा था, लेकिन सोवियत संघ की वापसी के बाद उपजी राजनीतिक अस्थिरता के कारण अफगानिस्तान की धरती को आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया गया। कुछ ऐसा ही खतरा अमेरिकी सेना की वापसी के बाद होने की आशंकाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता। ऐसी परिस्थिति में भारत को राजनीतिक स्थिरता के लिए हरसंभव प्रयास करने की जरूरत है। यह सच है कि भारत के पास सीमित विकल्प हैं, परंतु इसके बावजूद क्षेत्रीय शक्तियों मसलन रूस और ईरान समेत दुनिया के अन्य देशों के साथ मिलकर हमें प्रयासरत रहना होगा। परंतु इस बात का ध्यान रखना होगा कि अफगानिस्तान में हिंसा न हो और मानवाधिकार भी सुरक्षित रहें। हालांकि अच्छी बात यह है कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तालिबान द्वारा हाल ही में की गई हिंसा की आलोचना की है। जयशंकर ने कहा, दुनिया हिंसा और बल प्रयोग के जरिये कब्जा करने के विरुद्ध है। इस तरह के कदम को वैधता नहीं दी जानी चाहिए।

भारत को अपने पूर्व के घोषित अफगान नियंत्रित, अफगानी स्वामित्व और अफगान नेतृत्व के संकल्प पर कायम रहना चाहिए। अफगानिस्तान की व्यापक और दीर्घकालिक शांति की कुंजी इसी फार्मूले के तहत संभव है। अफगानिस्तान में चाहे किसी भी गुट की सरकार बने, हमें उनके साथ राजनीतिक संबंध मजबूत करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है।

तालिबान को लेकर भी हमें सकारात्मक नजरिया रखना चाहिए। एक बड़े कूटनीतिक कदम के तहत तालिबान ने कश्मीर को भारत को आंतरिक मामला बताया है। इसके अलावा, तालिबान ने कहा है कि अफगानिस्तान में मदद मुहैया कराने और पुनर्निर्माण कार्य जारी रखने के लिए वह भारत का स्वागत करेगा। भारत के लिए यह बड़ी राहत की बात है। पिछले 20 साल में अफगानिस्तान में ऊर्जा संयंत्र, बांध, राजमार्ग, स्कूल और संसद भवन के निर्माण में भारत ने अहम भूमिका निभाई है। अफगानिस्तान के सैनिकों को ट्रेनिंग समेत अन्य सुविधाएं भी प्रदान की हैं। भारत की योजना अफगानिस्तान में सड़क और रेल लाइन बिछाने तथा इसके माध्यम से मध्य एशिया तक तेजी से अपनी पहुंच कायम करने की है। इन सभी परियोजनाओं की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आने वाले दिनों में काबुल की सरकार के साथ हमारे संबंध कैसे होंगे।

जहां तक अफगानिस्तान की धरती से भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने जैसे खतरे का सवाल है तो तालिबान ने संकेत दिया है कि उनकी सत्ता में भागीदारी या वापसी के बाद काबुल की जमीन से भारत विरोधी गतिविधियों की इजाजत नहीं दी जाएगी। तालिबान की इस बदली हुई सोच को यदि समझने की कोशिश करें तो हम पाते हैं कि वर्ष 1996 से 2001 के बीच के तालिबान और 2021 के तालिबान में काफी फर्क है। आज तालिबान विश्व समुदाय के साथ वार्ता कर रहा है। उसे इस बात का इल्म है कि काबुल की धरती को आतंकी गतिविधि के लिए इस्तेमाल करने के क्या परिणाम हो सकते हैं। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीति की बदली हुई परिस्थिति में पाकिस्तान और सऊदी अरब भी तालिबान को एक सीमा तक ही मदद करने की स्थिति में हैं। शीत युद्ध के समय पाकिस्तान को अमेरिकी फंड मिलता था जिसका इस्तेमाल अफगानिस्तान और कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के लिए किया गया। आज की परिस्थिति में ऐसे किसी भी फंड के न होने का प्रभाव भी तालिबान के राजनीतिक व्यवहार पर पड़ना लाजमी है। अतः भारत को अपने सामरिक और आर्थिक हितों को सुरक्षित करने के लिए तालिबान के साथ बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहिए। अमेरिका और पाकिस्तान के लेंस से अफगानिस्तान को देखने की नीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

अमेरिकी सेना की अफगानिस्तान से वापसी के बाद वहां चीन की गतिविधियां बढ़ने की आशंका है। भारत के दृष्टिकोण से चीन के साथ मौजूदा सीमा विवाद के बाद ऐसी परिस्थिति अधिक चिंताजनक हो सकती है। अभी तक चीन अफगानिस्तान में आर्थिक गतिविधि तक ही सीमित रहा है, लेकिन उसकी विस्तारवादी नीति और 'वन रोड वन बेल्ट' प्रोजेक्ट से भारत को सामरिक खतरा भी हो सकता है। लिहाजा भारत को सेंट्रल एशिया और ईरान के साथ सामरिक नीति की योजना बनानी होगी।

पूर्व में भी हमने ईरान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में अपने सामरिक हितों को सुरक्षित किया है। अफगानिस्तान ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां अमेरिका और ईरान के हित में कोई टकराव नहीं है। भारत को इसका सामरिक-आर्थिक लाभ मिल सकता है। ईरान भी हजारा समुदाय के हितों को सुरक्षित करने के लिए चिंतित है। ऐसे में आने वाले दिनों की चुनौती गंभीर है। अतः भारत को एक यथार्थवादी, लेकिन अफगान केंद्रित नजरिये से रणनीति तैयार करने की जरूरत है। भारत-अफगान मैत्री के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और अपने साफ्ट पावर को प्राथमिकता सूची में शामिल करना चाहिए। भारत को अफगान नीति के केंद्र में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को अधिक महत्व देना चाहिए। वहीं सैन्य रणनीति अंतिम विकल्प होना चाहिए।

तालिबान का खतरनाक उभार

डा. पीके राय

अमेरिका सदैव अपनी लड़ाई दूसरों की भूमि पर लड़ता आया है तथा अपने नवीन सैन्य उपकरणों की क्षमता का परीक्षण विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में करता रहा है। इसका एक तो सीधा फायदा उसके हथियार निर्यात पर पड़ता है और दूसरा उन हथियारों को और भी परिष्कृत करने हेतु नवोन्मेषी विचार मिल जाते हैं। इस तरह से वह अगली पीढ़ी का हथियार बनाता जाता है तथा पुरानी पीढ़ी के हथियारों को बेचता रहता है। इस कार्य के लिए वह समुद्री द्वीपों पर सैन्य अड्डों का निर्माण करता है तथा अपने क्षेत्रीय एवं वैश्विक समीकरणों को साधने का कार्य करता है। वहीं पाकिस्तान एक धूर्त राष्ट्र है। वह अपने स्वार्थ सिद्धि हेतु भारत के खिलाफ किसी भी स्तर पर जा सकता है। उसका जन्म जहां द्वि-राष्ट्र के सिद्धांत पर धार्मिक आधार पर हुआ, वहीं अपने शैशवावस्था में ही अंधभारत विरोधवश पश्चिमी प्रभुत्व वाले क्षेत्रीय सैन्य संगठनों का हिस्सा बन गया। इन सभी प्रयासों से वह स्वयं को इस्लामिक राष्ट्रों का नेता मानने लगा। भारत से कई युद्धों में हारने और 1971 में बांग्लादेश के रूप में खंडित होने के बाद उसको यह समझ आ गया कि प्रत्यक्ष युद्ध में वह भारत से मुकाबला नहीं कर सकता। अतः उसने छद्म युद्ध के तौर पर राज्य प्रायोजित आतंकवाद को प्रश्रय देना प्रारंभ कर दिया। जनरल जिया उल हक ने 1982 में भारत को अस्थिर करने की नीति के तहत 'आपरेशन टोपैक' लांच किया जिसकी कमान आइएसआइ को सौंप दी गई। उसने अफगानिस्तान के जिहाद को कश्मीर में लांच किया तथा इनकी योजना में भारत के टुकड़े टुकड़े करना शामिल था। इसने जिहादियों की फौज तैयार करने के साथ ही अफगानिस्तान तथा गुलाम कश्मीर में इन्हें प्रशिक्षित किया। कुल मिलाकर पाकिस्तान अपने इतिहास से सीख नहीं लेता है तथा पुनः वही गलतियां दोहराता रहा है। पहले वह अमेरिका, आइएसआइ तथा सेना के सहारे देश चलाता था। अब वह चीन की गोद में बैठ चुका है। वह लोकतंत्र एवं सैन्य शासन की खिचड़ी बनकर रीढ़विहीन, परजीवी की भांति हाथ में कटोरा लिए चीन के तलवे चाट रहा है। कुटिल चीन जल्द ही अपने ऋण जाल में फंसा कर उसे भी निगल जाएगा।

अफगानिस्तान सदियों से असंख्य कबीलों में बंटा रहा है। यह सामाजिक, भौगोलिक, राजनीतिक, नृजातीय और सांस्कृतिक रूप से जटिलतापूर्वक उलझा रहा है। यहां के कबीले अत्यंत लड़ाकू प्रकृति एवं वर्चस्ववादी मानसिकता के रहे हैं। आपसी लड़ाई में वह हथियारबंद गिरोह के रूप में सक्रिय रहे हैं। सोवियत संघ के खिलाफ अमेरिका एवं पाकिस्तान द्वारा उन्हें संगठित कर भारी मात्रा में हथियार, धन एवं प्रशिक्षण दिया गया था। अपने भू-सामरिक अवस्थिति के कारण यह क्षेत्र मध्य एशिया एवं पश्चिमी एशिया पर नियंत्रण व निगरानी स्थल के रूप में महाशक्तियों के लिए बैटल ग्राउंड बनता चला गया। सोवियत रूस के वापस जाने पर जिहादियों का मनोबल बढ़ गया। अब वे किसी भी महाशक्ति से टकराने के लिए तैयार थे। परिणामस्वरूप पूरे अफगानिस्तान पर इस्लामिक कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता के सुन्नी तालिबानी शासन की स्थापना मुल्ला उमर के नेतृत्व में 1996 में हो गई। इस तालिबान आंदोलन को पाकिस्तान, सऊदी अरब एवं संयुक्त अरब अमीरात ने मान्यता प्रदान की थी।

आज के परिवेश में अफगानिस्तान सरकार और सेना का तालिबान के हाथों हार जाना विश्व में आतंकवादियों के मनोबल को बढ़ाने का कार्य करेगा। इसलिए प्रत्येक दशा में अमेरिका, भारत, चीन और अन्य शक्तियों को अफगानिस्तान की सेना का हाथ मजबूत करना चाहिए। उन्हें अत्याधुनिक हथियार मसलन ड्रोन, सर्जिकल स्ट्राइक हेतु हवाई युद्धक विमान तथा अन्य सटीक संघातक हथियार देने की अत्यंत आवश्यकता है, ताकि तालिबान को हर हाल में रोका जा सके। भारत को ज्यादा से ज्यादा स्वनिर्मित हथियारों को अफगानिस्तान भेजकर अपने दोहरे हित साधन का कार्य करना होगा।

(लेखक सामरिक विश्लेषक हैं)

खरी-खरी

साहित्य में रोजगार

श्रवण कुमार उर्मलिया

इन दिनों साहित्य का धंधा भी एक रोजगार के रूप में तेजी से फल-फूल रहा है। कुछ संभावनाओं और प्रचलित रोजगारों का उल्लेख यहां किया जा रहा है।

पहला : एक मासिक पत्रिका निकालिए और उसके लिए वार्षिक और आजीवन सदस्य बनाइए। अच्छी-खासी रकम इकट्ठी होते ही पूरी ईमानदारी से पत्रिका निकालना शुरू कीजिए। छह-छह महीने के अंतर पर पत्रिका को क्रमशः त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक और अनियतकालीन कर दीजिए और हर बार मेलिंग लिस्ट में से क्रमशः एक तिहाई आजीवन सदस्यों को तिलांजलि देते जाइए। अंततोगत्वा आजीवन सदस्यों को भूल जाइए और रकम पर आजीवन बेशर्मी से ब्याज खाते रहिए।

दूसरा : संस्था के मंच से कुछ मृत लोगों के नाम पर पुरस्कारों की घोषणा कर 500 रुपये सेवा शुल्क सहित पुरस्कार हेतु पुस्तकें आमंत्रित कीजिए। अच्छी-खासी रकम एकत्र होने के बाद अपनी चयन समिति द्वारा किसी ऐसी किताब को पुरस्कृत करवाइए, जिसका लेखक ईमानदारी से कुछ रुपये ऊपर से भिजवा दे।

तीसरा : किसी पत्रिका या साहित्यिक संस्था के मंच से साहित्यिक महाकुंभ का आयोजन कीजिए और साहित्य शिरोमणि, साहित्य शिल्पी आदि उपाधियों के लिए भागीदारी शुल्क के साथ साहित्यकारों के नाम आमंत्रित कीजिए। सरकारी संस्थानों के बड़े अधिकारियों का सम्मान करने से आसानी से विज्ञापन भी मिल जाते हैं। कुछ स्थापित लोगों से सभी को अलंकृत करवा दीजिए। जो प्रतिभागी पैसे देकर भी न आ पाएं, पूरी ईमानदारी से उनके पैसे पचा जाइए।

चौथा : इधर, बहुत से कविता सम्मेलन आयोजित करने वाले महारथी कवि सम्मलनों का ठेका लेते हैं, अपने गिरोह के कवि बुलाते हैं, उन्हें औना-पौना पारिश्रमिक देते हैं और मोटी रकम खुद पचा जाते हैं। आप भी यह धंधा शुरू कर सकते हैं।

पांचवां : साहित्य अब राष्ट्रीय स्तर तक सीमित नहीं है। कुछ रोजगारी संस्थाओं ने साहित्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा दिया है। ग्राहक फंसाने के लिए ये पुरस्कार घोषित करती हैं और विजेताओं से आने-जाने, ठहरने, खाने-पीने का खर्च वसूलती हैं।

ट्वीट-ट्वीट

ममता दीदी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस धीरे-धीरे अब सभी मर्यादाएं लांघ रही है। यह बहुत ही दुखद है। उनकी पार्टी के सांसद शांतनु सेन द्वारा राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के संबोधन के दौरान जो व्यवधान उत्पन्न कर अभद्र व्यवहार किया गया है, वह बेशर्मी की पराकाष्ठा है।
संगीता कुमारी सिंह देव@sksingh_deo

पेगासस जासूसी मामले को लेकर भारत में कहीं कोई आक्रोश व्यक्त नहीं हो रहा, जो देश के मौजूदा सूरतेहाल को बताने के लिए काफी है।
वीर सांघवी@virsanghvi

जहां तक पेगासस मामले पर हंगामे और आक्रोश की बात है तो उसे लेकर अमेरिका और यूरोप में भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है।
आर. जगन्नाथन@TheJaggi



अगर 50,000 फोन नंबरों की सूची का एनएसओ से सीधा जुड़ाव नहीं तो फिर वामपंथी अखबारों के समूह द्वारा पेगासस जासूसी रिपोर्ट की विश्वसनीयता को लेकर सवाल जरूर उठते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल को इस पर स्पष्ट जवाब देना होगा।
राहुल शिवशंकर@RShivshankar

इंसान भी बहुत कमाल है, पसंद करे तो बुराई नहीं देखता... नफरत करे तो अच्छाई नहीं देखता।
अरुण गोविल@arungovil12

उद्यमिता में नवाचार के लाभ

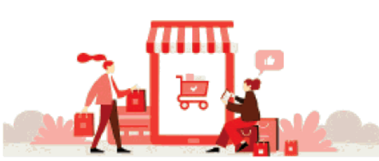


गौतम बाली
मैनेजिंग डायरेक्टर,
वेस्टीज

महामारी के दौरान कंपनियों, सरकारों और संस्थानों को तेजी से बदलते समय में खुद को ढालते देखा गया है। जिस तरह से परिचालन का तरीका आफलाइन से आनलाइन, आफिस से घर, केंद्रीकृत से विकेंद्रीकृत हुआ है, उसमें उद्योगों में भीतरी और बाहरी दोनों स्तर पर बदलाव हुए हैं। भारत की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने भी इन तमाम बदलावों का सामना किया है।

महामारी की अनिश्चितता के दौरान, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने अपने लचीलेपन, विकेंद्रीकरण और रिमोट वर्किंग के दम पर अपने परिचालन को फिर से परिभाषित किया और नया आकार दिया। इसने पर्सनलाइज्ड सेलिंग के साथ आनलाइन दुनिया को प्रभावी तरीके से जोड़ा और व्यक्तिगत क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण व अपस्किलिंग में टेक्नोलाजी का इस्तेमाल किया। इससे जमीनी स्तर पर आर्थिक समावेशन के रूप में आजीविका को बढ़ावा देने की उद्योग की प्रभाविता में निखार आया।

रोजगार में परिवर्तनकारी बदलाव, वर्क फ्राम होम की शुरुआत और पिछले एक साल में उत्पादों व सेवाओं की आनलाइन डिलीवरी ने कंपनियों को विकेंद्रीकृत परिचालन की ओर प्रेरित किया है। डायरेक्ट सेलिंग स्वाभाविक रूप से इसी दृष्टिकोण पर निर्मित है। परिस्थितियों के अनुरूप ढलने की डायरेक्ट सेलिंग सेक्टर की क्षमता और इसका लचीलापन महामारी के दौरान इस सेक्टर के विकास के रूप में सामने आया। एसोचैम के अनुसार इस इंडस्ट्री का कारोबार इस वर्ष के अंत तक 15,930 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा, जो वर्ष 2016 में 12,620 करोड़ रुपये था। यह वृद्धि मुख्य रूप से वेलनेस, न्यूट्रिशन और अन्य एफएमसीजी उत्पादों पर आधारित होगी। उपभोक्ताओं का रुझान न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, इम्युनिटी बूस्टर के साथ-साथ हाइजीन से जुड़े उत्पादों की ओर बढ़ रहा है।



उद्यमिता को प्रोत्साहित करने में पूरी तरह से सक्षम है डायरेक्ट सेलिंग उद्योग। प्रतीकात्मक

वर्ल्ड फेडरेशन आफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष विक्रेताओं की कुल संख्या 2018-19 में 57 लाख थी जिसके वर्ष 2025 तक बढ़कर 1.8 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है।

महामारी के दौरान लोगों को औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी, वेतन कटौती और नौकरी जाने जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ा। ऐसे में प्रभावित लोगों के लिए डायरेक्ट सेलिंग अतिरिक्त आय के साथ एक आकर्षक वैकल्पिक करियर हो सकती है। इस परिदृश्य में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आकर्षक साबित हुई, क्योंकि लोग आय के नए और वैकल्पिक स्रोतों की तलाश कर रहे हैं, जो स्थायी एवं भरोसेमंद हो। इस इंडस्ट्री ने लाखों लोगों को एक वैकल्पिक करियर प्रदान किया और कई परिवारों को जीवन रेखा प्रदान की।

डायरेक्ट सेलिंग स्वाभाविक रूप से बेहतर आर्थिक स्थिरता और सामाजिक प्रभाव के लिए उद्यमिता को बढ़ावा देती है। यह न केवल आर्थिक स्तर पर, बल्कि सामाजिक मानकों पर भी ऊपर उठने में मदद करती है। टेक्नोलाजी और डिजिटल इंडिया के साथ ने उद्योग में नए नियमों को आकार दिया है। मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टेक्नोलाजी का उपयोग करने के अलावा कंपनियां आनलाइन प्रशिक्षण और विकास के लिए जरूरी अन्य माध्यमों में तेजी से निवेश कर रही हैं। इससे बेहतर प्रशासन के साथ उद्यमिता के क्षेत्र में पारदर्शी व आत्मनिर्भर कारोबार का माडल तैयार हो रहा है। भारतीय घरेलू डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां देशभर में लोगों की भर्ती करके रोजगार के नए अवसर पैदा कर रही हैं। एक राष्ट्र के रूप में, हमारा उद्देश्य हर इंडस्ट्री और सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाना व यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि प्रत्येक नागरिक आत्मनिर्भरता को अपनाए। यह इंडस्ट्री इस बदलाव के लिए उत्प्रेरक की तरह काम कर रही है।

आज भले ही हमारा देश युवा आबादी वाला है, परंतु इस दशक के अंत तक भारत में दुनिया की सबसे अधिक कामकाजी उम्र वाली आबादी होगी। हालांकि रोजगार के मौजूदा अवसर इसका फायदा उठाने से बहुत दूर हैं। सेंटर फार मानिटरिंग इंडियन इकोनोमी के आंकड़ों के मुताबिक 20 से 24 आयु वर्ग के करीब 37 प्रतिशत लोग बेरोजगार हैं। विश्व बैंक की साउथ एशिया इकोनोमिक 2018 की रिपोर्ट के अनुसार इस आयु वर्ग में हर महीने 13 लाख लोग बढ़ रहे हैं। इस युवा कामकाजी आबादी को अपनी आजीविका के लिए अवसरों की जरूरत है।

इस बीच महामारी भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। हम इसके उतार-चढ़ाव से पार पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसके बदलते रूप के साथ ढलना हमारे लिए जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इसमें सक्षम है। इस समय दुनियाभर की सरकारें अपने नागरिकों को घरों ही रहने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं, जिससे रिटेल कारोबार में बड़ा बदलाव आया है। शारीरिक दूरी महामारी खत्म होने के बाद भी बनी रहेगी, क्योंकि ग्राहक सुरक्षित और व्यवस्थित सेवाएं चाहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग कारोबार के लिए बिल्कुल उन परिभाषाओं जैसी ही है, जिनके बारे में महामारी के ऐसे दौर में सोचा जा सकता है। आने वाले समय में आवाजाही पर प्रतिबंध हटने के बाद भी कारोबार का यह तरीका फलता-फूलता रहेगा।

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या राज्य सरकारें यह नहीं बताना चाहतीं कि उनके यहां कितने लोग आक्सीजन की कमी से मरे?



सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या मंत्री के हाथ से कागज छीनने वाले सांसद को संसद के शेष सत्र से निलंबित किया जाना चाहिए?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

बाभन-ठाकुर वाद का शुरू हो गया खेल,
जिनसे कभी दुराव था अब उनसे ही मेल।
अब उनसे ही मेल सियासत सब करवाए,
मांग रहे वो वोट जिन्हीं से थे भरपाए।
कुर्सी खातिर लोग बदलते दिखते हैं मन,
ज्यों माया को आज सगे लगते हैं बाभन!
- ओमप्रकाश तिवारी

मंथन

मुफ्तखोरी बनाम विकास का चुनावी एजेंडा



मनु त्यागी
manu@nda.jagran.com

वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में गुजरात माडल देशभर में चर्चा में रहा और लोगों ने इसे हाथोंहाथ लिया। तब से लगभग हर पार्टी या फिर स्वयं को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत करने वाले या सपना देखने वाले मुख्यमंत्री चुनावी सफलता का शार्टकट माडल बनाने और उसके जरिये अपने वोटों का गणित बैठाने में जुटा है। इनमें से एक लोकलुभावन या फिर मुफ्तखोरी का माडल भी है। इसे वोटों की खरीद का माडल भी कह सकते हैं। लेकिन दिल्ली में सफलता के बाद अब हर राज्य में किसी न किसी बहाने मुफ्तखोरी का माडल प्रमोट करने की होड़ लग गई है। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा हो गई। दिल्ली के बाद यही दांव अब दूसरे राज्यों में चला गया है। अच्छी बात है। जहां तक वोटरों में सियासी करंट दौड़ाने का सवाल है, तो इसकी घोषणा में भी करंट और तारतम्यता जरूरी है। ये सियासी करंट चुनाव के समय इन राज्यों में कितना हाइवोल्टेज ड्रामा उत्पन्न करेगा यह तो वक्त ही बताएगा।

फिलहाल एक राज्य से निकल केंद्र में सत्ता की बिसात तैयार करने को राज्य दर राज्य पैठ बनाने की रणनीति तेजी से चल रही है। हालांकि क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का यह फार्मूला राष्ट्रीय राजनीति में अभी तक नाकाम ही रहा है। ऐसे लोकलुभावन वादों के दम पर राजनीति का शिखर फतह करने को छटपटा रहे दलों पर आज से तकरीबन 18 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी कटाक्ष किया था, 'देशवासियों को देशहित में राष्ट्रीय दलों को ही वोट करना चाहिए। क्षेत्रीय दलों के मजबूत होने से केंद्र में मजबूत नहीं, बल्कि मजबूर सरकार बनती है।' उनके इस बयान में आज की हकीकत भी साफ नजर आती है। आडवाणी ने हरियाणा के जिला पलवल की भूमि पर एक राजनीतिक आयोजन के दौरान यह बयान दिया था। हालांकि इसके बावजूद हरियाणा की भूमि से भी ऐसे ही बीज उपजे थे, जिन्होंने प्रदेश में पेंशन योजना को शुरू करने और किसानों के कर्ज माफी जैसी घोषणाओं के दम पर जनता का मन जीता था। यहां बात देवीलाल की हो रही है। जनता के प्रचंड बहुमत ने ऐसा हौसला बढ़ा दिया कि दांव केंद्र की राजनीति का लगा बैठे। लेकिन, ये जनता है सब जानती है, जो उसकी सुनता है उसे ही सालती है।



मुफ्त बिजली या फिर बिल में छूट के माध्यम से मतदाताओं को लुभाने की बढ़ती प्रवृत्ति। फाइल

दरअसल, यहां देवीलाल यह भूल बैठे कि जनता ने उन्हें अपने लिए आगे बढ़ाया है। जन सर्वोपरि सरोकार है, लेकिन यह भी सर्वविदित है कि सत्ता मिलते ही स्वार्थ की राजनीति हावी हो जाती है। तभी तो देवीलाल ने 1989 में केंद्र का रुख किया। केंद्र की सत्ता तक पहुंचे भी। उप-प्रधानमंत्री बने भी, लेकिन हरियाणा छूट गया। हालात ऐसे बने कि तीन साल बाद प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। हरियाणा की जनता उन्हें भूल गई। आज उस पार्टी का हरियाणा में अस्तित्व तलाशने पर भी नहीं मिलता। आज इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) का एक भी विधायक नहीं बचा है। हां, उनका प्रपौत्र जरूर जननायक जनता पार्टी (जजपा) के दम पर हरियाणा सरकार में हिस्सेदारी बनाए हुए है।

देश में सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के ही क्षेत्रीय दलों को देख लीजिए। उनकी छटपटाहट भी कम नहीं रही। समाजवादी पार्टी ने छात्रों को मुफ्त लैपटाप और बेरोजगारी भत्ता बांटकर युवा और अभिभावकों को वोट के लिए सम्मोहित किया।

मुफ्त की राजनीति सिर्फ लालच भरी नहीं होती, एक तरह से कुछ दिन या समय के लिए मनुष्य को सम्मोहित भी कर लेती है। किसी भी मुफ्त योजना के पीछे वोट का लेबल जरूर लगा रहता है। उस उत्पाद में छूट, मुफ्त... मुफ्त... मुफ्त... में पार्टी का ब्रांड होता है। इसकी बंदरबांट में जनहित, सामाजिक सरोकार, मौलिक सिद्धांत को छोड़ सबकुछ होता है। कमोबेश आजकल लगभग सभी पार्टियां ऐसा करती हैं, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों ने इसे फार्मूले की तरह अपनाया हुआ है, ताकि इसके जरिये राज्य या एक खास क्षेत्र से निकलकर केंद्र तक पहुंचा जा सके। बिलकुल वैसे ही जैसे क्रिकेट में रणजी टूर्नामेंट खेलने के बाद हर खिलाड़ी नेशनल टीम में शामिल होने का सपना देखने लगता है। यह जरूरी है, और देखना भी चाहिए, लेकिन हर कोई वहां चल पाए यह भी तो संभव नहीं। और यहां तो राजनीति का चौसर है। अब एकमात्र मुफ्तखोरी के फार्मूले के साथ अपने राज्य या फिर क्षेत्र की जनता कितने दिन आपको सिर आंखों पर बैठाएगी? आप वहां से गए तो समझिए कि उस राज्य में आपको अपना अस्तित्व बचाए रखने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पार्टी सिमटती, सिकुड़ती चली जाएगी। कम से कम अभी तक तो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का इतिहास यही दर्शाता है। समाजवादी पार्टी की 'लैपटाप वाली तस्वीर' से मुलायम सिंह यादव भी वर्ष 2014 के चुनाव में तीसरे मोर्चे के बूते केंद्र में मुंगेरी लाल की तरह हसीन सपने ही देखते रह गए थे। सिर्फ मुलायम ही नहीं, हर क्षेत्रीय दल का वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री बनना चाहता था।

निश्चित ही आम आदमी पार्टी के सपने भी कुछ ऐसे ही हैं, लेकिन क्या दिल्ली से किए वादे पूरे हो पाए हैं। जिन वादों की नींव अब दूसरे राज्यों में डाली जा रही है, जिनके बूते उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात, गोवा और उत्तर प्रदेश में खुद को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, उनकी हकीकत दिल्ली जानती है। चाहे शिक्षा का माडल हो या मोहल्ला क्लीनिक और बात चाहे 200 यूनिट मुफ्त बिजली की हो, दिल्ली सब जानती है। राष्ट्रीय राजनीति का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ विकास और विचारधारा का हो सकता है।

स्वर्णिम दास्तां लिखने को तैयार

भारत के होनहार

टोक्यो ओलिंपिक में 127 भारतीय एथलीट पदक जीतने के लिए जान लगा देंगे। निशानेबाजी में मनु भाकर, दिव्यांश, इलावेनिल, सौरभ चौधरी, कुश्ती में बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, बैडमिंटन में पीवी सिंधू, मुक्केबाजी में अमित पंघाल, मेरी कोम और एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। इसके अलावा भारतीय हाकी टीम भी उलटफेर करने का माद्दा रखती है।

मनु भाकर

उम्र : 19 साल
निशानेबाजी : 10 मीटर एयर पिस्टल

2 विश्व रैंकिंग

स्वर्ण पदक 2019 आइएसएसएफ विश्व कप फाइनल्स व्यक्तिगत स्पर्धा और मिक्स्ड टीम

रजत पदक 2021 आइएसएसएफ विश्व कप



निशानेबाजी में इस बार सबसे बड़ा 15 लोगों का भारतीय दल भाग ले रहा है। इसमें कई शानदार युवा खिलाड़ी हैं, जिसमें मनु भाकर का नाम भी शामिल है। मनु ने भी कम समय में सटीक निशाने लगाते हुए निशानेबाजी विश्व कप में नौ तो निशानेबाजी विश्व कप फाइनल्स में दो पदक हासिल किए हैं। इसके अलावा मनु की सौरभ चौधरी के साथ जोड़ी भी विश्व में शीर्ष वरीय मानी जाती है। मिक्स्ड टीम स्पर्धा में यह जोड़ी ओलिंपिक में पदक की दावेदार मानी जा रही है।

सौरभ चौधरी

उम्र : 19 साल
निशानेबाजी : 10 मीटर एयर पिस्टल

2 विश्व रैंकिंग

स्वर्ण पदक 2018 एशियाई खेल

रजत पदक 2019 एशियाई चैंपियनशिप

महज 19 साल की उम्र में सौरभ ने आठ विश्व कप स्वर्ण पदक अपने नाम किए। उन्होंने जूनियर और सीनियर वर्ग में भी अपने सटीक निशाने से विश्व रिकार्ड अंक हासिल किए थे। विश्व रैंकिंग में हमवतन साथी अभिषेक वर्मा को भी पछाड़ने वाले सौरभ मनु भाकर के साथ भी जोड़ी बनाकर मैदान में उतरेंगे। जो विश्व की शीर्ष मिक्स्ड डबल्स जोड़ी में शामिल हैं। फार्म में नजर आने वाले सौरभ से भी ओलिंपिक में गोल्डन निशाने की उम्मीदें हैं।

इलावेनिल वलारिवान

उम्र : 21 साल
निशानेबाजी : 10 मीटर एयर राइफल

1 विश्व रैंकिंग

स्वर्ण पदक 2019 आइएसएसएफ विश्व कप फाइनल्स

रजत पदक 2018 विश्व चैंपियनशिप



गगन नारंग के सानिध्य में निशानेबाजी की बारीकियां सीखने वाली युवा इलावेनिल वलारिवान ने अपनी निरंतरता के चलते टोक्यो ओलिंपिक में जगह बनाई। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में उन्हें ओलिंपिक कोटा प्राप्त कर चुकी अंजुम मौद्गिल की जगह मिली। विश्व में नंबर एक पायदान पर काबिज वलारिवान तमाम टूर्नामेंट में सटीक निशाना लगाने के बाद अब ओलिंपिक में भी पदक पर निशाना लगाकर अपना नाम इतिहास में दर्ज कराना चाहेंगी।



बजरंग पूनिया

उम्र : 27 साल
कुश्ती (फ्रीस्टाइल)– 65 किग्रा

1 विश्व रैंकिंग

स्वर्ण पदक 2018 एशियाई खेल

रजत पदक 2018 विश्व चैंपियनशिप

कांस्य पदक 2019 विश्व चैंपियनशिप

कुश्ती के मैदान का स्तर जितना ऊंचा होता है, बजरंग पूनिया को उसमें दांव लगाना भी उतना ही अधिक रास आता है। पिछले तीन सालों से कुश्ती में बजरंग ने कोई भी ऐसा टूर्नामेंट नहीं छोड़ा, जिमसें उन्होंने पदक ना जीता हो। हरियाणा का यह पहलवान ताकत, तेजी और कौशल का संपूर्ण पैकेज नजर आता हैं। चोटों से खुद को दूर रखने वाले बजरंग ने ओलिंपिक से पहले अमेरिका और विभिन्न यूरोपीय देशों की कुश्ती संस्कृति को भी खुद में समाहित कर लिया है, जिसके बूते इस बार वह ओलिंपिक के अखाड़े में स्वर्ण पदक जीत के मजबूत दावेदार नजर आ रहे हैं।

नीरज चोपड़ा

उम्र : 23 साल,
भाला फेंक

4 विश्व रैंकिंग

स्वर्ण पदक 2018 एशियाई खेल, 2018 राष्ट्रमंडल खेल

नीरज के थ्रो से तय की गई सर्वश्रेष्ठ दूरी – 88.07 मीटर
पदक की संभावना – 90 मीटर

2016 रियो ओलिंपिक में पदक के लिए तय की गई दूरी : 90.3 मीटर (स्वर्ण पदक), 88.24 (रजत पदक), 85.38 (कांस्य पदक)

2016 जूनियर विश्व चैंपियनशिप के बाद नीरज ने दिन दूनी रात चौगुनी सफलता हासिल की, यही कारण है कि उनका नाम ओलिंपिक में पदक के दावेदारों में माना जा रहा है। नीरज ने हाल ही में भारत में संपन्न हुई इंडियन ग्रांप्रि में अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो से 88.07 मीटर दूर भाला फेंका था। ओलिंपिक में उनके सामने जर्मनी के जोहनेस वेटर की कड़ी चुनौती होगी, जो लगातार 92 से 93 मीटर दूर भाला फेंक रहे हैं। नीरज अगर 90 मीटर के करीब भाला फेंकने में कामयाब होते हैं तो वह पदक चूमते नजर आ सकते हैं।

विनेश फोगाट

उम्र : 26 साल
कुश्ती (फ्रीस्टाइल)– 53 किग्रा

1 विश्व रैंकिंग

स्वर्ण पदक 2021 एशियन चैंपियनशिप

रजत पदक 2018 एशियाई खेल

कांस्य पदक 2019 विश्व चैंपियनशिप

2016 रियो ओलिंपिक में घुटने की चोट से विनेश फोगाट के पदक जीतने का सपना टूट गया था। इस चोट से वह काफी मायूस हो गई थीं और उस समय उनकी आखों से आंसू तक आ गए थे। ऐसे में दर्द को दिल में दबाकर विनेश ने हार नहीं मानी और चोट ठीक होने के बाद सर्वश्रेष्ठ लय हासिल करते हुए कुश्ती के अखाड़े में कदम रखा। यही कारण है कि इस साल कुश्ती में अभी तक उन्हें कोई भी खिलाड़ी हरा नहीं सकी है और लगभग हर एक टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतते हुए विनेश ने ओलिंपिक में प्रवेश किया। इससे साफ नजर आता है कि शानदार लय में नजर आने वाली विनेश भारत को पदक दिलाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

एमसी मेरी कोम

उम्र : 38 साल
मुक्केबाजी : 51 किग्रा

3 विश्व रैंकिंग

स्वर्ण पदक 2018 विश्व चैंपियनशिप

रजत पदक 2021 एशियाई चैंपियनशिप

कांस्य पदक 2012 लंदन ओलिंपिक

38 साल की उम्र में भी मुक्केबाजी रिंग में तितली की तरह चपलता दिखाने को तैयार एमसी मेरी कोम हर हाल में ओलिंपिक पदक का रंग बदलना चाहती हैं। छह बार की विश्व चैंपियन मेरी कोम ने ओलिंपिक को लेकर हाल ही में दैनिक जागरण से कहा था कि वह सब कुछ हासिल कर चुकी हैं और इस बार ओलिंपिक स्वर्ण पदक पर ही नजरें हैं। मेरी कोम का यह अंतिम ओलिंपिक भी हो सकता है, जिसके चलते उन पर सभी प्रशंसकों की विशेष नजरें होंगी।

अमित पंघाल

उम्र : 25 साल
मुक्केबाजी : 52 किग्रा

1 विश्व रैंकिंग

स्वर्ण पदक 2018 एशियाई खेल

रजत पदक 2019 विश्व चैंपियनशिप

तीन साल के अंदर भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल ने रिंग में जोरदार पंच लगाते हुए अपने नाम का डंका पूरे विश्व में बजवा दिया। वह एकमात्र ऐसे भारतीय मुकेक्बाज हैं जिन्होंने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में फाइनल तक का सफर किया। टोक्यो ओलिंपिक में पंघाल को पहली वरीयता दी गई है, जिसका मतलब वह ओलिंपिक स्वर्ण पदक के काफी करीब हैं। ऐसे में फिट पंघाल अगर रिंग में अपने पंचों की लय कायम रखते हैं तो वह भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में देरी नहीं लगाएंगे।

दिव्यांश सिंह पंवार

उम्र : 18 साल
निशानेबाजी : 10 मीटर एयर राइफल

2 विश्व रैंकिंग

स्वर्ण पदक 2019 आइएसएसएफ विश्व कप (पुतियन, चीन)

रजत पदक 2019 आइएसएसएफ विश्व कप(बीजिंग, चीन

दिव्यांश ने 12 साल की उम्र में निशानेबाजी सीखना शुरू किया था और महज छह साल बाद उन्होंने विश्व में नंबर दो रैंकिंग हासिल करते हुए टोक्यो ओलिंपिक में जगह बनाई। दिव्यांश को कहीं पबजी गेम की लत ना लग जाए इस डर से उनके पिता अशोक कुमार ने उन्हें दिल्ली के कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में दाखिला दिलवा दिया। इसके बाद दिव्यांश ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और 2019 में संपन्न हुए छह निशानेबाजी विश्व कप में उन्होंने चार स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य पदक अपने नाम किया था। इस तरह विश्व में नंबर दो पर काबिज दिव्यांश 10 मीटर एयर राइफल में अगर गोल्डन निशाना लगाते हैं तो 2008 बीजिंग ओलिंपिक में इसी सपर्धा का स्वर्ण पदक जीतने वाले अभिनव बिंद्रा की विरासत को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा मिक्स्ड टीम में वह विश्व नंबर दो अंजुम मौद्गिल के साथ भी जोड़ी बनाकर भाग लेंगे।

पीवी सिंधू

उम्र : 26 साल
बैडमिंटन महिला सिंगल्स

7 विश्व रैंकिंग

स्वर्ण पदक 2019 विश्व चैंपियनशिप

रजत पदक 2016 रियो ओलिंपिक

रियो ओलिंपिक में स्वर्ण पदक के मैच में स्पेन की कैरोलिना मारिन से हारने वाली पीवी सिंधू से देश को इस बार स्वर्णिम उम्मीदें हैं। टोक्यो ओलिंपिक में मारिन भाग नहीं ले रही हैं, जिससे सिंधू के स्वर्ण पदक का रास्ता आसान माना जा रहा है। हालांकि अन्य शीर्ष खिलाड़ी भी सिंधू को कड़ी चुनौती दे सकती हैं। मगर अपने कोरियन कोच के साथ सिंधू मिशन ओलिंपिक पर हैं और अगर वह 2019 विश्व चैंपियनशिप के जैसा धमाकेदार प्रदर्शन करती हैं तो स्वर्ण पदक उनके गले में होगा।

डिजाइन : संजीव कुमार

पदकों की संख्या दोहरे अंकों में पहुंचने की उम्मीद

पीटी ऊषा
कलम से



महामारी के मौजूदा हालात के बीच ओलिंपिक का आयोजन अपने आप में इन खेलों के मूल्यों को दिखाता है। पिछले लगातार वर्षों में ओलिंपिक पर मानवता के विकास की परछाई नजर आती रही है। आप 100 मीटर की रेस का ही उदाहरण ले लीजिए। 1896 के ओलिंपिक स्वर्ण विजेता ने 12 सेकेंड का समय लिया था, जबकि आज की तारीख में ये रिकार्ड 9.58 सेकेंड का है। बात भारतीय दल की करते हैं, जो काफी मजबूत नजर आ रहा है। भारत अपने पदकों की संख्या दोहरे अंकों में पहुंचा सकता है। जिन खेलों में मुझे पदक की उम्मीद है उनमें निशानेबाजी, कुश्ती, मुक्केबाजी, बैडमिंटन, तीरंदाजी और एथलेटिक्स शामिल हैं। निशानेबाजी में भारत को कम से कम चार पदक मिलेंगे ही। पदक दिलाने की होड़ में सौरभ चौधरी, मनु भाकर, सरनोबत और अंजुम मौदगिल हैं तो वहीं अभिषेक वर्मा, यशस्विनी देसवाल और दीपक भी चौंकाने का दम रखते हैं।

कुश्ती में विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कमाल कर सकते हैं। मुक्केबाजी में हमारे पास दुनिया के नंबर एक मुक्केबाज अमित पंघाल हैं और एमसी मेरी काम भी। बैडमिंटन ऐसा खेल रहा है जिसमें पिछले दो ओलिंपिक से भारत को पदक मिलते रहे हैं। उम्मीद है कि इस बार भी पीवी सिंधू इस परंपरा को कायम रखेंगी। तीरंदाजी में हमारे पास विश्व नंबर एक दीपिका कुमारी हैं। अब बात करते हैं मेरे पसंदीदा एथलेटिक्स की। मुझे उम्मीद है कि नीरज चोपड़ा पुरुष भाला फेंक वर्ग में आजाद भारत के बाद देश को एथलेटिक्स में उसका पहला पदक दिलाएंगे। इसके अलावा मुझे उम्मीद है कि 3000 मीटर स्टीपलचेज और पुरुष शाट पुट वर्ग में भारतीय एथलीट फाइनल तक जरूर पहुंचेंगे। भारतीय दल को शुभकामनाएं। (टीसीएम)

नागल का पहले दौर में इस्तोमिन से होगा मुकाबला

ओलिंपिक डायरी

टोक्यो, प्रेट्र : भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में उज्बेकिस्तान के डेनिस इस्तोमिन से भिड़ेंगे। विश्व रैंकिंग में 160वें स्थान पर काबिज नागल अगले दौर में दूसरी वरीयता प्राप्त रूस के डेनिल मेदवेदेव से खेल सकते हैं, जो पहले दौर में एलेक्जेंडर बुबलिक का सामना करेंगे। महिला डबल्स में छह बार की ग्रैंडस्लैम चैंपियन सानिया मिर्जा और अंकिता रैना का सामना पहले दौर में यूक्रेन की नादिया और युडमाइला से होगा।

अमित पंघाल को मिली बाई

विश्व नंबर एक मुक्केबाज अमित पंघाल (52 किग्रा), सतीश कुमार (91 किग्रा से अधिक), लवलीना बोरगोहेन (69 किग्रा) और सिमरनजीत कौर (60 किग्रा) को पहले दौर में बाई मिली है। पंघाल 31 जुलाई को प्री क्वार्टर फाइनल में बोत्सवाना के ओतुकिले और कोलंबिया के हर्नी रिवास मार्टिनेज के बीच होने वाले मुकाबले के विजेता से भिड़ेंगे। एमसी मेरी कोम (51 किग्रा) 25 जुलाई को डोमिनिका की मिगुलिना हर्नानडेज से भिड़ेंगी।

सुशीला का कड़ा मुकाबला

भारतीय जुडोका सुशीला देवी को मुश्किल ड्रा मिला है और उन्हें शनिवार को पहले दौर में ही लंदन ओलिंपिक 2012 की कांस्य पदक विजेता हंगरी की इवा सेरनोविस्की का सामना करना होगा। 26 वर्षीय सुशीला जूडो में भारत की एकमात्र खिलाड़ी हैं और यदि वह पहली बाधा पार कर लेती हैं तो उन्हें अगले दौर में स्थानीय खिलाड़ी फुना तोनाकी से भिड़ना होगा, जो 2017 की विश्व चैंपियन हैं। सुशीला 48 किग्रा भार वर्ग में अपनी चुनौती पेश करेंगी।

भारत की जैकेट पहने दिखा युगांडा का फरार एथलीट

भारतीय अधिकारियों के दल में तब हड़कंप मच गया जब युगांडा का भारोत्तोलक जूलियस सेकिटोलेंको हवाई अड्डे पर भारत की ट्रैक जैकेट पहने हुए दिखाई दिया। जूलियस ओलिंपिक के पूर्व अभ्यास के दौरान भाग गए थे जिसके चार दिन बाद उन्हें उनके देश रवाना कर दिया गया। आइओए के महासचिव राजीव मेहता ने कहा, 'यह जैकेट टोक्यो ओलिंपिक में भारत की राष्ट्रीय ओलिंपिक समिति का नहीं है।'

विश्व स्तर पर स्वर्ण पदक के दावेदार



मेगन रापिनो

कप्तान महिला फुटबाल टीम, अमेरिका

दो बार (2015 और 2019) की फीफा महिला विश्व कप विजेता और लंदन 2012 की स्वर्ण पदक विजेता अमेरिकी फुटबालर मेगन रेपिनो पर सबकी नजरें होंगी। अमेरिका महिला फुटबाल की कप्तान व फारवर्ड खिलाड़ी मेगन ने मैदान के बाहर भी अपने हक की लड़ाई लड़ी है। वह एक सैमलैंगिक एथलीट हैं और इस बात को उन्होंने जगजाहिर कर दिया था। इसके बावजूद उन्होंने फुटबाल के मैदान पर रफ्तार जारी रखी और 2019 में फीफा की सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबालर के पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया। इन उपलब्धियों से साफ जाहिर है कि मेगन की नजरें अपनी टीम को एक बार फिर ओलिंपिक में स्वर्ण पदक दिलाने पर होंगी।



सिमोन बाइल्स

जिमनास्ट, अमेरिका

जिस तरह एथलेटिक्स में बोल्ट का और तैराकी में माइकल फेल्प्स का दबदबा था, उसी तरह जिमनास्टिक्स में सिमोन के आगे कोई नहीं टिक सका है। साल 2016 रियो ओलिंपिक में जिमनास्ट की चार प्रतिस्पर्धाओं में चार स्वर्ण पदक अपने नाम करने वाली सिमोन एक बार फिर जापान में अपनी कलाओं से सभी का दिल जीतने के लिए तैयार हैं। यही कारण है कि जिमनास्टिक्स में सिमोन को स्वर्ण पदक का प्रमुख दावेदार माना जा रहा है।



नोवाक जोकोविक

टेनिस, सार्बिया

रोजर फेडरर और राफेल नडाल के बराबर 20 ग्रैंडस्लैम हासिल करने वाले जोकोविक अगर ओलिंपिक में स्वर्ण पदक और उसके बाद यूएस ओपन भी अपने नाम कर लेते हैं तो एक ही साल में गोल्डन स्लैम (चारों ग्रैंडस्लैम और ओलिंपिक स्वर्ण पदक) हासिल करने वाले एकलौते पुरुष टेनिस खिलाड़ी बन जाएंगे। यह कारनामा एकमात्र टेनिस खिलाड़ी स्टेफी ग्राफ ने 1988 में किया था। जोकोविक के लिए ओलिंपिक की राह आसान नजर आ रही है कि क्योंकि नडाल और फेडरर ओलिंपिक में भाग नही ले रहे हैं।



कार्स्टन वारहोम

400 मीटर बाधा दौड़, नार्वे

कार्स्टन वारहोम ने एथलेटिक्स की 400 मीटर बाधा दौड़ में 29 साल पुराना रिकार्ड तोड़ा था। उन्होंने अमेरिका के केविन यंग के 1992 में बनाए रिकार्ड को तोड़ा। 400 मीटर बाधा दौड़ के शीर्ष खिलाड़ियों में कार्स्टन का नाम शुमार है। कार्स्टन ने यह दौड़ 46.7 सेकेंड में पूरी की थी। अमेरिकी राय बेंजामिन (46.83 सेकेंड) और कतर के अब्दुर रहमान (46.98 सेकेंड) भी पदक के दावेदार हैं।

97.69 फीसद परीक्षार्थी पास हो गए हैं बंगाल बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा में। इस बार कुल 8,19,202 परीक्षार्थियों में 7,99,088 परीक्षार्थी पास हुए हैं। 60 फीसद या उससे अधिक नंबर पाने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या 3,19,327 है, जो पिछले साल की तुलना में कम है।

राजमार्ग पर प्रशस्त–प्रवाहित होगी आस्था की धार

रामनगरी के 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को राजमार्ग घोषित किया गया है

अयोध्या सहित बस्ती, अंबेडकरनगर, बाराबंकी एवं गोंडा से होकर गुजरता है परिक्रमा मार्ग

रघुवरशरण, अयोध्या

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रामनगरी के जिस 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को राजमार्ग के रूप में उच्चीकृत करने की अधिसूचना जारी की है, उस मार्ग पर रामनगरी की आध्यात्मिकता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत प्रवाहमान है। वर्ष की अलग-अलग तिथियों और पुण्य पर्वों पर रामनगरी की तीन परिक्रमा होती हैं। पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा क्रमशः कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी एवं नवमी के दिन होती है, जबकि 84 कोसी परिक्रमा की शुरुआत चैत्र मास की पूर्णिमा से होती है। जहां अन्य परिक्रमा की शुरुआत रामनगरी से लगी परिधि में होती है, वहीं 84 कोसी परिक्रमा की शुरुआत रामनगरी से 15 किलोमीटर दूर बस्ती जिला के मखौड़ा नामक स्थान से होती है।

मान्यता है कि इसी स्थल पर युगों पूर्व राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति की कामना से यज्ञ किया था। यहां से आगे बढ़ती हुई 84 कोसी परिक्रमा पुण्यसलिला सरयू के किनारे पहुंचती है और सरयू को पार करती हुई बस्ती से अंबेडकरनगर जिले में दाखिल होती है। चैत्र पूर्णिमा से लेकर वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी यानी मां सीता की जयंती के बीच 24 दिन तक तक चलने वाली अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा में बस्ती और अंबेडकरनगर सहित अयोध्या, बाराबंकी एवं गोंडा जिले के कई स्थल शामिल हैं। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्रदास इस परिक्रमा मार्ग को राजमार्ग का दर्जा दिए जाने से अत्यंत उत्साहित नजर आते हैं और इसके लिए वे प्रधानमंत्री तथा सड़क परिवहन मंत्री सहित पूरी भाजपा सरकार के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हैं। उनका मानना है कि इस निर्णय से अयोध्या की आध्यात्मिकता नए सिरे से गौरवान्वित हुई है।

84 कोसी परिक्रमा की परिधि से लगे गोंडा जिला के ग्राम सिधौटी निवासी सेवानिवृत्त जिला होम्योपैथिक अधिकारी डा.चंद्रगोपाल पांडेय के अनुसार यह घोषणा अयोध्या के साथ उसकी वृहत्तर परिधि में शामिल बस्ती, अंबेडकरनगर, बाराबंकी एवं गोंडा जिला के स्थलों के लिए भी नई संभावनाओं जगाने वाली है और इससे रामनगरी की वृहत्तर परिधि में गौरवबोध का संचार हुआ है।



विजयी भव :

हर वो घटना, हर वो बात जिससे हमारा सिर गर्व से ऊंचा होता है, हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, ऐसी हर शख्सीयत, हर भारतीय के लिए हमारे दिल से यही शब्द निकलते हैं, 'शुभकामनाएं, विजयी भव :'। कुछ यही अंदाज होता है महादेव की नगरी में बसे काशीवासियों का। अपने इसी अंदाज के साथ वाराणसी में दशाश्वमेध घाट के सामने गंगा के पार रेत में गुरुवार को ऊंट की सवारी करते हुए नमामि गंगे के सदस्यों ने ओलिंपिक में प्रतिभाग करने टोक्यो गए भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। हाथों में पोस्टर व तिरंगा लेकर उन्होंने न सिर्फ 'भारत माता की जय' का उद्घोष किया, बल्कि 'सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी' के जोशीले बोल भी फिजाओं में गुंजाए। उत्तम राय चौधरी

12 हजार नए सीए बदलेंगे चुनावी गणित

जासं, कानपुरः इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट आफ इंडिया के चुनाव की घोषणा हो गई है। तीन व चार दिसंबर को केंद्रीय परिषद व सेंट्रल रीजन के चुनाव होने हैं। पिछले तीन वर्ष में करीब 12 हजार चार्टर्ड अकाउंटेंट सेंट्रल रीजन में बढ़े हैं, इससे इस क्षेत्र के दोनों ही चुनाव में एक-एक सीट बढ़ने की उम्मीद है। अभी तक सात राज्यों को जोड़कर बने सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल में केंद्रीय परिषद की छह और सेंट्रल रीजन की 11 सीटें हैं।

सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल में तीन वर्ष पहले हुए चुनाव में करीब 49 हजार मतदाता थे, जबकि इस बार इनकी संख्या करीब 12 हजार बढ़ चुकी है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान शामिल हैं। इसका मुख्यालय कानपुर है। इन सात राज्यों में केंद्रीय परिषद की छह और सेंट्रल रीजन की 11 सीटें हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट की संख्या के बढ़ने से इनकी सीटों की संख्या बढ़ती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के मुताबिक 12 हजार चार्टर्ड अकाउंटेंट बढ़ने से दोनों ही जगह-जगह एक-एक सीट बढ़ सकती है।

दिल्ली में रोहिंग्या कैंप से उप्र ने हटाई झुग्गियां

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली के मदनपुर खादर स्थित उत्तर प्रदेश (यूपी) के सिंचाई विभाग की जमीन पर बने रोहिंग्या कैंप को गुरुवार को पूरी तरह से खाली करा लिया गया। 2.10 हेक्टेयर के इस प्लाट में रोहिंग्या शरणार्थियों की 53 झुग्गियां थीं।

उत्तर प्रदेश के जलशक्ति मंत्री डा. महेंद्र सिंह ने ट्वीट कर जानकारी दी कि गुरुवार को सुबह चार बजे ही सिंचाई विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई थी। रोहिंग्या शरणार्थी लंबे समय से इस प्लाट पर कब्जा जमाए हुए थे। उन्हें दिल्ली सरकार की ओर से पानी व अन्य सुविधाएं दी जा रही थीं। इस जगह को खाली कराने के लिए जब भी उत्तर प्रदेश की टीम जाती थी, ये लोग विरोध करते थे। गुरुवार को पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची टीम ने अतिक्रमण हटाया। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही पूरे प्लाट की बाउंड्री करा दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता वीके सिंह ने बताया कि उस इलाके में विभाग की और जमीनों पर अतिक्रमण है, वहां भी कार्रवाई की जाएगी।

शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सेवा बढ़ाकर रोकना होगा मतांतरण

संजय कुमार, रांची

- हिंदू संगठनों की ओर से गांवों में एकल विद्यालय, आरोग्य सेवा केंद्र खुले हैं, लेकिन कम है संख्या

शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें ईसाई मिशनरियां वर्षों से सक्रिय हैं। पवित्र भाव से स्कूल और अस्पताल चलाने वालों की कमी नहीं, तो इसकी आड़ में अधिक से अधिक मतांतरण की मंशा पूरा करने वाले भी पूरे देश में भरे पड़े हैं। लक्षित वर्ग को दाना भी यहीं से फेंका जाता है। बच्चे मिशनरी स्कूल में दाखिला लें या कोई पीड़ित इनके अस्पताल में भर्ती हो, मतांतरण का हित साधने वाले लोग यहीं से इनके पीछे पड़ जाते हैं। बहरहाल, इन क्षेत्रों में सेवा करके ही समाज को एकजुट रखा जा सकता है यह हिंदू संगठनों ने भी महसूस किया है। गांवों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के अनुषंगिक संगठनों ने एकल विद्यालय, आरोग्य सेवा केंद्र, अस्पताल, स्कूल आदि खोले तो हैं, लेकिन ईसाई मिशनरियां यहां बहुत आगे हैं। तेजी से यहां काम करना होगा, सुदूर इलाकों में सेवा भाव और बढ़ाना होगा।

राष्ट्रीय सेवा भारती के पदाधिकारी गुरुशरण प्रसाद कमी स्वीकार करते हुए कहते हैं कि हमने जिन इलाकों में जरुरतमंदों की सेवा शुरू की है वहां मतांतरण में कमी आई है। यहां सभी संगठनों को जोर लगाना होगा। मिशनरी वाले गरीब बच्चों को पहले टारगेट करते हैं, उनके घर पहुंच बच्चे का दाखिला निश्शुल्क आवासीय विद्यालय में कराने की बात करते हैं। दाखिले के बाद घर आते-जाते प्रभाव में लेकर इनका मतांतरण करा दिया जाता है। इसी तरह अस्पताल में किसी पीड़ित का इलाज कराने के बाद उसका मतांतरण कराया जाता है। गुरुशरण कहते हैं, हमारी संस्थाओं के स्कूल और अस्पताल हों तो लोगों को इस मकड़जाल से बचाया जा सकता है। समाज के लोगों से अपील की कि अपने आसपास के जरूरतमंदों पर नजर रखें और उनकी मदद के लिए अधिक से अधिक आगे आएं ताकि समाज को टूटने से बचाया जा सके। धर्म छोड़ने वालों और समाज के हर तबके में जागरुकता भी बढ़ानी होगी।

सुनी नहीं जा रही शिकायतः एक और सवाल यह उठता है कि मतांतरण रोकने के लिए कानून है तो लोग आवाज क्यूं नहीं उठाते। सामाजिक कार्यकर्ता प्रिया मुंडा कहती हैं, हम चुप नहीं बैठे हैं। जैसे ही किसी मामले की जानकारी मिलती है पुलिस तक शिकायत पहुंचाते हैं लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जा रही। खूंटी जिला के तोरपा स्थित पनढरिया गांव में मतांतरण में लगे पादरियों से मैंने बपतिस्मा प्रमाण पत्र मांगा, इसमें अंकित रहता है कि आपने कब किसका मतांतरण कराया। इस बात पर बहस हुई और पादरी वहां से निकल भागे। थाने में जब इसकी शिकायत की गई तो समझौते का दबाव पड़ा। देर रात एक बजे तक मुझे थाने में बिठाकर रखा गया। प्रिया कहती हैं, ऐसा ही हो रहा है। शिकायत करने वालों को परेशान किया जाता है।

औरंगाबाद में रघुनाथपुर के अधिकांश हिंदू–मुस्लिम रघुनाथ सहाय के वंशज

उपेंद्र कश्यप, औरंगाबाद

- यहां की मुस्लिम आबादी स्वीकार करती है कि उनके पूर्वज थे हिंदू

बिहार के मंत्री जमा खान की स्वीकारोक्ति कि उनके वंशज हिंदू थे, के बाद बिहार के औरंगाबाद जिले के हसपुरा प्रखंड के पीरू गांव के निवासी स्वयं को गर्व से हिंदुओं का वंशज बताते हैं। इसी प्रखंड के एक और गांव रघुनाथपुर के बाशिंदे भी मानते हैं कि यहां मुस्लिमों के पूर्वज हिंदू हैं और उनका डीएनए भी एक ही है।

रघुनाथपुर निवासी मो. एहसान उल हक और श्यामाचरण प्रसाद बताते हैं कि गांव की बड़ी आबादी रघुनाथ सहाय की वंशज है। नई पीढ़ी भी जानती है कि उसके पूर्वज रघुनाथ सहाय के ही वंशज हैं। गांव में हिंदू-मुस्लिम मिलकर रहते हैं। यहां 1908 में मस्जिद का निर्माण हुआ। श्यामाचरण प्रसाद कहते हैं कि जो मजहब को नहीं पहचानते, वही राजनीति करते हैं। मो. एहसान उल हक कहते हैं- नबी के दुश्मन अबू जेहल, कंस के दुश्मन घनश्याम, नबी कहो या नट नगर, दो नाम से होता है एके काम।

प्रथम मतांतरण पर लिख रहे किताब : पीरू की तरह यहां का इतिहास स्पष्ट नहीं है। रघुनाथपुर में कब कौन कहां से आया और सबसे पहले किसने क्यों इस्लाम कबूल किया इसे लेकर मतभेद है। श्यामाचरण बताते हैं कि रघुनाथ सहाय के चार पुत्र थे। जिसमें से एक ने इस्लाम कबूल किया था। उन्हें अन्य भाई तंग करते थे। सहयोग की शर्त पर उनको इस्लाम कबूल कराया गया। रघुनाथपुर पर शोध करने वाले सनाउल्ला अहमद रिजवी कहते हैं कि यहां सबसे पहले रघुनाथ सहाय आए थे। उन्होंने ही इस्लाम कुबूल किया था। पीरू निवासी शाहनवाज रघुनाथपुर पर किताब लिख रहे हैं। यह बताने के लिए कि यहां के मुस्लिम के पूर्वज हिंदू थे। वैसे रघुनाथ सहाय ने इस्लाम कब कुबूल किया, इस पर अभी स्पष्ट राय नहीं है। रघुनाथ सहाय को यूपी से अथवा भोजपुर से आया भी बताया जाता है। मो. एहसानुल और रिजवी के अनुसार, रघुनाथ सहाय उर्फ रघु लाल और इनके भाई भोला सहाय यहां आए थे। दोनों ने मिलकर गांव बसाया। बड़े भाई के नाम पर गांव का नाम रघुनाथपुर रखा गया। तब इस इलाके में किसी कोल राजा का आतंक था। उससे त्रस्त होकर रघुनाथ सहाय अमझर शरीफ के हजरत सैयदना के पास जाया करते थे। ये इराक के बगदाद से 846 हिजरी में हिंदुस्तान आए सूफी संत थे। उनके सामने ही रघुनाथ सहाय ने इस्लाम ग्रहण कर लिया था। जबकि एहसानुल बताते हैं कि बंटवारे की घटना के कारण उन्होंने मजहब बदल लिया था। दूसरी तरफ शाहनवाज खां कहते हैं कि शाह आलम द्वितीय के जमाने में यह हुआ था। महत्वपूर्ण है कि शाह आलम द्वितीय जिसे अली गौहर भी कहा जाता है, उसका कार्यकाल 14 सितंबर, 1803 तक था। दोनों घटना की जो तिथि बताई जाती है। उसमें करीब 950 साल का अंतराल है। बहरहाल, रघुनाथपुर पर शोध जारी है।

'हिंदुओं को भी हो धर्मस्थलों के प्रबंधन का अधिकार'

खत्म हो भेदभाव

- सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर धार्मिक और धर्मार्थ चंदे के लिए समान संहिता की मांग
- कहा, देशभर में करीब चार लाख मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण पर किसी मस्जिद या चर्च पर दिखाई नहीं देता

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को एक जनहित याचिका दाखिल की गई जिसमें धार्मिक और धर्मार्थ चंदे के लिए समान संहिता की मांग की गई है। इसमें देशभर में हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण और इसके विपरीत कुछ अन्य समूहों को अपने संस्थानों के प्रबंधन की अनुमति होने का हवाला दिया गया है। याचिका में दलील दी गई है कि हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों और सिखों को भी मुस्लिमों, पारसियों और ईसाइयों की तरह अपने धार्मिक स्थलों की स्थापना, प्रबंधन और रखरखाव का अधिकार होना चाहिए।

भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की ओर से दाखिल और अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे के जरिये दाखिल याचिका में कहा गया है, 'अनुच्छेद 26 के तहत प्रदत्त संस्थानों के प्रबंधन का अधिकार सभी समुदायों के लिए स्वाभाविक अधिकार है। लेकिन हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों और सिखों को इस सुविधा से वंचित किया गया है।' याचिका के मुताबिक, देशभर में स्थित नौ लाख मंदिरों में से तकरीबन चार लाख सरकारी नियंत्रण में हैं। लेकिन चर्च या मस्जिद से जुड़े एक भी धार्मिक निकाय पर सरकार का नियंत्रण या हस्तक्षेप दिखाई नहीं देता। इसी कारण हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ चंदा (एचआरसीई) अधिनियम, 1951 और समय-समय पर बनाए गए इसी तरह के अन्य कानूनों में बदलाव की जरूरत है। याचिका के मुताबिक, यह कानून सरकार को मंदिरों और उसकी संपत्तियों पर नियंत्रण की अनुमति प्रदान करता है। मंदिरों पर करीब 13 से 18 फीसद सेवाकर लगता है। देश में करीब 18 ऐसे राज्य हैं जिनका हिंदुओं के धार्मिक संस्थानों पर नियंत्रण है। जब मंदिरों पर सेवाकर लागू किया जाता है तो यह बुनियादी रूप से अपने हितों की रक्षा करने के समुदाय के अधिकार और संसाधनों को छीनना है।

याचिका में कहा गया है कि मुस्लिमों और ईसाइयों की तरह हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों और सिखों को भी अपने धार्मिक स्थलों की चल-अचल संपत्तियों के अधिग्रहण और उनका प्रबंधन करने का अधिकार है, सरकार इसमें कटौती नहीं कर सकती। मंदिरों और गुरुद्वारों की चल-अचल संपत्तियों के अधिग्रहण और प्रबंधन के लिए बनाए गए सभी कानून मनमाने और तर्कहीन हैं और अनुच्छेद 14, 15 व 26 का उल्लंघन करते हैं। लिहाजा ये शून्य और निष्क्रिय होने चाहिए। याचिका के मुताबिक, 'अगर जरूरी हो तो अदालत केंद्र या विधि आयोग को धार्मिक एवं धर्मार्थ संस्थानों के लिए साझा चार्टर और धार्मिक एवं धर्मार्थ चंदे के लिए समान संहिता का मसौदा बनाने का निर्देश दे सकती है।'

फर्जीवाड़ा कर पत्नी को सरपंच बनाने वाले विधायक को जमानत

जागरण संवाददाता, उदयपुर

राजस्थान हाई कोर्ट ने फर्जी अंकतालिका के जरिये पत्नी को सरपंच का चुनाव लड़वाने के मामले में उदयपुर जिले के सलूम्बर से भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। पिछले दस दिन से न्यायिक हिरासत भुगत रहे मीणा की शुक्रवार को रिहाई होने की उम्मीद है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा ने गत 12 जुलाई को सराड़ा कोर्ट में सरेंडर किया था। उसी दिन उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई इसी कोर्ट में हुई थी, लेकिन अदालत ने अर्जी खारिज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उसके बाद मीणा ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत अर्जी लगाई थी, लेकिन अदालत ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट का रुख किया।

पेश मामले के अनुसार छह साल पहले 2015 में विधायक अमृतलाल मीणा ने अपनी पत्नी शांता देवी को सेमारी ग्राम पंचायत से सरपंच का चुनाव लड़ाया था। चुनाव में शांता देवी विजयी रहीं, लेकिन प्रतिद्वंद्वी सुगना देवी ने फर्जी मार्कशीट पर चुनाव लड़ने की शिकायत की। जांच में पता चला कि शांता देवी ने फर्जी अंकतालिका के जरिये ही चुनाव लड़ा। उनकी जारी पांचवीं पास की अंकतालिका में अभिभावक की जगह विधायक अमृतलाल के हस्ताक्षर पाए गए। इस पर शांता देवी व विधायक के खिलाफ भी धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ।

स्पोर्ट्स

ओलिंपिक उद्घाटन समारोह के निदेशक को अभद्र मजाक पड़ा भारी, बर्खास्त

ओलिंपिक डायरी

टोक्यो, एपी : टोक्यो ओलिंपिक आयोजन समिति ने उद्घाटन समारोह से एक दिन पहले इसके निदेशक को बर्खास्त कर दिया, जिसने 1998 में एक कामेडी शो में सर्वनाश (होलोकास्ट) को लेकर मजाक किया था। आयोजन समिति के अध्यक्ष सेइको हाशिमोतो ने कहा कि उद्घाटन समारोह के निदेशक केंतारो कोबायाशी को पद से हटा दिया गया है। उन्होंने एक बार अपने एक शो में सर्वनाश को लेकर अभद्र मजाक किया था। हाशिमोतो ने कहा, 'हमें पता चला कि कोबायाशी ने अपने एक शो में ऐतिहासिक त्रासदी का उल्लेख मजाक के संदर्भ में किया था। उद्घाटन समारोह से एक दिन पहले हुई इस असुविधा के लिए हम क्षमाप्रार्थी हैं।'

कोरोना वायरस के चलते ओलिंपिक से हटा गिनी

कोनाक्री (गिनी), एपी : अफ्रीकी देश गिनी ने कोरोना वायरस के फिर से फैलने के कारण ओलिंपिक से हटने का फैसला किया है। खेल मंत्री सानोयूसी बंटामा सो ने बुधवार को गिनी ओलिंपिक समिति के अध्यक्ष को संबोधित करते हुए पत्र में यह घोषणा की, जिसमें उन्होंने कोरोना वायरस और इसके वैरिएंट को जिम्मेदार ठहराया।

सानोयूसी ने कहा, 'कोविड-19 वैरिएंट के फैलने से सरकार ने गिनी की टोक्यो में 32वें ओलिंपिक में हिस्सेदारी रद करने का फैसला किया, जो गिनी के खिलाड़ियों के स्वास्थ्य को देखते हुए किया गया।'

मालूम हो कि गिनी के पांच खिलाड़ियों को ओलिंपिक में शिरकत करनी थी, जिसमें से फ्रीस्टाइल पहलवान फातोयूमाटा यारी कामारा इस फैसले से काफी नाराज हैं। गिनी ने 11 बार ओलिंपिक में हिस्सा लिया है, लेकिन कभी भी पदक नहीं जीत सका है। उत्तर कोरिया ने भी कोरोना वायरस का हवाला देते हुए ओलिंपिक से हटने का फैसला किया है।

ओलिंपिक शुरू होने से पहले टोक्यो में कोविड-19 के करीब 2000 मामले

टोक्यो, एपी : टोक्यो में गुरुवार को पिछले छह महीने से सबसे ज्यादा कोरोना वायरस संक्रमण के मामले दर्ज किए गए, जिससे ओलिंपिक खेलों के दौरान संक्रमण की स्थिति खराब होने की चिंता बढ़ गई हैं। गुरुवार को 1,979 नए मामले दर्ज किए गए, जो 15 जनवरी को सर्वाधिक 2,044 मामलों के बाद सबसे ज्यादा मामले हैं। प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने 12 जुलाई को टोक्यो में 22 अगस्त तक कोरोना आपात स्थिति लगाई थी लेकिन, इसके बावजूद तब से रोज के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। जापान में कोविड-19 महामारी शुरू होने के बाद करीब 8,53,000 मामले सामने आए हैं और 15,100 लोग जान गंवा चुके हैं।

कोरोना से नीदरलैंड्स और चेक गणराज्य को लगा झटका

टोक्यो, प्रेट्र : चेक गणराज्य की वालीबाल खिलाड़ी मार्केता नौशचु और नीदरलैंड्स की ताइक्वांडो खिलाड़ी रेशमी आगिंक को कोविड-19 जांच में पाजिटिव आने के बाद ओलिंपिक खेलों से हटना पड़ा। इन दोनों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद खेलों से जुड़े खिलाड़ियों के संक्रमण के मामले 10 तक पहुंच गए हैं।

चेक राष्ट्रीय ओलिंपिक समिति ने कहा, 'मार्केता नौशचु कोविड-19 के नियमित जांच में लगातार निगेटिव आ रही थी, लेकिन बुधवार के एक अस्पष्ट नतीजे के बाद गुरुवार को उसकी रिपोर्ट पाजिटिव आई है।'

नीदरलैंड्स की ओलिंपिक समिति ने कहा, 'रेशमी ओगिंक कोविड-19 पाजिटिव रिपोर्ट के कारण वह दुर्भाग्य से खेलों में भाग नहीं ले पाएंगी।' नौश और ओगिंक दोनों को क्वारंटाइन पर भेज दिया गया है।

सीरीज जीतने के बाद भारत के आगे टीम चयन की दुविधा

- प्रयोग करने या संयोजन बरकरार रखने को लेकर असमंजस में भारत
- श्रीलंका के खिलाफ तीसरा व अंतिम वनडे मैच आज

कोलंबो, प्रेट्रः भारतीय कोच राहुल द्रविड़ के सामने दुविधा होगी कि वह श्रीलंका के खिलाफ शुक्रवार को आखिरी मैच में प्रयोग करें या क्लीन स्वीप के लिए विजयी संयोजन को बरकरार रखें।

सीरीज जीतने के बाद अब देखना यह है कि भारत पारी की शुरुआत के लिए कप्तान शिखर धवन के साथ पृथ्वी शा को ही उतारता है या देवदत्त पडीक्कल या रुतुराज गायकवाड़ को मौका देता है। इशान किशन की जगह संजू सैमसन को वनडे क्रिकेट में पदार्पण का मौका दिया जा सकता है। गेंदबाजी आक्रमण में भुवनेश्वर का साथ देने के लिए नवदीप सैनी या चेतन सकारिया को दीपक चाहर की जगह मिल सकती है। स्पिनर कुलदीप यादव और युजवेंद्रा सिंह चहल की जगह कृष्णप्पा गौतम और राहुल चाहर के चयन को लेकर दुविधा होगी।

पंत टीम के साथ बायो-बबल में जुड़े

डरहम, प्रेट्र : भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज रिषभ पंत कोरोना संक्रमण से उबरकर इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले टीम के बायो-बबल (कोरोना से बचाव के लिए बनाए गए सुरक्षित माहौल) में जुड़ गए। कोरोना पाजिटिव पाए गए पंत ने 10 दिन का क्वारंटाइन पूरा कर लिया है। उनकी दो आरटी-पीसीआर रिपोर्ट निगेटिव आई हैं।

वाशिंगटन भी इंग्लैंड दौरे से बाहर

> धौनी का मुझ पर गहरा असर है। सिर्फ चेन्नई सुपरकिंग्स के साथ ही नही, बल्कि शुरू से हमने देखा है कि कैसे वह करीबी मैच जिताते थे। वह हमेशा मुझसे कहते हैं कि मैच आखिर तक ले जाना तुम्हारे हाथ में है और अगर तुम ऐसा कर सके और तुम्हारे पास ओवर हों तो मैच रोमांचक हो सकता है, तो मैं वही कर रहा था।
> –दीपक चाहर, भारतीय तेज गेंदबाज

नई दिल्ली, प्रेट्र : इंग्लैंड दौरे पर गई भारतीय टीम को गुरुवार को स्पिन गेंदबाजी आलराउंडर वाशिंगटन सुंदर के चोटिल होने से एक और झटका लगा है, जो चार अगस्त से शुरू होने वाली पांच टेस्ट मैचों की सीरीज से बाहर हो गए। इस दौरे पर शुभमन गिल और आवेश खान के बाद वाशिंगटन चोटिल होने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं। भारत और काउंटी एकादश के बीच प्रथम श्रेणी अभ्यास मैच के दूसरे दिन मुहम्मद सिराज की गेंद पर वाशिंगटन की अंगुली में फ्रैक्चर हो गया। गिल के बाद अब आवेश व वाशिंगटन दोनों ही स्वदेश लौटेंगे।

नेशनल स्टेडियम से उद्घाटन समारोह देखेंगे खेल मंत्री

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और खेल राज्य मंत्री निसित प्रमाणिक शुक्रवार को यहां मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से 32वें ओलिंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह देखेंगे। उनके साथ पूर्व खिलाड़ी और विभिन्न क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीयर फोर इंडिया अभियान के तहत टोक्यो में भाग लेने वाले भारतीय दल का उत्साह बढ़ाएंगी। इस दौरान हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह, यशोधरा राजे सिंधिया और राष्ट्रीय बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद आदि के स्टेडियम में उपस्थित रहने की उम्मीद है।

स्वर्ण पदक विजेता को 75 लाख रुपये देगा आइओए

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय ओलिंपिक संघ (आइओए) ने गुरुवार को घोषणा की कि वह टोक्यो ओलिंपिक खेलों के स्वर्ण पदक विजेता को 75 लाख रुपये का नकद पुरस्कार देगा। आइओए की सलाहकार समिति ने रजत पदक विजेताओं को 40 लाख रुपये और कांस्य पदक विजेताओं को 25 लाख रुपये देने की घोषणा की है।

आइओए ने इसके साथ ही प्रत्येक राष्ट्रीय खेल महासंघ (एनएसएफ) को 25 लाख रुपये और पदक विजेता एनएसएफ को 30 लाख रुपये का अतिरिक्त सहयोग देने के समिति के निर्णय को स्वीकार किया है। इसके अलावा अन्य राष्ट्रीय खेल महासंघों में से प्रत्येक को 15 लाख रुपये का सहयोग मिलेगा।

सलाहकार समिति ने भारतीय दल के प्रत्येक सदस्य के लिए टोक्यो प्रवास के दौरान प्रतिदिन 50 डालर (करीब 3722 रुपये) का भत्ता देने की भी सिफारिश की है।

रिकार्लिसन की हैट्रिक से ब्राजील ने जर्मनी को रौंदा

योकोहामा, एपी : ब्राजील ने फारवर्ड खिलाड़ी रिकार्लिसन की हैट्रिक से पहले मैच में जर्मनी को 4-2 से मात दी। इस तरह टोक्यो ओलिंपिक में रिकार्लिसन हैट्रिक पूरी करने वाले पहले खिलाड़ी भी बने। जापान के योकोहामा अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए मैच में रिकार्लिसन ने मैच के सातवें, 22वें और 30वें मिनट में लगातार तीन गोल दागकर पहले हाफ में ही टीम को मजबूती प्रदान की। इस तरह 0-3 से पिछड़ने वाली जर्मनी की टीम ने दूसरे हाफ में नादिम अमीरी (57वें मिनट) और रैग्नार (84वें मिनट) के गोल से वापसी करने की कोशिश जरूर की मगर मैच के इंजुरी टाइम में ब्राजील की तरफ से एक बार फिर पौलिन्हो ने गोल दागकर स्कोर 4-2 कर दिया। हालांकि मैच के 63वें मिनट में जर्मनी के मैक्सिमिलियन अर्नोल्ड को रेड कार्ड दिया गया, जिसके बाद उनकी टीम 10 खिलाड़ियों के साथ आगे को मैत खेला। इस तरह रियो ओलिंपिक 2016 के फाइनल में भी जर्मनी को हराकर स्वर्ण पदक जीतने वाली ब्राजील ने टोक्यो ओलिंपिक में भी इसी टीम के खिलाफ जीत से आगाज किया। वहीं, अन्य मुकाबलों में मेक्सिको ने फ्रांस को 4-1 से हराया तो स्पेन ने इजिप्ट के साथ गोल रहित ड्रा खेला।

जडेजा का अर्धशतक, अभ्यास मैच ड्रा

नई दिल्ली, जेएनएन : रवींद्र जडेजा (51 रिटायर्ड आउट) ने इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले भारत और काउंटी एकादश के बीच गुरुवार को डरहम में ड्रा छूटे तीन दिवसीय अभ्यास मैच में दूसरी पारी में भी अर्धशतक जड़ा। भारत ने पहली पारी में 91 रन की बढ़त हासिल करने के बाद अपनी दूसरी पारी तीन विकेट पर 192 रन बनाकर समाप्त घोषित की और काउंटी एकादश के सामने जीत के लिए 284 रन का मुश्किल लक्ष्य रखा। जब दोनों टीमों ने मैच ड्रा करने पर सहमति जताई तब काउंटी एकादश ने 15.5 ओवर में बिना किसी नुकसान के 31 रन बनाए। जडेजा के अलावा मयंक अग्रवाल (47), चेतेश्वर पुजारा (38) और हनुमा विहारी (नाबाद 43) ने भी उपयोगी पारियां खेलीं।

8 से 14 जुलाई के बीच अस्पतालों में भर्ती होने वाले कोरोना मरीजों की संख्या 38.4 फीसद बढ़ी है ब्रिटेन में। अभी अस्पतालों में रोज औसतन 745 मरीज भर्ती हो रहे हैं।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 23 जुलाई, 2021

युद्ध का नया हथियार बन रहे साइबर टूल्स



समय के साथ युद्ध का तरीका और हथियार भी बदल गए हैं। दूसरे देशों और वहां की कंपनियों के कंप्यूटर एवं नेटवर्क पर हमला करने वाले साइबर टूल्स अब युद्ध का नया हथियार बनकर सामने आए हैं। साइबर अटैक किसी देश को अव्यवस्थित करने और वहां की अर्थव्यवस्था को तबाह करने की ताकत रखते हैं। यूनिवर्सिटी आफ साउथ वेल्स के एथम इलबिज और क्रिश्चियन कौनर्ट ने इस संबंध में कई सवालों के जवाब दिए हैं।

हमलावर का पता लगाना चुनौती

युद्ध के इस तरीके में हमलावर का पता लगाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। किसी दूसरे देश की सरकार या कंपनी में सेंध लगाने के लिए सरकारें आमतौर किसी गैर सरकारी व्यक्ति या संस्थान की मदद लेती हैं। इसलिए किसी भी तरह का आरोप लगने पर सरकारों के लिए इनसे पल्ला झाड़ना आसान होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि संबंधित देश की रक्षा एजेंसियां ऐसे साइबर हमलावरों के खिलाफ जांच में मदद का भरोसा भी देती हैं, लेकिन अमूमन कोई नतीजा नहीं निकलता।

खतरनाक है हाइब्रिड वारफेयर

विभिन्न रैंसमवेयर और वायरस के जरिये होने वाले साइबर अटैक को हाइब्रिड वारफेयर नाम दिया गया है। किसी मजबूत दुश्मन को हराने के लिए इसमें पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इसका उद्देश्य उस राजनीतिक लक्ष्य को हासिल करना होता है, जिसे पारंपरिक हथियारों से हासिल करना संभव नहीं होता। इसमें किसी देश की संवेदनशील जानकारियों को चुराने से लेकर वहां की पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने तक की क्षमता होती है। यही कारण है कि दुनियाभर में विभिन्न देश इस समय इनसे



बचने के लिए व्यवस्था को मजबूत करने में जुटे हैं। साइबर हमलों से निपटने में नीति नियंताओं को रणनीतिक सुझाव देने के लिए यूरोपीय यूनियन (ईयू) ने हाइब्रिड फ्यूजन सेल स्थापित किया है। बहुत से हमलों में संदिग्ध भूमिका को देखते हुए ईयू और अमेरिका दोनों ने रूस के कई व्यक्तियों और इकाइयों को प्रतिबंधित भी किया है।

बहुत महीन है जिम्मेदारी की लकीर



साइबर स्पेस में तीन लेयर होती हैं, फिजिकल लेयर (हार्डवेयर), लाजिकल लेयर (डाटा प्रोसेसिंग यानी डाटा पर किस तरह काम होता है) और ह्यूमन लेयर (यूजर)। ज्यादातर इस व्यवस्था को सरकार के बजाय निजी संस्थान संभालते हैं। इसलिए यह तय कर पाना मुश्किल होता है कि बचाव की जिम्मेदारी किसकी है। बचाव की जिम्मेदारी तय करने की उलझन ही हमलावर देशों के लिए फायदेमंद होती है।

रूस की सक्रियता ने बढ़ाई है कई देशों की चिंता

जिस तरह से सैन्य स्तर पर साइबर हमले हो रहे हैं, उससे इनके पीछे सरकारों का हाथ होने का स्पष्ट संकेत मिलता है। रूस इस मामले में बहुत ज्यादा सक्रिय है। उसने एक व्यवस्थित साइबर वारफेयर रणनीति बनाई हुई है। बताया जाता है कि इस रणनीति को बनाने में एलेक्जेंडर डगिन जैसे राजनीतिक विज्ञानी की भूमिका रही है। उन्हें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दिमाग भी कहा जाता है। वह मास्को स्टेट यूनिवर्सिटी में सोशियोलाजी के प्रोफेसर हैं। 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्जे के बाद अमेरिका ने प्रोफेसर डगिन को प्रतिबंधित लोगों की सूची में डाल दिया था। पुतिन के वरिष्ठ सलाहकार आइगर पैनारिन और कई सैन्य हस्तियों ने भी इसमें भूमिका निभाई है। इनपुट : प्रेट्र

अमेरिका ने माना, अफगानिस्तान में बढ़ रहा तालिबान का दबदबा

संकट ▸ अमेरिकी जनरल ने कहा, आतंकियों का 212 जिला केंद्रों पर कब्जा

रणनीतिक तौर पर मजबूत होता जा रहा आतंकी संगठन

वाशिंगटन, आइएएनएस : अमेरिका ने माना है कि अफगानिस्तान में तालिबान का दबदबा बढ़ रहा है। अमेरिका के एक शीर्ष जनरल ने कहा, अफगानिस्तान के कुल 419 जिला केंद्रों में से 212 पर अब तालिबान का कब्जा है। अमेरिकी बलों की वापसी शुरू होने के बाद से ही तालिबान रणनीतिक तौर पर मजबूत होता जा रहा है।

अमेरिकी ज्वाइंट चीफ आफ स्टाफ के चेयरमैन मार्क मिले ने बुधवार को पेंटागन में पत्रकारों से कहा, 'अफगानिस्तान में हिंसा बढ़ गई है। हम स्थिति की समीक्षा करने जा रहे हैं। अफगान बलों में देश को तालिबान के कब्जे से मुक्त कराने की क्षमता है। अफगानिस्तान की सुरक्षा को लेकर सरकार, लोगों व सुरक्षा बलों की परीक्षा होने जा रही है।' मार्क ने कहा, अभी तक तालिबान का अफगानिस्तान की 34 प्रांतीय राजधानियों में से किसी पर कब्जा



मार्क मिले फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

नहीं हुआ है, लेकिन वे दबाव बना रहे हैं। इस बीच, अफगान सुरक्षा बल राष्ट्रीय राजधानी काबुल समेत प्रमुख शहरों में अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं।

95 फीसद अमेरिकी बलों की हो चुकी वापसी : अफगानिस्तान में 20 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद अब अमेरिकी बल इस देश को छोड़ रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि 95 फीसद से ज्यादा बलों की स्वदेश वापसी हो चुकी है। राष्ट्रपति जो बाइडन ने यह एलान किया है कि अमेरिका का अफगान मिशन 31 अगस्त को खत्म हो जाएगा।

जबरन धन जमा कर रहे आतंकी

समाचार एजेंसी एएनआइ के मुताबिक, अफगानिस्तान के बल्ख प्रांत में तालिबान आतंकी लोगों से जबरन धन वसूल रहे हैं। संगठन में लोगों की जबरन भर्ती भी कर रहे हैं। आतंकी उन इलाकों में ऐसा कर रहे हैं, जहां उनका नियंत्रण है।

ताजिकिस्तान का बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास

समाचार एजेंसी रायटर के अनुसार, अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा से सटे ताजिकिस्तान में बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास किया जा रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते दबदबे और अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन बलों की वापसी के बीच उपजे हालात में यह सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। ताजिकिस्तान में हुए सैन्य अभ्यास में दो लाख 30 हजार सैनिकों ने हिस्सा लिया।

अमेरिकी हवाई हमलों में पांच तालिबान मारे गए

काबुल, एएनआइ : अफगानिस्तान के विभिन्न प्रांतों में गत तीन दिनों में कम से कम पांच तालिबानी आतंकियों को अमेरिका ने हवाई हमलों में मार गिराया है। पत्रकार बिलाल सरवरी द्वारा किए गए कई ट्वीट में दावा किया गया है कि अफगानिस्तान के कई प्रांतों में अमेरिकी वायुसेना हवाई हमले कर रही है। हेलमंद के गर्मसिर जिले में तालिबान के एक वाहन को निशाना बनाकर खाक किया जा चुका है। यह सब तब हो रहा है जब अमेरिकी और नाटो सेनाओं के अफगानिस्तान छोड़ने के बीच तालिबान ने अफगान सुरक्षाबलों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। सरवरी के मुताबिक, अमेरिकी सेना द्वारा कंधार में किए गए हमले में पांच तालिबान मारे गए हैं। वरदक प्रांत के सयद अबद जिले में तालिबान के तोपखाने को ध्वस्त किया जा चुका है। शाह वाली कोट जिले में तालिबान के ट्रकों को निशाना बनाया गया है।

हांगकांग में गिरफ्तार चार संपादकों पर विदेशी मिलीभगत के आरोप

हांगकांग, एपी : हांगकांग पुलिस ने डेली एपल के चार संपादकों पर विदेशी से मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। इन चारों संपादकों में तीन को कुछ हफ्ते पूर्व गिरफ्तार किया गया था। पूर्व एक्जीक्यूटिव एडीटर इन चीफ लैम मन चुंग की बुधवार को गिरफ्तारी हुई है। इधर पुलिस ने पांच ट्रेड यूनियन नेताओं को भी देशद्रोह के आरोप में जेल भेज दिया। गिरफ्तार संपादकों को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने चारों को जमानत देने से इन्कार कर दिया है। पुलिस ने चार्जशीट में डेली एपल के चारों संपादक पर विदेश से मिलीभगत का आरोप लगाया है। अखबार के संस्थापक जिमी लाइ पहले से जेल में हैं। उनकी संपत्ति भी जब्त कर ली गई है। इसीलिये अखबार को बंद करना पड़ा था। पुलिस ने गुरुवार को पांच ट्रेड यूनियन नेताओं को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन सभी पर प्रशासन, न्यायपालिका के प्रति घृणा फैलाने, देशद्रोही सामग्री के प्रकाशन, जनता को सरकार के खिलाफ उकसाने का मुकदमा दर्ज किया है।

सात लोकतंत्र समर्थकों को सजा : रायटर के अनुसार, हांगकांग की अदालत ने 2019 में हुए लोकतंत्र समर्थकों के आंदोलन में रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन करने वाले सात लोगों को साढ़े तीन से लेकर सात साल तक कैद की सजा सुनाई है।

चीन ने पाक में रोकी अरबों डालर की दासू जलविद्युत परियोजना

▸ नौ इंजीनियरों की मौत से नाराज बीजिंग ने टाली सीपीईसी संयुक्त समन्वय समिति की 10वीं बैठक

कराची, एएनआइ : पाकिस्तान में बस पर हुए हमले में अपने नौ इंजीनियरों की मौत से नाराज चीन ने 50 अरब डालर की चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) परियोजना का कामकाज संभालने वाली संयुक्त समन्वय समिति की 10वीं बैठक स्थगित कर दी है। उसने अरबों डालर की दासू जलविद्युत परियोजना भी रोक दी है।

निक्केई एशिया के मुताबिक, कोशिस्तान जिले में चीन की अगुआई में दासू जलविद्युत परियोजना के निर्माण के दौरान हुए इस हमले में नौ चीनी इंजीनियरों समेत 13 लोगों की मौत हुई थी। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने इसे बस में तकनीकी दिक्कतों की वजह से हुआ हादसा बताया था। इस बयान पर चीन ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और विस्फोट की जांच कराने की मांग की थी। पाकिस्तानी अधिकारियों को बाद में घटनास्थल पर विस्फोटकों के सुराग मिले थे। मामले की जांच के लिए 15 चीनी जांचकर्ताओं की टीम भी पाकिस्तान पहुंची थी।

आतंकवाद की कवरेज करने वाले वरिष्ठ विश्लेषक फखार काकाखेल का कहना है, 'स्वाभाविक रूप से ये चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) के निर्माण कार्य को बाधित करने के प्रयास हैं। पूर्व में कई हमलों का निशाना बलूचिस्तान में सीपीईसी के बाहरी इलाके थे, लेकिन इस बार यह चीन के नजदीक हुआ।' विशेषज्ञों का मानना है कि यह हमला पाकिस्तान में चीनी हितों को बड़ा झटका है। निक्केई एशिया ने काकाखेल के हवाले से कहा है कि अफगानिस्तान के अशांत हालात भी पाकिस्तान में और मुश्किलें पैदा करेंगे जहां सीपीईसी मुख्य रूप से निशाने पर है।

इस बीच, चीन ने पाकिस्तान से उसके देश में चीनी कर्मियों के समक्ष सुरक्षा खतरों की पहचान करने के लिए कहा है। चीन के स्टेट काउंसलर और जन सुरक्षा मंत्री झाओ केझी ने पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री शेख राशिद अहमद से उक्त हालिया हमले के बारे में बातचीत भी की। दरअसल, चीनी नागरिकों पर हो रहे लगातार हमलों के बाद अब पाकिस्तान के लिए बीजिंग को आश्वस्त करना जरूरी है कि वह आतंकी समूहों से चीन के बुनियादी ढांचे और उसके नागरिकों की रक्षा कर सकता है। यह बात अलग है कि वह उनसे अपने ही बुनियादी ढांचे और नागरिकों की सुरक्षा करने में विफल रहा है।

चीनी साइबर अपराधियों ने कंबोडिया सरकार का डाटा किया हैक

हनोई, रायटर : साइबर अपराध के मामले में चीन अपने विश्वस्त सहयोगियों को भी नहीं बख्श रहा है। चीनी साइबर अपराधियों ने अब कंबोडिया के विदेश विभाग के डाटा में सेंध लगाई है। यहां से उसने मेकांग नदी से संबंधित डाटा चुरा लिया है।

मेकांग नदी के मामले में चीन और अमेरिका आमने-सामने हैं। मेकांग नदी चीन के युन्नान प्रांत से निकलकर म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया से वियतनाम तक पहुंचती है। चीन ने इस नदी पर बांध बना लिया है। इस बांध परियोजना से वह बिजली ही नहीं, सिंचाई के लिए 47 अरब क्यूबिक मीटर से ज्यादा पानी का उपयोग कर रहा है। चीन के द्वारा नदी पर बांध के कारण उपरोक्त देशों में हर साल गर्मी में पानी की कमी हो जाती है।

पेगासस जासूसी प्रकरण के बाद इजरायल निर्यात नीति की करेगा समीक्षा!

▸ विदेश-रक्षा मामलों की संसदीय समिति ने जताई आवश्यकता

▸ एनएसओ ने कहा, दुरुपयोग की शिकायत पुष्ट होने पर सेवा बंद होगी

यरुशलम, रायटर : इजरायल की संसदीय समिति ने देश की रक्षा उत्पाद निर्यात नीति में बदलाव की आवश्यकता जताई है। यह अपेक्षा देश के एनएसओ ग्रुप के उस सॉफ्टवेयर की बिक्री को लेकर पैदा हुए विवाद के बाद की गई है जिसके जरिये पत्रकारों, नेताओं, अफसरों व सामाजिक कार्यकर्ताओं की जासूसी हुई।

एनएसओ के पेगासस सॉफ्टवेयर के जो लोग शिकार हुए हैं उनमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भी हैं। गुरुवार को उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक कर मामले की जांच की घोषणा की। यूरोपीय यूनियन के चिंता जताए जाने के बाद जर्मनी में चांसलर एंजेला मर्केल ने जासूसी सिस्टम पर नाइत्तेफाकी जाहिर की है।

इजरायली संसद नीसेट की विदेशी व रक्षा मामलों की समिति के प्रमुख राम बेन बराक ने कहा है कि सरकार को निर्यात लाइसेंस नीति की समीक्षा करनी चाहिए। इजरायल में यह लाइसेंस सरकारी संस्था डिफेंस एक्सपोर्ट कंट्रोल्स एजेंसी (डीईसीए) देती है। इससे पहले इजरायल सरकार दुनिया के 17 मीडिया संगठनों के आरोपों की जांच के लिए मंत्रियों का दल गठित कर चुकी है। इन संगठनों का आरोप है कि पेगासस के जरिये पत्रकारों के स्मार्टफोन से मैसेज, कॉल रिकॉर्डिंग व लाइव चैट को देखा गया, जबकि एनएसओ ने कहा है कि जासूसी प्रकरण से उसका कोई लेना-देना नहीं है। किसी खरीदार के विषय में सॉफ्टवेयर के दुरुपयोग की पुष्ट शिकायत मिलेगी तो वह उसकी सेवाएं बंद करने में देर नहीं करेगी। कंपनी ने कहा है कि सॉफ्टवेयर आतंकियों और अपराधियों के मोबाइल फोन ट्रैक करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है और उसकी ज्यादातर खरीदार विदेशी सरकारें हैं। वैसे एनएसओ के सॉफ्टवेयर के जरिये जासूसी का शिकार होने वालों की सूची लंबी होती जा रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और मोरक्को के किंग मुहम्मद (सिक्स) का नाम भी इस सूची में शामिल हो गया है।

बाढ़ से बेहाल चीन, फिर से तूफान आने की चेतावनी

▸ हेनान प्रांत में पौने चार लाख लोग विस्थापित, अब तक 33 की मौत

▸ 1400 करोड़ रुपये का नुकसान, दो लाख हेक्टेयर से ज्यादा फसल तबाह

झेंगझोऊ, रायटर : चीन में बारिश के कारण आई भीषण बाढ़ से हालात बेकाबू हैं। हेनान प्रांत के कई शहरों में मौसम के कहर के बाद आसमान साफ रहा, लेकिन बाढ़ का पानी एक दर्जन से ज्यादा शहरों में भरा हुआ है। इस बीच प्राकृतिक आपदा में मरने वालों की संख्या 33 हो गई है। आठ लापता लोगों का कोई पता नहीं चला है। प्रांतीय मौसम विभाग ने अब शिनजियांग, आन्यांग, हेबी और जियाजुओ में तीव्र गति वाले तूफान आने की चेतावनी जारी की है। साथ ही कहा है कि अगले दो दिन फिर भारी बारिश हो सकती है। प्रशासन ने प्राकृतिक आपदा से 18.9 करोड़ डालर (करीब 1400 करोड़ रुपये) के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। वहीं, राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने हालात चिंताजनक बताते हुए राहत दल से जान माल की सुरक्षा के लिए जुटे रहने की अपील की है।

प्रेट्र के अनुसार हेनान प्रांत में तीस लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। पौने चार लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दो लाख 15 हजार हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र की फसल तबाह हो गई है। गुआडोंग के जुहाई शहर में निर्माणाधीन टनल में गत सप्ताह पानी भरने की घटना में 13 मजदूरों की मौत हो गई। एएनआइ के अनुसार झेंगझोऊ की मेट्रो प्रणाली में सात लाइन और 153 स्टेशन हैं। सभी को फिलहाल बंद कर दिया गया है। मेट्रो में पानी भर जाने के बाद 12 लोगों की मौत हो गई थी। बाढ़ में घिरे 10 हजार रोगियों वाले अस्पताल में बिजली पूरी तरह से गुल हो गई है।

3200 कारों में नुकसान के बीमा कंपनियों में दावे : रायटर के अनुसार हेनान प्रांत में मुख्य रूप से उद्योग और कृषि कार्य



चीन में बाढ़ ने लोगों के जीवन की दुश्वारियां बढ़ा दी हैं। हेनान प्रांत के झेंगझाऊ शहर में गुरुवार को सुरक्षित स्थान की ओर जाता एक परिवार। रायटर

होता है। झेंगझोऊ शहर में बड़े उद्योग होने के कारण यहां काफी नुकसान हुआ है। 11 बीमा कंपनियों में गुरुवार तक 3200 कारों के क्षतिग्रस्त होने के दावे पहुंच चुके हैं। सभी उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

जर्मनी में फिर भारी बारिश की पूर्वानुमान : एपी के अनुसार, बाढ़ और बारिश से जूझ रहे जर्मनी में एक बार फिर इस सप्ताहांत में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार यहां शनिवार के मध्य से भारी बारिश शुरू हो जाएगी। फिर यह एक बड़े क्षेत्र में फैल जाएगी। जर्मनी में हाल ही में आई बाढ़ के कारण 205 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में 31 लोग बेल्जियम के भी शामिल हैं।

पाक में भारी बारिश से 14 लोगों की मौत : प्रेट्र के अनुसार पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में भारी बारिश के कारण 14 लोगों की मौत हो गई। 26 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।

जलवायु परिवर्तन से बढ़ रहा अतिवृष्टि का खतरा

जेएनएन, नई दिल्ली : जर्मनी और चीन में बाढ़ के कारण तबाही मची हुई है। यह तबाही दरअसल याद दिला रही है कि जलवायु परिवर्तन दुनियाभर में मौसम में अप्रत्याशित बदलाव का कारण बन रहा है। जलवायु परिवर्तन के चलते ही बिजली गिरने, बादल फटने, जंगलों में आग लगने जैसी घटनाएं बढ़ी हैं। सरकारों को समझना होगा कि विकास के नाम पर उठाए जा रहे बहुत से कदम ही विनाश का कारण बन रहे हैं। चीन की बाढ़ इसका बड़ा उदाहरण है। विशेषज्ञों का कहना है कि बाढ़ के लिए कई बांध और निर्माण कार्य भी जिम्मेदार हैं। फिलहाल हजारों लोग बाढ़ में फंसे हैं।

...तो भर जाते 10 टिहरी जलाशय

चीन के झेंगझोऊ में मंगलवार से गुरुवार तक कुल 617.1 मिलीमीटर बारिश हुई है। यहां सालभर में औसतन 640 मिलीमीटर बारिश होती है। एक वर्गमीटर जगह पर एक लीटर पानी बरसने को एक मिलीमीटर बारिश कहा जाता है। झेंगझोऊ का क्षेत्रफल 7500 वर्ग किलोमीटर है। 617.1 मिलीमीटर बारिश का अर्थ है कि यहां तीन दिन में 4.62 लाख करोड़ लीटर से ज्यादा पानी बरसा है। यह उत्तराखंड स्थित टिहरी जलाशय की कुल क्षमता के 10 गुना से भी ज्यादा है यानी इस बरसात से टिहरी जैसे 10 जलाशय भर जाते।

अमेरिका में फिर बढ़ रहे कोरोना के केस

▸ देशभर में ढाई माह बाद मिले 56 हजार नए संक्रमित

वाशिंगटन, एपी : अमेरिका में कोरोना संक्रमण फिर बढ़ने लगा है। देश में बीते 24 घंटे में 56 हजार से ज्यादा नए संक्रमित पाए गए। ढाई माह बाद एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में नए केस पाए गए हैं। यहां कोरोना के डेल्टा वैरिएंट का कहर बढ़ रहा है। इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने धीमी गति से चल रहे टीकाकरण पर नाखुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा, संक्रमण फिर बढ़ रहा है। ऐसे में अमेरिकियों के लिए टीकाकरण में तेजी लाना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

जान्स हापकिन्स यूनिवर्सिटी के डाटा के अनुसार, कोरोना महामारी की दो लहरों का सामना कर चुके अमेरिका में गत छह जुलाई को 13 हजार 700 केस पाए गए थे। मंगलवार को यह संख्या बढ़कर 37 हजार से ज्यादा हो गई। अब यह दैनिक आंकड़ा 50 हजार के पार पहुंच गया है। अमेरिका में अब तक 56.2 फीसद लोगों को वैक्सीन की एक डोज लग चुकी है। इधर, बाइडन ने बुधवार रात सिनसिनाटी शहर में एक कार्यक्रम में कहा, 'हमारे समक्ष उन लोगों



इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा में 10 वर्षीय बच्चे की कोरोना जांच के लिए स्वैब सैंपल एकत्रित करता मेडिकलकर्मी। एपी

के लिए महामारी है, जिन्होंने अभी अपना टीकाकरण नहीं कराया है।' उन्होंने यह उम्मीद जताई कि आने वाले कुछ माह में 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन स्वीकृत हो जाएगी। इस बीच, एक रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिका में महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक 40 लाख से ज्यादा बच्चे कोरोना पाजिटिव पाए गए।

75 फीसद मामले डेल्टा के : विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने बताया कि बीते चार हफ्ते के दौरान भारत, चीन, रूस, इजरायल और ब्रिटेन जैसे कई देशों में कोरोना के जितने नमूनों का परीक्षण किया गया, उनमें से 75 फीसद मामले डेल्टा के पाए गए। यह बेहद संक्रामक वैरिएंट दुनिया के 124 देशों में पहुंच चुका है। इसकी सबसे पहले भारत में पहचान हुई थी। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि टीकाकरण प्रयासों में तेजी लाने के बावजूद कई देशों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं।

इंग्लैंड में छह लाख को आइसोलेशन का संदेश : समाचार एजेंसी रायटर के अनुसार, ब्रिटेन में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। यहां डेल्टा का भी कहर जारी है। इंग्लैंड और वेल्स में कोरोना पीड़ितों के संपर्क में आने पर करीब छह लाख 20 लोगों को आइसोलेशन में रहने को कहा गया है। यह संदेश हेल्थ सर्विस कोविड एप के जरिये दिया गया है।

कोरोना संक्रमित ने बीवी का भेष धर की विमान यात्रा

टरनेट, एपी : इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एक कोरोना पीड़ित को शहर छोड़ने से मना किया गया, तो उसने अपनी पत्नी के नाम से घरेलू उड़ान का टिकट खरीदा। बुर्का पहना और बीबी का पहचान पत्र व उसकी कोरोना 'निगेटिव' रिपोर्ट लेकर हवाई अड्डे पहुंच गया। यहां भी कोई उसे पहचान नहीं पाया। सफर के दौरान आरोपित टॉयलेट गया और कपड़े बदल लिए। एक फ्लाइट अटेंडेंट ने जब यह सब देखा तो उसे शक हुआ, उसने तुरंत इसकी सूचना पायलट को दी। जैसे ही विमान टरनेट पहुंचा, सुरक्षा और स्वास्थ्य अधिकारियों की टीम ने आरोपित को पकड़ लिया। एयरपोर्ट पर ही उसका दोबारा कोरोना टेस्ट किया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। फिलहाल आरोपित को उसके घर में क्वारंटाइन किया गया है।

कोविड के स्रोत पर डब्ल्यूएचओ की योजना से चीन का इन्कार

बीजिंग, एपी : चीन ने गुरुवार को कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के वैश्विक महामारी कोविड-19 के दूसरे चरण के मूल स्रोत की खोज संबंधी योजना को लेकर वह स्तब्ध हैं।

चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के वाइस मिनिस्टर झेंग वाइक्सिन ने कहा, लैब से वायरस के लीक होने की अफवाह फैलाई जा रही है। ज्ञात हो, डब्ल्यूएचओ के प्रमुख ने गत सप्ताह कहा था कि इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता कि महामारी और चीन की लैब से वायरस लीक होने में सीधा संबंध है। झेंग ने कहा, उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ जब उन्होंने डब्ल्यूएचओ की योजना रिपोर्ट पढ़ी। कुछ डाटा इसलिए साझा नहीं किया जा सकता क्योंकि यह निजता संबंधी सुरक्षा से संबंधित है।

रूस ने लगाया फेसबुक और टेलीग्राम पर जुर्माना

मास्को, रायटर : रूस की एक अदालत ने अमेरिकी इंटरनेट मीडिया कंपनी फेसबुक पर साठ लाख रूबल (करीब 81,350 डालर) का और मैसेजिंग एप टेलीग्राम पर 1.1 करोड़ रूबल का जुर्माना लगाया है। रूस और इन इंटरनेट कंपनियों के बीच तनाव जारी है चूंकि इन अमेरिकी कंपनियों ने अवैध विषय सामग्री को हटाने से मना कर दिया था। रूस पिछले कई महीनों से इंटरनेट मीडिया से जुड़ी कंपनियों पर देश के नियमों के पालन न करने पर जुर्माने जैसी सजाए देकर कार्रवाई करता रहा है। इन विदेशी कंपनियों पर रूस में दफ्तर खोलने और रूसी डाटा का देश के बाहर इस्तेमाल नहीं करने पर दबाव डाला जा रहा है। रूस के तगेन्सकी की जिला अदालत ने गुरुवार को अपने फैसले में कहा कि फेसबुक पर दो प्रशासनिक नियमों के उल्लंघन में साठ लाख रूबल का जुर्माना लगाया गया है।

यूएन में भारत की तारीफ, अध्यक्ष ने शांति और सुरक्षा पर सराहा

संयुक्त राष्ट्र, प्रेट्र : संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष वोल्कन बोज्किर ने अगस्त में सुरक्षा परिषद की भारत की अध्यक्षता के दौरान किए जाने वाले समृद्ध कार्यों के लिए देश की प्रशंसा की। बोज्किर ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति के साथ समन्वय बैठक की। तिरुमूर्ति अगस्त महीने के लिए सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष होंगे।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष के कार्यालय से जारी बयान के अनुसार, तिरुमूर्ति ने बोज्किर को 15 देशों की परिषद की भारत की अध्यक्षता के दौरान होने वाली मुख्य गतिविधियों की जानकारी दी। समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, शांति रक्षा के साथ ही आतंकी कृत्यों से अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को होने वाले खतरों पर उच्च स्तरीय चर्चा पर केंद्रित होगा। उन्होंने महासभा के 76वें सत्र के उच्च स्तरीय सप्ताह की तैयारियों पर भी चर्चा की, जो सितंबर में आयोजित होगा।

बोज्किर ने मुलाकात करने के लिए तिरुमूर्ति का आभार जताया और सुरक्षा परिषद की अधिकतर बैठकों में व्यक्तिगत तौर पर मौजूद रहने और अगस्त के लिए सुरक्षा परिषद के काम के समृद्ध कार्यक्रम के लिए उनकी प्रशंसा की। बयान के मुताबिक, दोनों ही लोगों ने अगस्त के पूरे महीने में एक साथ काम करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। ज्ञात हो, भारत को वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया था। ऐसे में भारत को अगले महीने 15 देशों वाली शक्तिशाली परिषद के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभानी है।

शिनजियांग में उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार के लिए 240 हिरासत केंद्र

दबनचेंग, एपी : शिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों व अन्य अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के लिए चीन ने 240 हिरासत केंद्र बना रखे हैं। अंतरराष्ट्रीय आलोचना के बावजूद उसने यहां ऐसे केंद्रों की संख्या में कोई कमी नहीं की है। कुछ हिरासत केंद्रों में नई इमारत बन रही हैं।

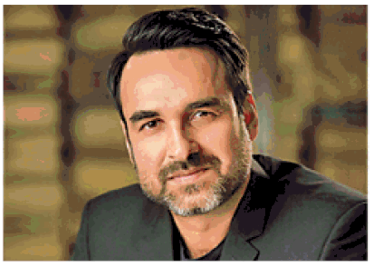
दबनचेंग में ऐसे ही एक हिरासत केंद्र के संबंध में समाचार एजेंसी एपी के संवाददाता ने जाकर तहकीकात की। 220 एकड़ में फैले इस यह हिरासत केंद्र में उइगर मुस्लिमों को रखा गया है। इन कैदियों को एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के जरिये चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास की जानकारी दी जा रही थी।

हालांकि यहां चीनी अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि ऐसे कितने हिरासत केंद्र चल रहे हैं। लेकिन तहकीकात में पता चला कि 240 ऐसे केंद्र कार्य कर रहे हैं, जहां करीब दस हजार उइगर मुस्लिम थे। चीन का तर्क है कि ये केंद्र आतंकवाद से लड़ाई लड़ने के लिए बनाए गए हैं। कई केंद्रों को व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र बताया जाता है।

शिनजियांग के इन हिरासत केंद्रों के बारे में लगातार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता जताई जा रही है। शोधकर्ताओं का मानना है कि विदेश यात्रा करने या धार्मिक समारोह में शरीक होने पर भी सजा देकर उइगरों को यहां बंद कर दिया जाता है। कोलोराडो विवि में उइगरों पर अध्ययन करने वाले मानवविज्ञानी डेरेन बायलर कहते हैं कि ऐसे सैकड़ों लोग हैं, जो बिना अपराध के ही इन केंद्रों में बंद कर दिए गए हैं और यातना का शिकार हो रहे हैं।



इमोशनल सीन के लिए तैयारी नहीं करता



खास मुलाकात

कोरोना काल में जब सिनेमाघर बंद थे तब भी पंकज त्रिपाठी दर्शकों से रूबरू होते रहे। उनकी फिल्में 'गुंजन सक्सेना- द कारगिल गर्ल', 'लूडो', 'कागज' और वेब सीरीज 'मिर्जापुर 2' सहित कई प्रोजेक्ट ओटीटी पर रिलीज हुए। अब वह फिल्म 'मिमी' में कृति सैनन के साथ नजर आएंगे। यह 30 जुलाई को जियो सिनेमा और नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। 'मिमी' सरोगेसी (किराए पर कोख लेना) के मुद्दे पर आधारित है। बीते एक साल के अनुभव, 'मिमी' और आगामी प्रोजक्ट्स को लेकर पंकज से स्मिता श्रीवास्तव की बातचीत के अंश...

पिछले एक साल के घटनाक्रम ने बतौर इंसान आपको कितना बदला?
जीवन में थोड़ा ठहराव आ गया है। जीवन कितना क्षणभंगुर है। उसमें हम गुस्सा, क्रोध एकदूसरे के प्रति कटुता पाले रहते हैं। इस वक्त ने ज्यादा उदार और समझदार बनाया। ज्यादा संवेदनशील बनाया।

सिनेमा में आप जिन किरदारों में दिखते हैं, उससे काफी अलग वेब सीरीज में आपकी छवि दिखती है?
यह महज संयोग है। मुझे अलग-अलग किरदार चाहिए ताकि मेरी दिलचस्पी परफार्मेंस में बनी रहे। हां, फिल्मों में देखें तो 'गुंजन सक्सेना- द कारगिल गर्ल' हो या 'मिमी', मुझे वैरायटी किरदार मिल रहे हैं। ग्रे, डार्क या लाइट हार्टेड किरदार मिल रहे हैं। यह सुखद है।

यह फिल्म सरोगेसी से जुड़े किन मुद्दों को उठा रही है?
मुख्य रूप से यह एक मनोरंजक फिल्म है। यह मनोरंजन करते हुए आहिस्ता से आपके कान में मैसेज दे देती है। बिना चिल्लाए बहुत जरूरी बात कह जाती है। फिल्म में बिना प्रवचन दिए, भाषण दिए, हम एक जरूरी बात कह रहे हैं।

संदेश प्रधान फिल्में अब ज्यादा बन रही हैं...
सिनेमा बहुत बड़ा मीडियम है, उसे सिर्फ मनोरंजन पर हमें खत्म नहीं करना चाहिए। उसके साथ संदेश भी होना चाहिए भले ही वह सब टेक्स्ट के तौर पर हो। वैसे हर कहानी में एक संदेश तो होता ही है।

'मिमी' में क्या खास लगा जो इस फिल्म को स्वीकृति दी?
इस फिल्म के निर्माता दिनेश विजन मेरे करीबी हैं। हमने साथ में 'लुकाछुपी' और 'स्त्री' की थी। शुरुआत में मैं कहानी सुनकर द्वंद्व में था। उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहिए। मैं उनपर भरोसा करता हूं तो निश्चिंत हो गया। शूटिंग में मजा आया।

इंडस्ट्री में कहते हैं कि दोस्ती बहुत ज्यादा नहीं चलती। एक प्रोजेक्ट के बाद खत्म हो जाती है...
नहीं ऐसा नहीं है। दोस्ती का प्रोजेक्ट से कोई लेना-देना नहीं है। वैसे मेरा कोई दोस्त नहीं है। मुझे लाइक माइंडेड लोगों से बातचीत करना अच्छा लगता है।

राजस्थान में शूटिंग का अनुभव कैसा रहा?
मैं पहले भी वहां गया हूं। हम शेखावटी में थे। वहां झुंझुनू, चुरु, मंडावा गए। शेखावटी बहुत खूबसूरत है। वहां का आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत है। शूटिंग के बाद मैं रोज घूमता था। मंडवा हेरिटेज टाउन है। हम वहीं पर रह रहे थे। हमारा होटल भी सौ साल पुरानी इमारत थी। खाना भी बहुत जायकेदार लगा। शूटिंग के दौरान वहां के लोग मिलने भी आ जाते थे।

फिल्म के ट्रेलर में थप्पड़ वाला सीन करने में कितने सहज रहे?
फिल्म में सिचुएशन ही ऐसी है कि कोई भी लड़की थप्पड़ ही मारेगी। उस सीन में थप्पड़ मारने के अलावा भी बहुत कुछ है। फिल्म में बहुत सुंदर पंच है। थोड़े इमोशनल सींस हैं। उनको मेलोड्रामा से बचाना था। रियल भी लगना था। मेरे ऊपर ठप्पा लग चुका है कि बहुत अंडर प्ले करता हूं। मेरी चाहत थी कि इसमें बाउंड्री को थोड़ा बड़ा करूं, लेकिन वह मेलोड्रैमैटिक भी न लगे। इसमें मैंने अपना सुर बढ़ाया है। देखते हैं दर्शक उसे कितना पसंद करते हैं।

'बरेली की बर्फी', 'लुकाछुपी' के बाद कृति सैनन के साथ 'मिमी' आपकी तीसरी फिल्म है...
बहुत अच्छी बांडिंग है हमारी। परफार्मेंस के स्तर पर हम एकदूसरे को समझते हैं। इसमें मेरा और उनका रिश्ता यूनीक है। इसमें एक अलग प्योरिटी (पवित्रता) है।

फिल्म में सरोगेसी से किरदार अपरिचित है। फिल्म कहीं पीछे तो नहीं रह गई?
(गंभीर होते हुए) नहीं। उसके बारे में शहरी लोग भलीभांति परिचित हैं। अगर आप हिंदुस्तान के अंदरूनी इलाकों में जाएं तो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। हमारी कहानी शेखावटी के एक छोटे से कस्बे में सेट है।

आपके लिए इमोशनल सीन करना कितना कठिन होता है?
इमोशनल सीन करना टफ होता है। उसे मैं प्रिपेयर नहीं कर पाता हूं। उसे आर्गेनिक ही रखता हूं। उस वक्त जो आएगा नेचुरल होगा। इमोशनल सीन की तैयारी आप क्या करेंगे? जितने इमोशनल क्षण हमारी जिंदगी में आते हैं वे अनापेक्षित होते हैं। सिनेमा में हमें रीक्रिएट करना होता है। मैं उसके लिए रिहर्सल नहीं करता हूं। सीन के समय ही उसमें उतरने की कोशिश करता हूं कि शायद मेरा इंपल्स काम कर जाए।

'बच्चन पांडे' में अक्षय कुमार के साथ काम का कैसा अनुभव रहा?
बहुत बढ़िया। पहली बार मैं उनसे आमने-सामने इस फिल्म में ही मिला। वह गर्मजोशी से मिले। उनका सेंस आफ ह्यूमर बहुत तगड़ा है। उनकी कंपनी में मजा आया।

बालीवुड ट्रेंड

एक्टिंग के साथ बिजनेस भी समझते हैं सितारे

अभिनय के साथ अपनी पसंद के कंटेंट का हिस्सा बनने के लिए कलाकार फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी सक्रिय रहे हैं। बीते दौर में स्वर्गीय गुरु दत्त, राज कपूर से लेकर आजकल अमिताभ बच्चन, शाह रुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, अनुष्का शर्मा, कंगना रनोट, लारा दत्ता, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा इत्यादि कलाकार फिल्म निर्माण में भी सक्रिय हैं। पिछले दिनों आलिया भट्ट, ईशा देओल तख्तानी, रिचा चड्ढा, अली फजल, तापसी पन्नू, विद्युत जामवाल ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के तहत फिल्मों का ऐलान किया है। फिल्म निर्माण में कलाकारों की रुचि, दूसरे निर्माताओं के साथ साझेदारी व बिजनेस की अन्य चुनौतियों की पड़ताल की स्मिता श्रीवास्तव व प्रियंका सिंह ने ...

पिछली सदी के पांचवें और छठवें दशक में कई अभिनेताओं ने फिल्मों का निर्माण किया। गुरु दत्त ने अपने बैनर गुरु दत्त मूवीज प्राइवेट लिमिटेड के तहत 'आर पार' (1954), 'सीआईडी' (1956) और 'प्यासा' (1957) जैसी बेहतरीन फिल्मों का निर्माण किया। देव आनंद की कंपनी नवकेतन फिल्म्स ने 'हरे रामा हरे कृष्णा', 'गाइड', 'ज्वैलथीफ' जैसी हिट फिल्में दीं। इन अभिनेताओं ने उन फिल्मों को बनाया जिन पर वे विश्वास करते थे। आज के अभिनेता, अपनी ब्रांड छवि के बारे में जागरूक हैं, वे उन फिल्मों का निर्माण पसंद करते हैं, जिनसे वे जुड़ना चाहते हैं।

नए विषयों को उठाने का जोखिम: जान अब्राहम की कंपनी जेए एंटरटेनमेंट के प्रोडक्शन तले पहली फिल्म 'विकी डोनर' बनाई थी। स्पर्म डोनेशन जैसे टैबू विषय पर आधारित फिल्म 'विकी डोनर' को बनाने में करीब नौ करोड़ रुपये खर्च हुए जबकि फिल्म ने 44 करोड़ रुपये की कमाई की। हालांकि उनसे पहले अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और अजय देवगन जैसे अभिनेता अपने पहले प्रयास में हाथ जला चुके थे, पर उन्होंने हार नहीं मानी और फिल्म निर्माण का क्रम जारी रखा। अजय देवगन ने 30 करोड़ रुपये बजट से फिल्म 'राजू चाचा' बनाई थी, पर वह फ्लाप रही। अमिताभ बच्चन की कंपनी एबीसीएल ने 'तेरे मेरे सपने' (1996), मृत्युदाता (1997), अक्स (2001) जैसी फिल्में बनाईं, लेकिन खराब वित्तीय प्रबंधन, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के कारण वे विफल रहीं। एबीसीएल को एबी कार्पोरेशन लिमिटेड के रूप में पुनर्जीवित किया गया और रिलायंस बिग पिक्चर्स के साथ फिल्म 'पा' का निर्माण किया गया। बिग बी और अभिषेक बच्चन अभिनीत 15 करोड़ रुपये की फिल्म ने लगभग 60 करोड़ की कमाई की। शाहरुख खान और आमिर खान साल 2000 की शुरुआत में निर्माता बने और सफल रहे। आमिर खान की बतौर निर्माता पहली फिल्म 'लगान' (2000) को बनाने में करीब 25 करोड़ रुपये की लागत आई थी और इसने करीब 75 करोड़ रुपये कमाए।

स्टूडियो किसी को जज नहीं करता: कई बड़े स्टूडियोज हैं, जो निर्माताओं के साथ मिलकर फिल्में बनाते हैं। इस बाबत रिलायंस एंटरटेनमेंट के सीईओ शिबाशीष सरकार कहते हैं, 'फिल्म प्रोडक्शन की एक्टिविटी और एक्टर जो किरदार फिल्म में निभाते हैं, वे दो अलग चीजें हैं। अगर कोई निर्माता कोई कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है तो स्टूडियो सबसे पहले यही देखता है कि क्रिएटिव इनपुट्स क्या हैं, निर्देशक कौन है, कहानी कैसी है। एक्टर कौन है या वह फिल्म का निर्माण कर रहा है? इससे ज्यादा जरूरी है यह देखना है कि उनकी आर्गेनाइजेशन का कहानी कहने का तरीका और विस्तार क्या है। अगर क्रिएटिव बात होगी, तो फिर चाहे एक्टर की प्रोडक्शन कंपनी हो या निर्देशक की या फिर स्टैंड अलोन निर्माता जैसे साजिद नाडियाडवाला, दिनेश विजन की कंपनी हो, जो सिर्फ निर्माता हैं और निर्देशन या एक्टिंग के क्षेत्र से नहीं आते हैं, उन्हें स्टूडियो अलग तरह से जज नहीं करता है। जब एक्टर प्रोडक्शन का हिस्सा होता है और फिल्म में एक्टिंग भी कर रहा होता है तो कई बार फायदेमंद हो जाता है। एक्टर्स अच्छे क्रिएटिव इनपुट्स देते हैं। हालांकि निर्माता बने एक्टर के लिए निर्देशक और लेखक को ओवरशैडो न करते हुए एक संतुलन बनाए रखना जरूरी है।'

विश्वसनीयता बढ़ाते हैं सितारे: ट्रेड विशेषज्ञ और निर्माता गिरीश जौहर कहते हैं, 'एक्टर्स निर्माता बनने के बाद अपने कंटेंट और मनपसंद कहानी को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। इकोनामिक्स के साथ क्रिएटिविटी को कैसे मिक्स किया जाता है, इसकी समझ भी उन्हें होती है। उनके ब्रांड नेम की वजह से प्रोडक्शन हाउस के प्रमोशन पर ज्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ता है। एक विश्वसनीयता जुड़ जाती है। हर एक्टर का अपना दायरा होता है। कोई क्रिएटिविटी पर ज्यादा ध्यान देता है, कोई कहानी को लेकर ज्यादा सतर्क होता है। वे जिस उद्देश्य के साथ प्रोडक्शन हाउस शुरू करते हैं, उसकी ओर ही अग्रसर रहते हैं। यही वजह है कि पहले के कलाकारों के मुकाबले प्रोडक्शन में वे नुकसान से बचे रहते हैं। डिजिटल प्लेटफार्म ने भी उनके लिए मौके बढ़ा दिए हैं। निर्माता बनने के बाद इकोनोमिक कंट्रोल की समझ बढ़ जाती है कि जितना बजट तय है, उसी में फिल्म को बनाना है। शूटिंग समय पर पूरी करनी है।'

टेबल की दूसरी तरफ की दिक्कतों का एहसास: अजय देवगन के साथ फिल्म 'द बिग बुल' का सह निर्माण कर चुके निर्माता आनंद पंडित ने अमिताभ बच्चन के साथ अपनी आगामी फिल्म 'चेहरे' का सह निर्माण किया है। वह कहते हैं, 'उनका जो तजुर्बा था वह हमारे काम आया। जब एक अनुभवी अभिनेता आपके साथ बतौर निर्माता जुड़ता है तो एक और एक ग्यारह हो जाते हैं। एक कंफर्ट लेवल आ जाता है कि एक स्टार आपके साथ बतौर निर्माता जुड़े हैं। उनके कनेक्शन, उनकी फिल्म को लेकर समझ फिल्म को बेहतर बनाने में योगदान देती है। मैं पसंद करता हूं कि कोई स्टार बतौर निर्माता मेरे साथ काम करे। कलाकारों का फिल्म निर्माण में उतरना सकारात्मक कदम है, क्योंकि इसकी वजह से उन्हें टेबल की दूसरी तरफ यानी निर्माताओं की दिक्कतों का एहसास होगा।'

मुनाफे में हिस्से की कहानी: अक्षय कुमार, शाह रुख खान या आमिर खान एक फिल्म में अभिनय करने के लिए लगभग 20-25 करोड़ रुपये लेते हैं, वहीं सह-निर्माता के रूप में वे लाभ का बड़ा हिस्सा लेने के लिए सहमत होते हैं। अगर कोई फिल्म अच्छा प्रदर्शन करती है तो अभिनेता और स्टूडियो दोनों को फायदा होता है। अगर फिल्म खराब प्रदर्शन करती है तो स्टूडियो को अभिनय के लिए मोटी फीस नहीं देनी पड़ती। फिल्म जानकारों के मुताबिक भारत में मुख्य अभिनेता की कुल फीस फिल्म लागत का लगभग 35 प्रतिशत हिस्सा होती है। जब लागत का एक घटक इतना अधिक होता है तो जोखिम को कम करना आवश्यक होता है। ऐसा करने का एक अच्छा तरीका यह है कि परियोजना के लिए अग्रिम वित्तीय प्रतिबद्धता को कम किया जाए। अभिनेता को जोड़ा जाए ताकि रिस्क को कम किया जा सके।

अहम है चुनौतियों के लिए तैयार होना: पिछली सदी के विपरीत आज बड़ी संख्या में अभिनेत्रियां जैसे लारा दत्ता, दीया मिर्जा, दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा, कंगना रनोट, रिचा चड्ढा फिल्म निर्माण में कदम रख चुकी हैं। इंडस्ट्री में महिला प्रोड्यूसर की बढ़ती तादाद के बाबत निर्देशक से निर्माता बनीं अश्विनी अय्यर तिवारी कहती हैं, 'महिलाएं बड़े पदों पर जिम्मेदारियां निभा रही हैं। यहां पर सवाल महिला या पुरुष का नहीं है। सवाल यह है कि क्या आप बड़े चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं। मेरे लिए प्रोड्यूसर होने का अर्थ है कि मैं युवा लेखकों, प्रतिभाशाली लोगों को प्रोत्साहित कर सकूं हूं जो निर्देशक बन सकते हैं और अपनी कहानी कहना चाहते हैं। मुझे भी यह मौका मिला था जब आनंद एल राय ने मेरी 'निल बटे सन्नाटा' की कहानी सुनी तो उन्होंने कहा कि तुम्हें निर्देशन करना चाहिए। एडवरटाइजिंग से मैं निर्देशन में आई। निल बट्टे सन्नाटा के बाद एकता कपूर ने मुझसे कहा था कि तुम निर्देशक से कहीं ज्यादा हो तुम्हें प्रोड्यूसर बनना चाहिए क्योंकि प्रोड्यूसर में टैलेंट, अच्छी कहानी को पहचानने की क्षमता होती है। यह सिर्फ प्रोडक्शन की बात नहीं है।'





नई प्रतिभाओं को देना है मौका

विद्युत जामवाल ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी एक्शन हीरो फिल्म्स की पहली फिल्म 'आईबी 71' का ऐलान किया है। इस फिल्म का निर्माण वह रिलायंस एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर करेंगे। निर्माता बनने की वजह बताते हुए विद्युत कहते हैं कि जितना मुझे फिल्म इंडस्ट्री से मिला है, उतना ही अच्छा देने की कोशिश करूंगा। मैं अपनी निर्माण कंपनी को प्रतिभाशाली लोगों को आगे बढ़ाने के अवसर के तौर पर देख रहा हूं। विद्युत की तरह ही सोच रखती हैं हाल ही में निर्माता बनी तापसी पन्नू। वह कहती हैं कि अपने प्रोडक्शन हाउस आउटसाइडर्स फिल्म्स की फिल्मों में आउटसाइडर्स को मौका देकर इंडस्ट्री का कर्ज उतारना चाहती हूं।



क्षेत्रीय कहानियों को प्रमोट करने की ख्वाहिश

प्रियंका चोपड़ा ने अपने प्रोडक्शन हाउस पर्पल पेबल्स पिक्चर्स तले फिल्म 'द स्काई इज पिंक' और 'द व्हाइट टाइगर' बनाईं। दोनों ही फिल्मों से प्रियंका बतौर कलाकार भी जुड़ीं। उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्में बनाने की भी इच्छा जाहिर की है। वह कहती हैं कि मेरे पिता सेना में थे। उनकी पोस्टिंग देश के कई हिस्सों में हुई थी। जिससे मैं देश के कई स्थानों और संस्कृतियों में पली-बढ़ी हूं। बतौर निर्माता मैं लोकल कहानियों को सपोर्ट करने की इच्छा पूरी कर पा रही हूं। मैं ऐसा कंटेंट बनाना चाहती हूं जिसमें नए फिल्ममेकर्स और नई प्रतिभाओं को मौका मिले।

सेलेब स्पीक

जो दिल चाहता है वह करती हूं



फिल्म 'तैश' के बाद अभिनेत्री कृति खरबंदा अभिनीत फिल्म '14 फेरे' डिजिटल प्लेटफार्म जी5 पर आज रिलीज हुई है। इस फिल्म, शादी की योजना जैसे कई मुद्दों पर उनसे बातचीत के अंश:

'तैश' के बाद यह आपकी दूसरी फिल्म है जो डिजिटल पर आ रही है। आप दर्शकों के बीच बनी हुई हैं...
'तैश' जब रिलीज हो रही थी, तब मैं डरी हुई थी। पहले बाक्स आफिस नंबर्स बोलते थे, अब डिजिटल प्लेटफार्म पर फिल्में देखकर लोग अपनी राय देते हैं। पहले नंबर्स की वजह से बच जाते थे। अब उसके पीछे नहीं छुप सकते हैं। '14 फेरे' पारिवारिक फिल्म है। अनेक फिल्में शूट होकर रिलीज का इंतजार कर रही हैं। ऐसे में मेरी फिल्म कम से कम दर्शकों तक पहुंच रही है। यह बात खुशी देती है।

खुद को साबित करने के बाद भी क्या यह डर रहता है कि लोग भूल जाएंगे?
यह डर जब तक जिंदा है, आप मेहनत करते रहेंगे। आउट आफ साइट, आउट आफ माइंड, यूं ही नहीं बोला जाता। मुझे इतना काम करना है कि मेरे जाने के बाद भी लोग मुझे याद रखें।

'14 फेरे' के ट्रेलर में कालेज के सीन में आप रैगिंग में विक्रांत मेस्सी से माफी मांगने को कहती हैं। रियल लाइफ में कालेज में कैसे रही हैं?
मैं कालेज सिर्फ छह महीने के लिए गई हूं। बहुत कम उम्र से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। मैं स्कूल में सख्त हाउस कैप्टन रही हूं। यह रोल करते हुए वे यादें ताजा हो गई थीं। इस किरदार में मुझे खुलकर जीने का मौका मिला।

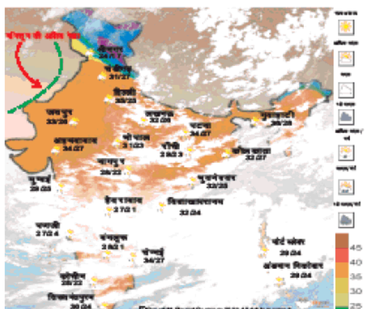
दूसरों से गलती स्वीकार करने की अपेक्षा रखने या स्वयं माफी मांगने को लेकर क्या सोचती हैं?
जब तक मुझमें मैच्योरिटी नहीं आई थी, तब तक लगता था कि फलां ने गलती की, लेकिन माफी नहीं मांगी। अब लगता है मैं समय बर्बाद कर रही थी। मैं किसी और की जिंदगी पर नियंत्रण नहीं कर सकती हूं। यह समझ उम्र और अनुभव के साथ आती है। मैं समझ गई हूं कि लोग जैसे हैं, वैसे ही रहेंगे। मैं बहुत जल्दी अपनी गलती का एहसास करके माफी मांग लेती हूं। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि इससे रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं।

फिल्म '14 फेरे' करने के बाद अब रियल लाइफ में शादी की तैयारियां खुद करेंगी या स्वजनों पर छोड़ देंगी?
(सोचते हुए) नहीं, मुझे हर चीज पर नियंत्रण चाहिए। मैं जो करूंगी, वह खुद करना चाहूंगी। वैसे मैं मानती हूं कि अगर आप किसी के साथ भावनात्मक तौर पर जुड़े हैं तो मंदिर में फेरे लो या हजार लोगों के बीच शादी करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिश्ता पवित्र होना चाहिए।

आप और पुलकित सम्राट शादी करने के बारे में सोच रहे हैं?
हमने इस बारे में अब तक बात नहीं की है। मैं अपनी जिंदगी को लेकर बहुत ओपन रही हूं, जब जो होगा, सबको पता चल जाएगा।

आपने जिंदगी को खुली किताब की तरह रखा हुआ है। कभी लगता है कि लोग फायदा उठा सकते हैं?
मैं उसका तनाव नहीं लेती हूं। मैं वह करती हूं, जो मेरा दिल चाहता है। मेरे लिए खुद को खुश रखने से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। जब मैं खुश रहूंगी तो मेरे आसपास के लोग भी खुश रहेंगे। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। उनकी सोच मैं नहीं बदल सकती। मैं स्वयं को प्राथमिकता देती हूं।

प्रियंका सिंह





पहली बार भारत में रेडियो ब्राडकास्ट सेवा की शुरुआत

वर्ष 1927 में आज ही मुंबई से निजी ट्रांसमीटर से रेडियो ब्राडकास्ट सर्विस की शुरुआत हुई थी। 1930 में सरकार ने इसका अधिग्रहण किया और भारतीय प्रसारण सेवा नाम रखा। 1936 में इसका नाम आल इंडिया रेडियो और 1957 में आकाशवाणी कर दिया गया।



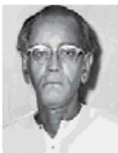


दुनिया के सबसे पुराने खेल परिसंघ की स्थापना

वर्ष 1881 में आज ही इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन की बेल्जियम में स्थापना हुई थी। विश्व के सबसे पुराने परिसंघ में 1921 तक बेल्जियम, फ्रांस और नीदरलैंड ही सदस्य थे। गैर यूरोपियन देशों के शामिल होने के बाद यूरोपियन फेडरेशन आफ जिम्नास्टिक नाम रखा गया।

आजादी की लड़ाई में जेल गए थे ताराशंकर बंद्योपाध्याय

मशहूर बांग्ला लेखक ताराशंकर बंद्योपाध्याय का जन्म आज ही वर्ष 1898 में बंगाल के बीरभूम जिले में हुआ था। देश की आजादी की लड़ाई में इन्हें जेल जाना पड़ा था। इन्होंने 65 उपन्यास, 53 कहानी, 12 नाटक, कुछ निबंध, आत्मकथा और यात्रावृतांत लिखे हैं। 1952 से 1960 तक बंगाल विधान परिषद के सदस्य रहे। इन्हें साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, पद्मश्री, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1960 से 1966 तक राज्यसभा सदस्य रहे। 14 सितंबर, 1971 को कोलकाता में निधन हो गया था।



इधर-उधर की

गिलहरी को बचाने की कोशिश में घर में घुसी कार



अब्राहम लिंकन के पूर्वजों ने बनाया था घर। इंटरनेट मीडिया

मैसाच्युसेट्स, एजेंसी : दूसरे की जान बचाने के चक्कर में खुद की जान पर आ गई। अमेरिका के मैसाच्युसेट्स में ऐसा ही वाकया हुआ, जहां एक गिलहरी को बचाने के चक्कर में लड़की कार लेकर ऐतिहासिक घर से जा टकराई। इस घर को अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के पूर्वजों ने 1650 में बनाया था। पुलिस विभाग ने कहा, 19 साल की लड़की ने सड़क पर जा रही गिलहरी को बचाने के चक्कर में कार को दाईं तरफ पटरी की ओर घुमा दिया, जिससे कार घर में जाकर टकरा गई। आधी कार घर में घुस गई थी। हालांकि वहां मौजूद किसी शख्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।

एंजाइम से रीसाइकिल होगा प्लास्टिक

मिलेगी मदद ▶ शोधकर्ताओं ने तलाशा प्लास्टिक प्रदूषण से निजात दिलाने का बेहतर रास्ता

नए तरीके में ऊर्जा की खपत और ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होता है कम



प्लास्टिक की समस्या होगी कम। फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

वाशिंगटन, एएनआइ : प्लास्टिक प्रदूषण वर्तमान में एक ऐसी समस्या बन गई है, जिसके समाधान के लिए दुनिया भर के विज्ञानी प्रयासरत हैं। इसके बावजूद प्लास्टिक कचरे की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। अब इस कड़ी में शोधकर्ताओं ने एक ऐसा रास्ता तलाशा है, जिससे इस समस्या के समाधान में कुछ मदद मिल सकती है। दरअसल, एक नवीन अध्ययन के दौरान शोधकर्ताओं ने पाया कि पालीइथाइलीन टेरेफ्थेलेट (पीईटी) को रीसाइकिल करने के लिए एंजाइम प्रयोग में लाए जा सकते हैं। पीईटी एक सामान्य प्लास्टिक है, जिसका प्रयोग एक बार इस्तेमाल होने वाली बोतलों, कपड़ों व खाद्य पदार्थों की पैकिंग आदि के लिए किया जाता है। इसकी मात्रा बढ़ने से प्लास्टिक प्रदूषण में वृद्धि हो रही है।

अमेरिकी ऊर्जा विभाग (डीओई) के राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा प्रयोगशाला (एनआरईएल) और पोर्ट्समाउथ विश्वविद्यालय सहित बोटल कंसोर्टियम के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए इस अध्ययन को जौल जर्नल में प्रकाशित किया गया है। इस अध्ययन से पता चला है कि एंजाइम से पीईटी को प्रभावी तरीके से रीसाइकिल करने में सक्षम हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक, इस नए तरीके से पीईटी को रीसाइकिल करने में परंपरागत तरीकों की तुलना में कम ऊर्जा की खपत होगी।

शोधकर्ताओं का कहना है कि यदि इस नई प्रणाली का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाए तो भविष्य में पीईटी को रीसाइकिल करने के लिए नए द्वार खुल सकते हैं। पीईटी दुनिया में सबसे अधिक उत्पादित सिंथेटिक पालिमर में शुमार है, जिसमें सालाना 82 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन होता है। पीईटी का लगभग 54 फीसद प्रयोग कपड़ों और कालीनों के लिए फाइबर के निर्माण में किया जाता है।

एनआरईएल में केमिकल इंजीनियर और एंजाइम-आधारित रीसाइक्लिंग की दिशा में इस शोध की पहली लेखक अवंतिका सिंह के मुताबिक, 1950 के बाद से जितना भी प्लास्टिक बना है उसका 10 फीसद से भी कम रीसाइकिल किया जा सका है। अधिकांश अपशिष्ट प्लास्टिक लैंडफिल में समाप्त हो जाते हैं। इस शोध के अन्य लेखक बोटल कंसोर्टियम से जुड़े हैं। बोटल कंसोर्टियम प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या से निजात दिलाने के लिए दो नवीन दृष्टिकोणों पर कार्य कर रहा है। पहला यह कि ऐसा तरीका तलाशा जाए, जिससे ऊर्जा की बचत हो और कम कीमत में बड़े पैमाने पर प्लास्टिक को रीसाइकिल किया जा सके। दूसरा यह है कि माडर्न प्लास्टिक तैयार किया जाए, जिसे आसानी से रीसाइकिल किया जा सके। यह नवीन अध्ययन प्लास्टिक को रीसाइकिल करने में आने वाली चुनौतियों के बारे में बताता है। इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए शोधकर्ताओं ने रीसाइकिल के लिए एक माडल तैयार किया है, जो अमेरिका में हर साल निकलने वाले तीन मिलियन मीट्रिक टन पीईटी के एक बड़े हिस्से को रीसाइकिल करने में सक्षम होगा।

इस तरह काम करती है नई विधि

शोधकर्ताओं के मुताबिक, एंजाइमेटिक रीसाइक्लिंग प्रक्रिया पीईटी को उसके दो बिल्डिंग ब्लाक्स, टेरेफ्थेलिक एसिड (टीपीए) और एथिलीन ग्लाइकॉल में तोड़ देती है। शोधकर्ताओं के दल ने पाया कि पारंपरिक प्रक्रियाओं की तुलना में इस प्रक्रिया में 69 से 83 फीसद कम ऊर्जा की खपत होती है और प्रति किलोग्राम में ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन भी 17 से 43 फीसद कम होता है। शोधकर्ताओं का दावा है कि यदि इस प्रक्रिया को बेहतर ढंग से अपनाने में कामयाब रहे तो अमेरिका में पूरी रीसाइकिल प्रक्रिया में 95 फीसद तक इस प्रक्रिया का प्रयोग किया जा सकता है। इससे पर्यावरण को भी कम नुकसान होगा, क्योंकि ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आएगी, साथ ही ऊर्जा की भी बचत हो सकेगी।

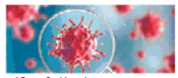


युवक ने खोजी गुफाएं...

इंग्लैंड के अब्रोथ के कैमरून स्मिथ ने स्काटलैंड के एंगस तट के समीप मोबी की गुफाओं की खोज की है। यह अब्रोथ चट्टानों के नीचे गुफाओं के एक नेटवर्क का हिस्सा है। इन्हें स्मगलर गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है। स्मिथ का कहना है कि यह एक संयोग था कि वह इन गुफाओं का पता लगाने में सफल हुए। उन्होंने कहा, वक्त काटने के लिए वह इस क्षेत्र में टहल रहे थे और यहां के नजारों को कैमरे में कैद कर रहे थे। अचानक उन्हें इन गुफाओं का पता चला। यहां लगभग 12 गुफाएं हैं। उनके साथी जेन बारलो ने इन तस्वीरों का खींचा। एएफपी

बुजुर्गों में कम बन सकती है कोरोना के खिलाफ एंटीबाडी

अनुसंधान



अमेरिका की ओरेगन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के अध्ययन में आया सामने। फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

कोरोना वायरस (कोविड-19) के खिलाफ एंटीबाडी को लेकर एक नया अध्ययन किया गया है। इसका दावा है कि युवाओं की तुलना में बुजुर्गों में कम मात्रा में एंटीबाडी बन सकती है। एंटीबाडी एक प्रकार का ब्लड प्रोटीन है, जिसकी उत्पत्ति प्रतिरक्षा प्रणाली (इम्यून सिस्टम) संक्रमण से बचाव के लिए करती है। कोरोना संक्रमण के खिलाफ बचाव में भी इसकी अहमियत जाहिर हुई है। अमेरिका की ओरेगन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी (ओएचएसयू) के शोधकर्ताओं के अनुसार, एक नए अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है। अध्ययन के प्रमुख शोधकर्ता और ओएचएसयू के असिस्टेंट प्रोफेसर फिकाडु टफेस ने कहा, 'टीके के बावजूद हमारे बुजुर्ग कोरोना के नए वैरिएंट के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं।' उन्होंने कहा, 'बुजुर्ग टीकाकरण के बावजूद सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए इनके साथ रहने वाले लोगों को भी वैक्सीन लगवाने की जरूरत है।' शोधकर्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि बुजुर्गों में भले एंटीबाडी की कम प्रतिक्रिया पाई गई हो, लेकिन हर उम्र के ज्यादातर लोगों में वैक्सीन न सिर्फ संक्रमण की रोकथाम, बल्कि इसे गंभीर होने से रोकने में भी कारगर साबित हुई है। शोधकर्ताओं ने 50 बुजुर्गों और युवाओं को दो समूहों में बांटकर यह अध्ययन किया। वैक्सीन की दूसरी डोज लगने के दो हफ्ते बाद इन प्रतिभागियों के रक्त नमूनों की जांच की गई। 70 से 82 वर्ष के बुजुर्गों की तुलना में 20 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों में करीब सात गुना अधिक एंटीबाडी की प्रतिक्रिया पाई गई। -एएनआइ



अमेरिका में मिला माइक्रोसार का जीवाश्म

अमेरिका में एक अंगुली के आकार का माइक्रोसार का जीवाश्म खोजा गया है। यह तस्वीर कैरलटन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने जारी की है। उनका दावा है कि करीब 30 करोड़ वर्ष पहले छोटे आकार के डायनासोर जैसे जीव भी पाए जाते थे। शोधकर्ताओं ने कहा है कि नई प्रजाति के इन माइक्रोसार के अध्ययन से पता चला है कि बेहद छोटे डायनासोर का भी धरती पर अस्तित्व था। एएफपी

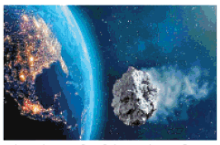
कल रात धरती के करीब से गुजरेगा क्षुद्र ग्रह

जागरण संवाददाता, नैनीताल

ब्रह्मांड में लगातार अनंत खगोलीय घटनाएं घटती रहती हैं। इन्हीं में से एक है क्षुद्र ग्रह (एस्टेरायड) का धरती के पास से गुजरना। डायनासोर जैसे विशालकाय जीवों का अस्तित्व मिटाने में भी इन्हीं का हाथ रहा है। अब शनिवार की रात एक और बड़े आकार का क्षुद्र ग्रह धरती के पास से गुजरने जा रहा है। हालांकि, इससे धरती को किसी तरह से नुकसान की कोई आशंका नही है।

> इस साल अब तक 92 लघु पिंड गुजर चुके हैं पृथ्वी के नजदीक से

आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान (एरीज) के खगोल विज्ञानी डा. शशिभूषण पांडेय के अनुसार, एक क्षुद्र ग्रह 24-25 जुलाई को धरती के करीब से गुजर जाएगा। इसका नाम 2008 जीओ 20 है। इसका आकार 200 मीटर से अधिक है। यह आठ किमी प्रति सेकेंड की गति से आगे बढ़ रहा है। करीब से गुजरने के दौरान इसकी पृथ्वी से दूरी करीब 28 लाख किमी होगी, जिस कारण इसके धरती से टकराने की कोई आशंका नहीं है।



एस्टेरायड के कारण ही धरती से डायनासोर का अस्तित्व धरती से खत्म हुआ था। फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

इसके बाद इस वर्ष तीन और विशाल आकार के क्षुद्र ग्रह धरती के करीब से गुजरेंगे। डा. पांडेय के मुताबिक, इस वर्ष अभी तक 92 क्षुद्र ग्रह धरती के करीब से गुजर चुके हैं। इनमें तीन दर्जन ऐसे थे, जिनके धरती के पास पहुंचने की जानकारी ही नहीं थी। इनका आकार एक मीटर से भी कम का था। ऐसे पिंडों से धरती को कोई खतरा भी नहीं होता है, क्योंकि यह पृथ्वी के करीब पहुंचते ही यहां के वातावरण से टकराकर जलकर नष्ट हो जाते हैं।

एपोफिश से टकराने की अब कोई आशंका नहीं : अभी कुछ समय पहले तक विज्ञानी आशंका जता रहे थे कि पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा खतरा एपोफिश नामक क्षुद्र ग्रह से है, जो 2036 में धरती के करीब आएगा। नासा के ताजा अध्ययन के मुताबिक, यह भी धरती के करीब से होकर गुजर जाएगा।

स्क्रीन शॉट

कपिल के शो से गैरमौजूदगी पर निराश हैं सुमोना!



कभी कपिल की पत्नी तो कभी उनकी पड़ोसन के किरदार में नजर आ चुकी हैं सुमोना। इंस्टाग्राम

द कपिल शर्मा शो बहुत जल्द फिर से टीवी पर शुरू होने वाला है। इसकी घोषणा खुद कामेडियन कपिल शर्मा ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर साझा करके की थी। कपिल ने लिखा था नई शुरुआत उन्हीं पुराने चेहरों के साथ। इन चेहरों में कपिल, कृष्णा अभिषेक, भारती सिंह, चंदन प्रभाकर, सुदेश लहरी, कीकू शारदा के बीच एक चेहरा कम नजर आया, वो था सुमोना चक्रवर्ती का। सुमोना अरसे से कपिल शर्मा के शो का हिस्सा रही हैं। इस बात का दुख सुमोना ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखकर जताया। पोस्ट में उन्होंने किसी का नाम नहीं लिखा है, लेकिन जो भी लिखा है, उसका इशारा कपिल के शो की तरफ ही लग रहा है। सुमोना लिखती हैं, 'अगर आप किसी चीज को मौका नहीं देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि वह चीज आपके लिए बनी है या नहीं। फिर चाहे वह रिश्ता हो, एक नई नौकरी हो, नया शहर या फिर एक नया अनुभव हो। खुद को उसमें पूरी तरह से झोंक दें, मन में कुछ भी न रखें। अगर असफल हो जाते हैं तो समझ लेना कि वह चीज आपके लिए बनी ही नहीं थी। तब आप बिना किसी पछतावे के आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने उसके लिए बहुत मेहनत की थी। आप बस यही कर सकते हैं। यह जानना डरावना लगता है कि आप किसी परिस्थिति को यह जानते हुए छोड़ देते हैं कि आप उसमें और बेहतर कर सकते थे और करना भी चाहिए था। वह मौका पाने के लिए हिम्मत जुटाएं, अगला कदम बढ़ाने के लिए प्रेरणा ढूंढे और जब वह मिल जाए तो उसमें दिल लगाकर जुट जाएं। फिर पीछे मुड़कर न देखें।'

मिस्र में शूट होगा खुदा हाफिज चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा का आखिरी शेड्यूल

पिछले साल डिजिटल प्लेटफार्म पर रिलीज हुई फिल्म खुदा हाफिज के सीक्वल की घोषणा कुछ वक्त पहले हुई थी। फिल्म पर काम शुरू भी हो चुका है। मुंबई में एक छोटा सा शेड्यूल शूट करके फिल्म की टीम अगस्त के पहले हफ्ते में उत्तर प्रदेश में अगले शेड्यूल की शूटिंग करेगी। फिल्म का नाम खुदा हाफिज चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा होगा। दैनिक जागरण से बात करते हुए फिल्म के निर्माता अभिषेक पाठक ने बताया कि फिल्म का आखिरी शेड्यूल मिस्र में शूट करने की योजना है। तब तक कोरोना को लेकर माहौल कैसा होगा, इसको लेकर किसी को कोई जानकारी फिलहाल नहीं है। मिस्र में शूटिंग को लेकर जो नियम हैं, वे बेहतर हैं। फिर भी हमने वहां का शेड्यूल आखिर में रखा है। यहां पर भी वैक्सीनेशन तब तक ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में हम सभी गाइडलाइंस के मुताबिक अगस्त के पहले हफ्ते से शूटिंग शुरू करेंगे। वहां पर भी जिन लोकेशन पर शूटिंग की इजाजत है, वहीं पर शूटिंग होगी। पहले हम स्क्रिप्ट के मुताबिक लोकेशन चुनते थे, लेकिन अब जहां टीम के लिए सुरक्षित माहौल होगा उन्हीं जगहों को चुनकर शूटिंग शुरू की जाएगी। ज्यादा भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से हम बचेंगे। अभिषेक आगे कहते हैं कि भले ही खुदा हाफिज फिल्म कोरोना काल की वजह से डिजिटल पर रिलीज हुई थी, लेकिन इसके दूसरा पार्ट की शूटिंग हम एक बार फिर थिएटर को ध्यान में ही रखकर कर रहे हैं। रिलीज के समय जैसा माहौल होगा, उसके मुताबिक निर्णय लिया जाएगा।



विद्युत जामवाल होंगे फिल्म में। इंस्टाग्राम

अगस्त से शुरू होगी फिल्म द इम्मोर्टल अश्वत्थामा की शूटिंग

कोरोना काल की वजह से कई फिल्मों की शूटिंग पर असर पड़ा है। खास तौर पर विदेश में शूट होने वाली फिल्मों पर। इनमें फिल्म द इम्मोर्टल अश्वत्थामा भी शामिल है। उरी : द सर्जिकल स्ट्राइक के बाद विक्की कौशल और निर्देशक आदित्य धर की जोड़ी ने फिल्म द इम्मोर्टल अश्वत्थामा बनाने की घोषणा की थी। इस साइंस फिक्शन फिल्म की शूटिंग दोनों इस साल की शुरुआत में करने वाले थे, लेकिन महामारी की वजह से उसे टालना पड़ा। कोरोना की गति मंद पड़ने पर फिल्म की शूटिंग की योजना पर तेजी से काम किया गया। इस महीने से यूरोप में फिल्म में शूटिंग शुरू करने की योजना बनाई गई, लेकिन एक बार फिर शूटिंग में देरी होने की खबर है। खबरों के मुताबिक टीम को अभी तक वीजा नहीं मिला है। इस वजह से अब इसकी शूटिंग अगस्त के मध्य में आरंभ होगी। बताया जा रहा है कि पहले आदित्य लोकेशन के लिए यूरोप की यात्रा पर जाने वाले थे। बाकी टीम के अगस्त में जाने की तैयारी थी। आदित्य ने पिछले महीने ही यामी गौतम के साथ शादी की है।

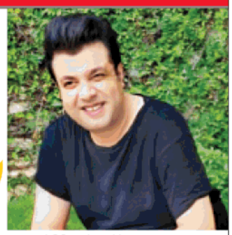


फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं विक्की कौशल। इंस्टाग्राम

खुशकिस्मती है कि मेरे किरदारों के नाम अतरंगी होते हैं : वरुण

सात सवाल

फुकरे, दिलवाले और रूही जैसी फिल्मों के अभिनेता वरुण शर्मा आज से सोनी लिव पर रिलीज हो रही वेब सीरीज चुट्जपाह में नजर आएंगे। अक्सर अपने चुलबुले किरदारों से हंसाने वाले वरुण रोहित शेट्टी निर्देशित फिल्म सर्कस का भी हिस्सा हैं। उनसे हुई बातचीत के अंश :



चुट्जपाह से डिजिटल डेब्यू करेंगे वरुण ● इंस्टाग्राम

● कोरोना की दूसरी लहर के दौरान घर में आपकी पसंदीदा गतिविधियां क्या रहीं?

-आमतौर पर हमारी जिंदगी में इतनी दौड़भाग होती है कि अपने बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। यह समय मेरे लिए भविष्य की योजनाएं बनाने और आगे क्या करना है और क्या नहीं, तय करने के लिए सबसे सही वक्त था। इसके साथ ही मैंने अपनी मां से पेंटिंग सीखी और अच्छा बच्चा बनकर घर के कामों में हाथ बंटाया। इसके अलावा घरवालों के साथ बैठकर एल्बम से तस्वीरें देखते हुए पुरानी यादें ताजा कीं।

● इस शो के ज्यादातर हिस्से वीडियो कालिंग पर आधारित हैं, इससे जुड़े आपके क्या अनुभव रहे?

- इस महामारी से पहले मेरी जिंदगी में वीडियो कालिंग का ज्यादा इस्तेमाल नहीं था। मुझे लोगों से मिलकर बातें करने में ज्यादा मजा आता था, लेकिन महामारी के आने के बाद सबकी तरह मैंने भी अपने दोस्तों, परिवार वालों और काम से संबंधित लोगों से वीडियो काल पर खूब बातें कीं। अब लगता है कि जैसे यह जिंदगी का हिस्सा बन गया हो। एक बार मैं वीडियो काल पर इंटरव्यू कर रहा था, तभी मेरी मां ने मुझे खाना परोस दिया। मेरी थाली में राजमा चावल देखकर मेरा इंटरव्यू कर रहे पत्रकार का भी राजमा चावल खाने का मन कर गया। बाद में उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि इंटरव्यू के बाद उन्होंने भी आनलाइन राजमा चावल मंगवा कर खाया।

● जैसा कि शो में दिखाया गया है, व्यक्तिगत जीवन में घर से दूर रहने पर खाने-पीने के बारे में मम्मी के क्या निर्देश होते हैं?

- हर भारतीय मां की तरह मेरी मां को भी अपने बच्चों के खाने-पीने की बहुत फिक्र रहती है। (हंसते हुए) हम तो पंजाबी लोग हैं, पानी भी पीते हैं, तो अंदर जाकर घी बन जाता है। अगर किसी किरदार के लिए मैं डायट पर भी रहता हूं तो भी वह कहती हैं कोई बात नहीं कम ही घी डाला है, खा लो। सेट पर भी वह अक्सर खाने को लेकर फोन करती रहती हैं। मुझे मम्मी के हाथों से बनाया डोसा, बेसन की पूरियां और आलू की सब्जी बहुत पसंद हैं। मेरे घर में सप्ताह के दो दिन मम्मी के हाथ के ये व्यंजन बनते ही बनते हैं।

● सेक्सा, चूचा, राधा या बूशित, आपके किरदारों के नाम बहुत विचित्र होते हैं। इन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है?

-यह मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे किरदारों के नाम इतने अतरंगी होते हैं। मुझे ऐसे किरदार निभाने में बड़ा मजा आता है। ये सब चीजें निर्देशक ही तय करते हैं, वही इतने अतरंगी नाम ढूंढकर लाते हैं। चुट्जपाह में मुझे अतरंगी नाम की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इस शो का नाम ही बहुत अतरंगी है। इससे पहले मैंने फिल्म हैदर में चुट्जपाह शब्द सुना था। बाद में मुझे पता चला कि यह एक हिब्रू शब्द है, जिसके अलग-अलग अर्थ होते हैं। हमारे लिए इसका अर्थ पागलपन या मजाकिया है।

● डिजिटल प्लेटफार्म पर पदार्पण के बाद अपने लिए इस प्लेटफार्म को कैसे देखते हैं?

-यह अलग-अलग कहानियां प्रदर्शित करने के लिए बहुत ही खूबसूरत प्लेटफार्म है। किसी कहानी को पांच-छह घंटे में विस्तार से बताने के लिए यह बेहतरीन माध्यम है। मैं खुशकिस्मत हूं कि उस समय इस प्लेटफार्म पर आया, जब इसके दर्शकों का बड़ा समूह बन चुका है।

● आपने करियर की शुरुआत मृगदीप सिंह लांबा की फिल्म फुकरे से की थी, अब उन्हीं के साथ डिजिटल पारी भी शुरू कर रहे हैं..

-मैं खुशकिस्मत हूं कि मेरे करियर की शुरुआत मृगदीप सिंह लांबा जैसे निर्देशक और फुकरे जैसी फिल्म के साथ हुई। हमें एक साथ काम करते हुए 10 साल से ज्यादा हो गया है। वह मेरे लिए गाडफादर की तरह हैं। उन्होंने न सिर्फ मुझे पहला मौका दिया, बल्कि फुकरे रिटर्न्स, खानदानी शफाखाना और रूही जैसी फिल्मों से मेरी कला को संवारा भी। इस शो के साथ सिर्फ मैं नहीं, बल्कि बतौर निर्माता मृगदीप सिंह लांबा और दिनेश विजन भी डिजिटल पर अपनी पारी का आगाज कर रहे हैं।

● फिल्म सर्कस की शूटिंग का क्या माहौल रहा?

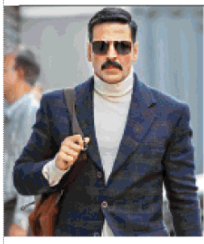
-इस फिल्म और रोहित शेट्टी के निर्देशन में काम करने को लेकर मैं बहुत उत्साहित हूं। इसकी शूटिंग के दौरान पूरी टीम ने बहुत मजे लेकर काम किया। अगर मैं एक शब्द में उस अनुभव को बयां करूं तो करिश्माई अनुभव रहा है। फिल्म के ज्यादातर हिस्सों की शूटिंग हो चुकी है, सिर्फ थोड़ा सा बचा है। जल्द ही हम वह भी पूरी कर लेंगे। (दीपेश पांडेय)

'गुरुओं से मिले ज्ञान का इस्तेमाल कर एक मुकाम तक पहुंचें'



शंकर महादेवन सारेगामापा के अगले सीजन को करेंगे जज। सौ. जी टीवी पीआर टीम

सिंगिंग रियलिटी शो से कई गायकों ने आगे चलकर अपना मुकाम बनाया है। एक बार फिर गायकों की तलाश शुरू हो रही है। जी टीवी अब अपने लंबे समय से चले आ रहे रियलिटी शो सारेगामापा के नए सीजन के साथ लौट आया है। गायक हिमेश रेशमिया और विशाल डडलानी एक बार फिर जज की सीट पर नजर आएंगे। शो के तीसरे जज के तौर पर जुड़ेंगे गायक और संगीतकार शंकर महादेवन, जो आठ साल बाद सारेगामापा में लौटेंगे। दैनिक जागरण से बातचीत में शंकर ने कहा कि सारेगामापा पूरी दुनिया के प्रतिभाशाली गायकों के लिए एक वैश्विक मंच रहा है। यह पहला शो था, जिसमें मैं एक मेंटर बनकर आया था। इस बार भी मैं जज के रूप में वापसी कर रहा हूं, जिसे लेकर मैं बेहद खुश और रोमांचित हूं। म्यूजिक कंपोजर के तौर पर हम हमेशा नई प्रतिभाओं और नई आवाजों की तलाश में रहते हैं जो हमारे गानों और फिल्मों का हिस्सा बनें। मैंने अपने करियर में रियलिटी शोज के 30 गायकों को फिल्मों में गाने में मौका दिया है और वे बेहद सफल भी हुए हैं। इसलिए मेरा मानना है कि एक कंपोजर के लिए नए टैलेंट से मिलना, सबसे बड़ा मौका होता है। मैं खुश हूं कि मुझे एक बार फिर मार्गदर्शन करने का मौका मिलने वाला है। युवा गायकों को मेरी यही सलाह है कि वो अपने गुरुओं से मिले ज्ञान का इस्तेमाल करके गायन में अपना एक मुकाम बनाएं। मुझे एक ऐसे गायक की तलाश है, जो सिर्फ गायक न हो, बल्कि उस गाने में अपना योगदान भी दे।



27 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी अक्षय कुमार अभिनीत बेल बाटम ● इंस्टाग्राम

बेल बाटम फिल्म की रिलीज फिलहाल टली

कोरोना की दूसरी लहर मंद पड़ने के बावजूद फिल्मों की रिलीज के लिए अब भी वक्त मुश्किल बना हुआ है। मुंबई, दिल्ली समेत कई शहरों के सिनेमाघर अब भी खुलने का इंतजार कर रहे हैं। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सिनेमाघर को बंद ही रखा गया है। ऐसे में अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म बेल बाटम की रिलीज की तारीख को अगस्त तक के लिए टाल दिया गया है। यह फिल्म 27 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिलहाल मुंबई और दिल्ली के थिएटर के अगले हफ्ते तक खुलने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। ऐसे में इस फिल्म को बाकी जगहों पर रिलीज करने से निर्माता को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि मुंबई और दिल्ली से फिल्मों की लगभग 90 प्रतिशत कमाई होती है। ऐसे में मिल रही जानकारी के मुताबिक अब बेल बाटम के निर्माता फिल्म को अगस्त में रिलीज करने की योजना बना रहे हैं। गत जून में जब अक्षय कुमार ने बेल बाटम को 27 जुलाई को रिलीज करने की घोषणा की थी, तब से सिनेमा संचालकों और निर्माताओं के बीच एक उत्साह देखा गया था। दैनिक जागरण से बातचीत में डिस्ट्रीब्यूटर समीर दीक्षित ने इस फिल्म को बूस्टर डोज बताया था, साथ ही कहा था कि यह फिल्म निर्माताओं का आत्मविश्वास बढ़ाएगी। फिलहाल माहौल को देखते हुए रिलीज को अगले महीने के लिए टाल दिया गया है।